दैनिक जागरण

इच्छा और आवश्यकता में अंतर ही सुख की कुंजी है

रेल सेवा का विस्तार

देश के व्यस्त रेल मार्गों पर यातायात के दबाव को देखते हुए सात रेल मार्गों को चार लेन का बनाने का फैसला समय की मांग के अनुरूप है। इस फैसले पर अमल से ट्रेनों की क्षमता बढ़ाने और यात्रा को ज्यादा सुगम बनाने में तो सहायता मिलेगी ही, ट्रेनों के लेट होने की समस्या का भी समाधान होगा। चूंकि जिन सात रेल मार्गों को चार लेन का करने का निर्णय लिया गया, वे सभी अति व्यस्त रेल रूट हैं, इसलिए देश के अनेक बड़े शहरों को इसका लाभ मिलेगा। उल्लेखनीय यह भी है कि इससे यातायात के साथ माल ढुलाई भी बेहतर होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने रेल सेवा के आधुनिकीकरण को ध्यान में रखते हुए तीन मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इनके पूरा होने से भारतीय रेलवे के नेटवर्क में करीब 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। समय के साथ जिस तरह आवाजाही तेजी के साथ बढ़ रही है, उसे देखते हुए रेल सेवा के आधुनिकीकरण और उसके विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह सही है कि सड़क यातायात अपेक्षाकृत सुगम होने के साथ हवाई सेवाएं भी नए-नए शहरों में पहुंच रही हैं, लेकिन भारत सरीखे बड़े और विशाल आबादी वाले देश में रेल सेवा का कोई विकल्प नहीं।

आज भी बड़ी संख्या में लोग रेल से यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता में कमी के कारण कुछ लोगों को मजबूरी में सड़क या हवाई सेवा का चयन करना पड़ता है। त्योहारों और अन्य विशेष अवसरों पर ट्रेनों में सीटें मिलना अभी भी कठिन बना हुआ है। एक समस्या उनकी लेट-लतीफी भी है। इसका कारण पर्याप्त रेल मार्ग न होना है। देश के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं, जो अभी रेल सेवा से नहीं जुड़ सके हैं। कुछ बड़ी आबादी वाले क्षेत्र ऐसे हैं, जहां तक जाने के लिए ट्रेन कठिनाई से उपलब्ध होती है। इसे देखते हुए रेल सेवा का विस्तार कहीं अधिक तेजी से होना चाहिए। इसके पहले रेल मंत्री ने यह जानकारी दी थी कि स्वदेशी बुलेट ट्रेन का परीक्षण अगले वर्ष मई-जून में होगा और यदि सब कुछ सही रहा तो दिसंबर में उसका संचालन शुरू हो जाएगा। यह एक उपलब्धि तो होगी, लेकिन यह ध्यान रहे कि बुलेट ट्रेन परियोजना को साकार करने में देर हुई है। जापान, चीन और यूरोपीय देश न जाने कब से प्रमुख मार्गों पर बुलेट ट्रेन चला रहे हैं। इसी तरह एक सच्चाई यह भी है कि इन देशों में सामान्य ट्रेनों की औसत गति भारत के मुकाबले कहीं अधिक है। यह ठीक है कि पिछले कुछ वर्षों में चुनिंदा ट्रेनों की रफ्तार बढ़ी है, लेकिन अभी कुल मिलाकर उनकी गति सीमा दो सौ किमी प्रति घंटे के अंदर ही है और कुछ ट्रेनों को तो सुरक्षा कारणों से तय गति से कम रफ्तार में ही चलाने की मजबूरी है।

राहत के इंतजाम

बिहार के 13 बाढ़ प्रभावित जिलों में प्रभावित लोगों के लिए राहत के इंतजाम किए गए हैं। सामुदायिक किचन में पीड़ित परिवारों को भोजन दिया जा रहा है, उनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद एक टीस हर परिवार को सालती है कि आखिर इस पीड़ा से उन्हें कब स्थायी समाधान मिलेगा। हर साल बाढ़ और पलायन से उन्हें कब छुटकारा मिलेगा। यह सही है कि सरकार मुस्तैदी से राहत शिविरों में लोगों को हर संभव मदद दे रही, लेकिन घर-बार छोड़कर यूं शिविरों में सरकारी कृपा पर जिंदगी गुजारना भला किसे सुहाता है। पूरी तरह से समस्या का समाधान राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती। केंद्र और नेपाल सरकार के साथ रोडमैप बनाकर ही बाढ़ का स्थायी समाधान किया जा सकता है, लेकिन कई जगहों पर हल अपने ही हाथ है। तत्परता दिखाकर और सही निगरानी से बड़ी आबादी को भयमुक्त माहौल दिया जा सकता है। भागलपुर राघोपुर तटबंध टूटने के बाद जिस तरह से सक्रियता दिखाई गई। बचे हिस्से को बचाने के लिए दिन-रात युद्धस्तर पर कार्य किया गया। सचिव, मंत्री कैंप किए रहे। मुख्यमंत्री भी खुद मौके पर पहुंचे। अगर तटबंध की कमजोरी का आकलन बरसात से पहले हो जाता तो शायद ऐसी विषम स्थिति नहीं आती। अकबरपुर-सुल्तानगंज एनएच 80 पर बाढ़ का पानी चढ़ आया है। आवागमन बंद है। अभी कुछ महीनों पूर्व ही इस सड़क का चौड़ीकरण कार्य हुआ है, काफी पैसे खर्च कर इसकी ऊंचाई भी बढ़ाई गई है। सवाल उठता है कि प्रायः हर बाढ़ में डूब जाने वाली इस सड़क के निर्माण से पूर्व विभाग ने ठीक से आकलन क्यों नहीं किया।

> तत्परता और सही निगरानी से कई परिस्थितियां नियंत्रित की जा सकती हैं

नई पीढ़ी को सक्षम बनाने की चुनौती

जीएन वाजपेयी

शासन-प्रशासन में अनुभव और संयम का महत्व तो सदैव रहेगा, मगर भारत के भविष्य को गढ़ने में भावी पीढ़ी की भूमिका तय होनी ही चाहिए

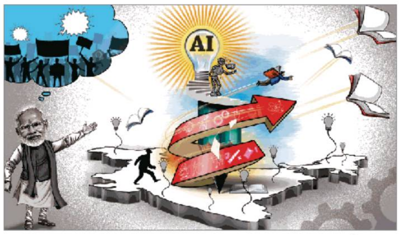

अवधेश राजपूत

नई दिल्ली में जंतर-मंतर पर युवा आंदोलनकारियों के धरना-प्रदर्शन और शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र के बाद से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उनकी सरकार ने जेन-जी को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक कई निर्णय लिए हैं। अगर इन फैसलों पर सही से अमल हो सका तो इस पीढ़ी की तमाम चिंताएं दूर हो सकती हैं। इस दिशा में तत्परता से काम भी शुरू हो चुका है। इसी के साथ इस विरोध-प्रदर्शन में निहित संदेश को समझने के लिए यह पड़ताल करना भी उतना ही आवश्यक है कि किसी प्रायोजक या सुनियोजित एवं संगठित समर्थन के बिना इतनी भारी भीड़ आखिर 'स्वतः स्फूर्त' ढंग से क्यों उमड़ पड़ी? जेन-जी न केवल देश की एक बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि यह पीढ़ी देश की नई आकांक्षाओं का प्रतीक भी है। जेन-जी का बचपन और जवानी इंटरनेट, स्मार्टफोन और इंटरनेट मीडिया के साए में गुजरी है। इनके लिए आभासी और वास्तविक दुनिया के बीच की दीवार बनावटी और बेमानी है। सूचनाओं तक तात्कालिक पहुंच के बल पर यह पीढ़ी दुनिया भर में संबंध जोड़ सकती है, ज्ञान हासिल कर सकती है, स्टार्टअप शुरू कर सकती है और मुख्यधारा के मीडिया या पारंपरिक तंत्र के बिना भी अपनी बात को राष्ट्रीय-वैश्विक मंच पर रख सकती है। जंतर-मंतर का वह जमावड़ा इसी ताकत का प्रत्यक्ष प्रमाण रहा। इन पहलुओं ने एक ऐसी पीढ़ी को आकार दिया है, जो व्यक्तिगत पहचान, प्रामाणिकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और समावेशिता को सर्वोपरि मानती है।

जेन-जी पीढ़ी किसी सत्ता या व्यवस्था को महज इसलिए स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वह पारंपरिक रूप से चली आ रही है। वह सीधे सवाल करती है कि पुरानी व्यवस्थाएं बदस्तूर क्यों बनी रहें, क्या स्थापित संस्थाएं उनकी आवाज सुन भी रही हैं और क्या मौजूदा तंत्र उन्हें न्यायसंगत एवं समान अवसर उपलब्ध करा पा रहा है? इनकी आकांक्षाएं पिछली पीढ़ियों की तुलना में बुनियादी रूप से भिन्न हैं, जिनके लिए एक सुरक्षित और स्थिर करियर ही जीवन का वास्तविक एवं अंतिम ध्येय हुआ करता था।

पुरानी पीढ़ी की तुलना में वे कोई अर्थपूर्ण अथवा रुचि का काम चाहते हैं। ऐसा काम, जिसमें न केवल आर्थिक आजादी, बल्कि अपनी शर्तों पर काम की सहूलियत के साथ ही कुछ नया रचने की छूट और आत्मविकास की गुंजाइश हो। स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग, डिजिटल प्लेटफार्म, कंटेंट क्रिएशन और आधुनिक तकनीकी पेशों ने रोजगार को लेकर उनके सोच के क्षितिज को और व्यापक स्वरूप प्रदान किया है। हालांकि इस सिक्के का दूसरा पहलू उतना ही स्याह है और वह यह कि उत्कृष्ट शिक्षा और ढंग की नौकरियों के लिए आज भी इन्हें बेहद कड़े संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। शैक्षिक डिग्रियों और आर्थिक अवसरों के बीच बढ़ता अंतर युवाओं में भारी हताशा पैदा कर सकता है। जेन-जी युवा संभवतः सरकारी नौकरियों के अभाव को स्वीकार कर भी ले, किंतु वह पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, योग्यता-आधारित चयन, भरोसेमंद बुनियादी ढांचा और ऐसे संस्थान अवश्य चाहता है, जो नागरिकों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करें। वस्तुतः, उनकी सबसे मूल आकांक्षा आत्मसम्मान और गरिमा से जुड़ी है।

यदि पुरानी पीढ़ी ने इंटरनेट के नए सबक सीखे तो जेन-जी एआइ के दौर में पलने वाली पहली पीढ़ी है। एआइ इनके पठन-पाठन, सृजन, संवाद और सवालों के हल का सबसे बड़ा जरिया बनेगी। एक ऐसे डिजिटल मार्गदर्शक के बूते यह पीढ़ी नई भाषाएं और कला-कौशल सीखेगी। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर एक-दूसरे के साथ सहजता से मिलकर काम कर सकेगी। संभावनाओं के इस अपार संसार में उन पर एक भारी नैतिक दायित्व भी होगा। स्पष्ट है कि भविष्य में मशीनी दक्षता से कहीं ज्यादा अहमियत मानवीय फैसलों, संवेदना, सृजनशीलता, नैतिक मूल्यों, नेतृत्व-कौशल और सच तथा गढ़े गए झूठ के बारीक फर्क को पकड़ने वाली क्षमताओं की होगी।

भारत की युवा आबादी देश की ताकत तभी बन सकती है, जब इस पीढ़ी को हुनर, रोजगार, आत्मसम्मान, अपनी बात कहने का मंच और एक बेहतर भविष्य का भरोसा मिले। इसके लिए शिक्षा को रटने की परिपाटी से मुक्त कर रचनात्मक विवेक, प्रयोगधर्मिता और समस्याओं के व्यावहारिक समाधान की ओर मोड़ना होगा। साथ ही, तकनीकी एवं व्यावसायिक पठन-पाठन का उद्योगों से सीधा तालमेल बैठाना, युवाओं को बाजार की मांग के अनुरूप तैयार करना और स्टार्टअप एवं नए अनुसंधानों के दरवाजे हर तबके के लिए खोलना अपरिहार्य होगा। भारत को एआइ से लैस ऐसे कुशल कार्यबल को तैयार करना होगा जो मशीनों से महज प्रतिस्पर्धा के बजाय उनके साथ मिलकर उत्पादकता और सृजनशीलता से काम करने की सामर्थ्य विकसित कर सके। इसके साथ ही, युवाओं में मानसिक दृढ़ता, शारीरिक तंदुरुस्ती, खेलकूद, सांस्कृतिक अभिरुचि और जीवंत एवं गतिशील सामुदायिक जीवन को बढ़ावा देने पर भी पहले से कहीं अधिक बल देना होगा। सबसे अहम बात यह है कि सरकार को इन युवाओं की आवाज को संवेदनशीलता से सुनना होगा और समयानुकूल समुचित कदम उठाने होंगे। डिजिटल कनेक्टिविटी के इस दौर में सुस्त और अपारदर्शी लालफीताशाही वाली प्रक्रियाओं के प्रति इस पीढ़ी का असंतोष एवं असहिष्णुता का भाव और तीखा होता जाएगा।

भले ही पीएम मोदी ने सांसदों-विधायकों को नई पीढ़ी से जुड़ने की एक कवायद सौंप दी हो, लेकिन महज बातों पर सुनवाई उनके मनोभावों और आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। समय आ गया है कि संसद और विधानसभाओं में नौजवानों को अपनी बात रखने की असली जगह मिलनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि पुराने नेतृत्व को एकाएक दरकिनार कर दिया जाए। शासन-प्रशासन में अनुभव, समझ और संयम का महत्व तो सदैव रहेगा, मगर भारत के भविष्य को गढ़ने में भावी पीढ़ी की भूमिका तय होनी ही चाहिए।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)
response@jagran.com

ब्रिक्स को नए आयाम देता भारत

अजय मल्होत्रा

ब्रिक्स की अध्यक्षता में भारत का मूल मंत्र सक्षमता, नवाचार, परस्पर तालमेल और टिकाऊ भविष्य पर केंद्रित हैं

नई दिल्ली में 12 से 13 सितंबर के बीच ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। इस साल अपनी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ मना रहे इस संगठन की यह शिखर बैठक उस कसौटी को निर्धारित करेगी कि तमाम भिन्नताओं के बावजूद यह मंच सदस्य देशों के बीच जमीनी सहयोग और व्यावहारिक समन्वय का माध्यम बन पाया है या नहीं? न्यूयार्क में 20 सितंबर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र की बैठकों के बीच स्थापना के दौरान भले ही इसे लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, लेकिन एक नई शुरुआत का रोमांच साफ महसूस हो रहा था। तब से लेकर अब तक इस संगठन का निरंतर विस्तारित हो रहा दायरा वास्तव में चकित करने वाला है। विश्व की लगभग आधी-आबादी और जीडीपी में करीब 40 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ ब्रिक्स एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन बन चुका है। हालांकि, इसके सदस्य देशों के बीच न तो कोई साझा भू-राजनीतिक एजेंडा है और न ही मौद्रिक या सुरक्षा से जुड़ा कोई एकीकृत दृष्टिकोण। यहां भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता के बीच उनका सहयोग भी जारी है। जबकि ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी अपनी गहरी क्षेत्रीय रंजिशों के बावजूद ब्रिक्स के मंच पर साथ आते हैं। यह आंतरिक विविधता ब्रिक्स को किसी अड़ियल संगठन बनने से रोकने के साथ ही उसे एक लचीले मंच के रूप में और अधिक मजबूती भी प्रदान करती है।

ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत ने देश के 30 शहरों में 35 अलग-अलग मुद्दों पर 350 से अधिक बैठकें आयोजित कीं। इस क्रम में 'संपूर्ण भारत' के साझा संकल्प की झलक दिखाई दी, जिसमें केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें, उद्योग, शोध संस्थान और समाज का हर वर्ग साथ खड़ा दिखा। इनमें कागजी घोषणाओं पर जोर के बजाय ठोस नतीजों को प्राथमिकता दी गई। बैठकों का यह व्यापक दायरा यही दर्शाता है कि भारत ने नए सदस्यों से लैस ब्रिक्स को कहीं अधिक एकजुट, कार्यकुशल और असरदार बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारत की अध्यक्षता का मूल मंत्र सक्षमता, नवाचार, परस्पर तालमेल और टिकाऊ भविष्य पर केंद्रित है। यह प्रधानमंत्री मोदी के 'मानवता सर्वोपरि' वाले जन-केंद्रित सोच का ही प्रतिबिंब है। इस दौरान भारत ने लाजिस्टिक्स नेटवर्क, बैट्री एवं ऊर्जा स्टोरेज, नए उद्यमों के लिए पूंजी, छोटे उद्योगों की वैश्विक पहुंच, आसान कस्टम प्रक्रिया और जलवायु संकट से निपटने के उपायों पर कार्य को आगे बढ़ाया है। साथ ही, आयुष एवं पारंपरिक चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य को ब्रिक्स के विमर्श में शामिल कर भारत ने इस मंच को पारंपरिक आर्थिक सहयोग के एजेंडे से इतर नया आयाम प्रदान किया है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान स्वाभाविक रूप से सबका ध्यान डालर से इतर विकल्पों पर जाएगा। वैसे, यह चर्चा किसी मुद्रा के वर्चस्व को समाप्त या सीमित करने से अधिक उस पर निर्भरता घटाने की अधिक है।

नई विश्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण हुआ ब्रिक्स। फाइल

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आइएमएफ के अनुसार विश्व के विदेशी मुद्रा भंडार में डालर का हिस्सा 1999 के 72 प्रतिशत से घटकर 2026 की शुरुआत में 57.1 प्रतिशत रह गया है। इसके बावजूद डालर के रुतबे पर संदेह नहीं, क्योंकि उसकी जैसी साख, बाजार विस्तार और बेहिसाब नकदी किसी और मुद्रा के पास नहीं है। चीनी युआन पर अब भी बंदिशें हैं और ब्रिक्स की साझा मुद्रा बनाने के लिए जिस आर्थिक सहमति और संप्रभुता के समझौते की जरूरत है, उसके लिए कोई देश तैयार नहीं। इसलिए व्यावहारिक रास्ता यही निकाला जा रहा है कि चुनिंदा द्विपक्षीय व्यापार में अपनी-अपनी मुद्राओं का उपयोग हो, डिजिटल पेमेंट सिस्टम आपस में जुड़ें और स्थानीय स्तर पर कर्ज एवं वित्तीय संसाधन जुटाए जाएं। टैरिफ के जरिये व्यापारिक प्रतिबंधों के विरोध में भी ब्रिक्स देश एकमत हैं।

ब्रिक्स से जुड़ी आकांक्षाओं की पूर्ति की एक परीक्षा न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की व्यावहारिकता को लेकर भी होनी है। 2015 से अब तक इसने केवल भारत के लिए ही इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु करीब 10 अरब डालर मंजूर तो किए हैं, लेकिन अपनी गतिशीलता, वित्तीय आकार और पहुंच के लिहाज से यह आज भी विश्व बैंक या एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी से कोसों पीछे है। इस मंच पर भारत की छाप इससे तय होगी कि वह बैंक के कर्ज देने के तौर-तरीकों, परियोजनाओं की तैयारी और अपनी मुद्राओं में फंडिंग को बढ़ावा देने वाले सुधारों को कितनी मजबूती से लागू करा पाता है।

भारत की अध्यक्षता ब्रिक्स को संप्रभु राष्ट्रों के एक स्वतंत्र मंच के रूप में अक्षुण्ण रखते हुए व्यावहारिक सहयोग के एक अधिक प्रभावी माध्यम के तौर पर स्थापित करने की दिशा में अग्रसर है। कुल मिलाकर, नई दिल्ली शिखर सम्मेलन की सफलता का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि इसने धरातल पर क्या परिणाम दिए। इस समूह की परिपक्वता की वास्तविक परीक्षा उन पहलुओं पर भी निर्भर करेगी कि भारत द्वारा आरंभ की गईं पहल अगले वर्ष चीन को अध्यक्षता सौंपे जाने के बाद भी निरंतर रहते हुए स्थायी संस्थागत ढांचे का रूप ले पाती हैं या नहीं?

(रूस में भारत के राजदूत रहे लेखक टेरी में फेलो हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

गतिशीलता

चलना केवल पैरों की गति नहीं, चेतना की उस अविराम धारा का प्रतीक है, जो मनुष्य को जड़ता से मुक्त रखता है। जब मनुष्य एक कदम आगे बढ़ाता है, तब वह मात्र दूरी तय नहीं करता, वरन उद्घोषणा करता है कि उसके भीतर अभी भी संभावनाएं विद्यमान हैं। गति में ही जीवन की सार्थकता निहित है, क्योंकि जो रुक जाता है, वह समय के प्रवाह से पीछे छूट जाता है। गतिशीलता और उसके साथ किए गए प्रयास ही विजय का मार्ग प्रशस्त करते है। मानवीय संबंधों में भी यही सत्य लागू होता है। जब हम किसी मनमुटाव के पश्चात क्षमा और संवाद की ओर कदम बढ़ाते हैं, तब हम यह स्वीकार करते हैं कि परिवर्तन अभी संभव है और संबंध अभी सजीव है।

ठहराव और विश्राम में मौलिक भेद है। शरीर के लिए विश्राम आवश्यक है। वह पुनः शक्ति संचय के लिए अनिवार्य है, परंतु जब यह विश्राम आत्मा में प्रविष्ट होकर स्थायी जड़ता का रूप धारण कर लेता है, तब अनुत्पादक एवं आत्मघाती बन जाता है। जड़ता मनुष्य की जिज्ञासा को कुंद करती है। उसके स्वप्नों को धूमिल करती है और आत्मतुष्टि के मिथ्या आवरण में बांध देती है। सबसे भयावह पराजय ठहराव ही है। वह क्षण जब मनुष्य यह मान लेता है कि अब आगे कुछ शेष नहीं, तब गतिशीलता पर विराम लग जाता है और यही विराम प्रगति में अवरोध बनता है।

स्मरण रहे कि नदी जब तक बहती है, तभी तक निर्मल रहती है। रुक जाने पर वह दलदल बन जाती है। मनुष्य का जीवन भी इसी नियम से बंधा है। चाहे प्रगति की गति मंद हो, चाहे मार्ग में अनेक बाधाएं हों, किंतु गतिशीलता ही अस्तित्व की सार्थक अभिव्यक्ति है। जीवन में रुकने से कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक ठहराव धीरे-धीरे अवनति का कारण बनता है।

ममता कुशवाहा

बनें अपनेआप का संबल

डा. मोनिका शर्मा

> **आज के दौर में समय रहते मन को मायूस करने वाली बातों-हालात के प्रति सजगता बरतना आवश्यक हैं**

वर्तमान में आत्महत्या एक चिंतनीय एवं वैश्विक समस्या है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे इसी वैश्विक चिंता को संबोधित करता है। यह दिन जीवन बचाने का एक साझा संदेश देने वाला, जीवन से हारने की घटनाओं से जुड़े हर पहलू को समय रहते समझने की बात लिए है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे की थीम 'चेंजिंग द नैरेटिव आन सुसाइड' है, जिसका अर्थ है कि लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए न केवल आत्महत्या से जुड़े सोच को समझना, बल्कि इन घटनाओं के प्रति समाज-परिवार में मौजूद विचारों पर ध्यान देना भी आवश्यक है। वस्तुतः जीवन सहेजने से जुड़े बहुत से प्रयास समाज, परिवार, विभिन्न संस्थाओं और सरकारी अभियानों के तहत हो रहे हैं, पर यह विषय मानवीय दृष्टिकोण बदलने की बात लिए है। ऐसे में भावनात्मक रूप से मजबूत बनने का दायित्व स्वयं के हिस्से भी आता है। आज के दौर में खुद अपने आप को बचाने के मोर्चे पर भी प्रयास करना भी जरूरी है।

इसमें कोई शक नहीं कि साझी कोशिशें बेहद कारगर होती हैं, पर स्वयं को संभालने की ओर कदम बढ़ाने पर ही दूसरों के प्रयास काम आ पाते हैं। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में अपने जज्बातों को थामने की जिम्मेदारी उठाने का मनोबल रखना सबल मानवीय दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसीलिए हर आयु और लिंग के भेद से परे हर देशवासी अपने जीवन का मोल समझे। स्वयं अपनी सार्थकता को समझकर मन को बिखेरने वाली परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है। अपनेआप को दोषारोपण के घेरे में आने बचाना जरूरी है। अंतर्मन में छुपी शक्ति को जुटाकर हर विपरीत परिस्थिति से जूझा जा सकता है।

किसी भी हाल में जिंदगी से मुंह मोड़ लेने का कदम सही नहीं होता। आभासी होते संसार में अपनी अहमियत समझते हुए मन को चोट पहुंचाने वाली परिस्थितियों में अपना संबल बनें। यह भावनात्मक रूप से मजबूत बनने की पहली सीढ़ी है। पीड़ादायी परिस्थितियों में दूसरे भी यही कहते हैं कि 'हिम्मत से काम लो' या 'सब ठीक हो जाएगा, खुद को संभालो।' यानी जिंदगी का मोल पहले आप खुद समझिए। अपने हों या पराए, दूसरों की समझाइश, कोशिश या सलाह तभी काम आ सकती है जब अपने मन को मजबूत करने की ठान ली जाए। समझना आवश्यक है कि इंसानी मन की संवेदनाओं-भावनाओं का प्रबंधन कोई और नहीं कर सकता। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे किसी के थके मन के प्रति संवेदनशील होने का संदेश लिए है। इसीलिए सबसे पहले अपने मन के मोर्चे पर सजग होइए। अपने प्रति संवेदनशील बनिए। हर जद्दोजहद का हल तलाशकर अपने जज्बातों को संभालने के मायने समझिए। धैर्य के साथ जीवन को गले लगाने वालों के संघर्ष से प्रेरणा लीजिए।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणाकार हैं)

न्याय के दोहरे मापदंड

'अराजकता करने वालों को विशेष छूट' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान के दृष्टिकोण पर विमर्श की जरूरत है। इस संदर्भ में उनके द्वारा उठाया गया यह प्रश्न प्रासंगिक है कि 'क्या कोई इस बात की गारंटी लेने को तैयार है कि सीजेपी के संसद मार्च में हिंसा केवल आपराधिक अतीत वालों ने ही की?' कदाचित ऐसी गारंटी न तो सरकार ले सकती है और न ही कोई न्यायिक संस्था। फिर हिंसा फैलाने वाले उन कथित छात्रों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गई एफआइआर को बिना जांच के वापस लेने के पीछे न्याय की कौन सी अवधारणा थी? सीजेपी के संसद मार्च में हुई हिंसा में हिंसक भीड़ में क्या किसी कथित छात्र ने पुलिस पर पत्थर नहीं फेंका होगा? फिर किसी उपद्रवी छात्र को बिना जांच के दोषमुक्त कैसे मान लिया गया? ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जिनका समाधान होना न्याय का तकाजा था। बेशक पहली बार अपराध करने वाला कोई छात्र नरमी का हकदार हो सकता है, लेकिन उसे अपराधबोध कराए बिना ही न्यायिक प्रक्रिया से मुक्त कर देना, न्याय का दोहरा मापदंड है। ऐसे में दूसरा ज्वलंत प्रश्न यह भी उठता है कि सीजेपी संसद मार्च के समय जो पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी करते हुए उपद्रवियों की हिंसा से घायल होकर मरणासन्न हो गए, उनको न्याय कैसे मिलेगा? क्योंकि उन्हें बुरी तरह पीटकर और पत्थर मारकर घायल करने वाले वह कथित छात्र भी रहे होंगे, जिन्हें पूर्ण न्याय की अवधारणा के तहत दोषी नहीं माना गया और उनके विरुद्ध सभी एफआइआर सरकार के आग्रह पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बिना किसी जांच के इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी गईं कि इसमें केवल आपराधिक अतीत वालों के विरुद्ध नए सिरे से एफआइआर दर्ज की जाएं। क्या न्याय का यह दोहरा मापदंड भविष्य में नए आंदोलनजीवियों के लिए बेधड़क हिंसा करने की जमीन तैयार नहीं करेगा?

डा.वीपी पाण्डेय, अलीगढ़ (उप्र)

मेलबाक्स

वाहन चालक की भी जिम्मेदारी

सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की हर टोल प्लाजा पर एक एंबुलेंस तैनात करने की योजना को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को भी पूर्ण सहयोग देने की आवश्यकता है। आज देश के राजमार्गों पर दुर्घटनाओं का ग्राफ जिस गति से बढ़ रहा है, उसे देखते हुए यह योजना अत्यंत प्रासंगिक और समय की मांग बन गई है। राजमार्गों पर होने वाले हादसों के पीछे कई प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण सड़कों की बदहाली और बीच-बीच में टूटे हुए हिस्से हैं। जब वाहन अत्यधिक तेज रफ्तार में होते हैं, तो चालकों के लिए अचानक सामने आए गड्ढों या टूटी सड़कों को देख पाना और वाहन को नियंत्रित करना बेहद कठिन हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप भयावह हादसे होते हैं। इसके अलावा, कई स्थानों पर सड़कों की त्रुटिपूर्ण डिजाइन और असंतुलित मोड़ भी दुर्घटनाओं की मुख्य वजह बनते हैं। ऐसी आपातकालीन स्थितियों में घायलों की जान बचाने के लिए समय पर इलाज मिलना सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि हर टोल प्लाजा पर 24 घंटे एक सुसज्जित एंबुलेंस उपलब्ध रहें तो पीड़ितों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जा सकती है। केवल एंबुलेंस की तैनाती ही काफी नहीं है, बल्कि राजमार्गों के आसपास पर्याप्त ट्रामा सेंटरों का निर्माण भी जरूरी है, ताकि घायलों को 'गोल्डन आवर' में ही उचित चिकित्सा मिल सके। साथ ही, इन एंबुलेंस की कार्यप्रणाली और उनकी वास्तविक उपयोगिता पर नजर रखने के लिए एक पारदर्शी और सख्त निगरानी तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। सरकारी स्तर पर उठाए जाने वाले कदमों के साथ-साथ वाहन चालकों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। गति सीमा का पालन करना, लेन अनुशासन बनाए रखना, नशे में गाड़ी न चलाना और सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। सरकार का ढांचागत सहयोग और चालकों का संयमित व्यवहार मिलकर ही हमारी यात्रा को सुगम, सुरक्षित और दुर्घटनामुक्त बना सकते हैं। सड़क दुर्घटनाएं न सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था पर, बल्कि आम परिवारों पर बोझ डालती हैं।

पैंथर तोमर, किशन गंज (दिल्ली)

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com. R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

28 लोगों की मौत हो चुकी है मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब से। 110 से अधिक लोग अब भी अलग-अलग अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं।

शिशिर शुक्ला
शिक्षक, स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर

आजकल

समय की विसंगति दूर करता भारत

एक देश, एक समय को केवल घड़ियों की सुइयों को मिलाने की कवायद समझना ठीक नहीं होगा। यह डिजिटल भारत की वह जरूरत है, जिसमें समय अब केवल दिन और रात का हिसाब रखने का माध्यम नहीं, बल्कि वित्तीय लेन-देन, संचार, ऊर्जा, परिवहन और राष्ट्रीय सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का आधार बन चुका है। समय की एकरूपता जितनी अधिक होगी, इन प्रणालियों के बीच तालमेल और विश्वसनीयता भी उतनी ही मजबूत होगी। असल में यह पहल भारत के डिजिटल भविष्य को एक समय पर लाने की कोशिश है

प्रतीकात्मक

समय किसी भी राष्ट्र की कार्य संस्कृति, प्रगति और वैज्ञानिक चेतना का मूल आधार होता है। भारत अब इस महत्वपूर्ण आधार को लेकर एक महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत लीगल मेट्रोलाजी नियम, 2026 यानी भारतीय मानक समय (आइएसटी) को देशभर में कानूनी, प्रशासनिक, व्यावसायिक और आधिकारिक गतिविधियों के लिए एकमात्र मानक समय-संदर्भ बनाया जाएगा। नियम 180 दिन बाद प्रभावी होंगे अर्थात मार्च 2027 के आसपास व्यवस्था की यह एकरूपता लागू हो जाएगी। प्रथमदृष्ट्या तो यह फैसला केवल देश भर की घड़ियों को मिलाने का निर्णय लगता है, लेकिन यदि गंभीरता से मंथन किया जाए तो इसके पीछे बदलती अर्थव्यवस्था और विकास की राह पर दौड़ते भारत की एक बड़ी आवश्यकता छिपी है। प्रौद्योगिकी पर दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई निर्भरता के मध्य उठाया गया यह कदम बहुआयामी रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। आज सरकारी कार्यालय से लेकर बैंकिंग, शेयर बाजार, दूरसंचार, रेलवे, बिजली व्यवस्था, डिजिटल भुगतान और आनलाइन सेवाओं तक लगभग हर क्षेत्र समय की सटीकता पर निर्भर है। ऐसे में अलग-अलग प्रणालियों में समय के मामूली अंतर का प्रभाव भी कभी-कभी बड़ा हो सकता है। शासन द्वारा बनाई जा रही नई व्यवस्था का उद्देश्य इस विसंगति को समाप्त करते हुए पूरे देश के लिए एक समान आधिकारिक समय-संदर्भ सुनिश्चित करना है।

भारत भौगोलिक रूप से विस्तृत देश है। नतीजतन पूर्वी और पश्चिमी छोर के स्थानीय सौर समय में स्वाभाविक रूप से अंतर होता है। एक डिग्री देशांतर पर चार मिनट का अंतर भारत के पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर के बीच समय का एक अच्छा खासा फासला उत्पन्न कर देता है। सूर्य देश के पूर्वी हिस्से में पहले दिखाई देता है और पश्चिम में बाद में, लेकिन प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय समन्वय के लिए भारत लंबे समय से एक ही मानक समय का उपयोग करता आया है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को आधार मानता है और समन्वित सार्वभौमिक समय से पांच घंटे तीस मिनट आगे है। अब इसे कानूनी रूप से और अधिक स्पष्ट तथा बाध्यकारी आधार दिया जा रहा है। इस निर्णय का सर्वप्रमुख लाभ प्रशासनिक एकरूपता होगा। देश के किसी भी हिस्से में जारी आदेश, निविदा, अनुबंध, परीक्षा, भुगतान, कार्यालयी समय या डिजिटल रिकार्ड के लिए समय का एक ही आधिकारिक संदर्भ होगा। इससे समय को लेकर उत्पन्न होने वाली व्यावहारिक अस्पष्टताओं में कमी आएगी। विशेषकर ऐसे मामलों में जहां किसी कार्रवाई की वैधता मिनट या सेकंड तक निर्धारित होती है, एक प्रमाणित राष्ट्रीय समय-संदर्भ नितांत उपयोगी साबित होगा।

डिजिटल अर्थव्यवस्था में इस नई व्यवस्था का महत्व और बढ़ जाता है। आज करोड़ों लेन-देन ऐसे डिजिटल तंत्रों पर निर्भर हैं जिनमें प्रत्येक गतिविधि का समय दर्ज होता है। बैंकिंग, आनलाइन भुगतान, स्टाक एक्सचेंज, दूरसंचार नेटवर्क और क्लाउड आधारित सेवाओं में अलग-अलग प्रणालियों के बीच सूक्ष्म समय-अंतर भी तकनीकी समस्या पैदा कर सकता है। सरकार की नई पहल में भारतीय समय को अत्यधिक सटीकता से उपलब्ध कराने और तकनीकी प्रणालियों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करने पर जोर दिया गया है। इसके लिए अत्याधुनिक व्हाइट रैबिट तकनीक का परीक्षण किया गया है, जो अत्यंत सूक्ष्म स्तर पर नेटवर्क घड़ियों के समन्वय में सक्षम है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी सटीक समय का महत्व कम नहीं है। आधुनिक रक्षा प्रणालियों, संचार नेटवर्क, उपग्रह आधारित सेवाओं और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं में समय-सामंजस्य अनिवार्य है। यदि विभिन्न प्रणालियां एक ही प्रमाणित समय-स्रोत से जुड़ी हों तो समन्वय और विश्वसनीयता बेहतर हो सकती है। भारत अपने समय-संदर्भ के लिए स्वदेशी और विश्वसनीय व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, इसलिए यह पहल तकनीकी आत्मनिर्भरता के व्यापक लक्ष्य से भी जुड़ती दिखाई देती है।

हालांकि इस निर्णय के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। सबसे पहली चुनौती है तकनीकी संक्रमण। सरकारी विभागों, निजी कंपनियों, डिजिटल प्लेटफार्म, औद्योगिक इकाइयों और अन्य संस्थानों को अपने समय-संबंधी साफ्टवेयर और हार्डवेयर को आधिकारिक आइएसटी से सिंक्रोनाइज करना होगा। पुराने सिस्टमों में बदलाव, नेटवर्क की विश्वसनीयता और छोटे संस्थानों के लिए अनुपालन की लागत व्यावहारिक प्रश्न बन सकते हैं। 180 दिनों की संक्रमण अवधि इसी तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होगी। दूसरी चुनौती जागरूकता की है। आम नागरिक को शायद ही कोई कठिनाई हो, क्योंकि उसके मोबाइल और कंप्यूटर पहले से ही समय स्वतः अपडेट कर लेते हैं। वास्तविक चुनौती उन संस्थानों में होगी जहां समय दर्ज करने, प्रमाणित करने और साझा करने की अपनी पुरानी प्रणालियां हैं। सरकार को केवल नियम बनाकर नहीं रुकना चाहिए, बल्कि स्पष्ट तकनीकी दिशानिर्देश, प्रशिक्षण और सहायता तंत्र भी उपलब्ध कराना चाहिए। तीसरा एवं अहम प्रश्न भारत की भौगोलिक विविधता का है। पूर्वोत्तर राज्यों में सूर्योदय अपेक्षाकृत जल्दी होता है, जबकि पश्चिमी भारत में सूर्य देर से अस्त होता है। एक ही मानक समय प्रशासनिक दृष्टि से सुविधाजनक है, लेकिन स्थानीय जीवनचर्या पर इसका प्रभाव अलग-अलग क्षेत्रों में अलग हो सकता है। 'एक समय' का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि देश के हर हिस्से की कार्य-संस्कृति भी बिल्कुल एक जैसी कर दी जाए। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यालयों, विद्यालयों और उद्योगों के कार्य-समय में लचीलापन बनाए रखना समझदारी होगी।

घड़ी का एक होना तभी सार्थक है जब उसके साथ व्यवस्था की गति भी एकरूप हो। देश की घड़ियों को मिलाना आसान है, लेकिन संस्थानों की कार्यप्रणाली, डिजिटल प्रणालियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एक मानक पर लाना अधिक कठिन काम है। इसलिए इस निर्णय की सफलता इस बात से तय होगी कि भारत कितनी कुशलता से अपनी तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था को आधिकारिक भारतीय मानक समय के साथ जोड़ पाता है। यदि इसे केवल नियम के रूप में नहीं, तकनीकी आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक दक्षता और डिजिटल भारत की विश्वसनीयता के अभियान के रूप में लागू किया गया तो देश की घड़ियां ही नहीं, उसकी व्यवस्थाएं भी पहले से अधिक समन्वित ढंग से चल सकेंगी। समय की सबसे बड़ी कीमत उसकी गति में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करने में है।

डिजिटल दुनिया में समय की कीमत

भारत में हर जगह घड़ी एक ही समय बताती है। दिल्ली में सुबह के दस बजे हैं तो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या श्रीनगर में भी घड़ी दस बजे ही दिखाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब पूरे देश में पहले से ही एक ही समय लागू है, तो फिर 'एक देश, एक समय' जैसी पहल की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमारी दीवार पर लगी घड़ी में नहीं, बल्कि उन डिजिटल प्रणालियों में छिपा है, जो पर्दे के पीछे देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को संचालित करती हैं। दरअसल देश में समय एक हो सकता है, लेकिन उस समय को निर्धारित करने और अलग-अलग प्रणालियों तक पहुंचाने वाले स्रोत हमेशा एक जैसे नहीं रहे हैं। बैंकिंग सिस्टम, सर्वर, दूरसंचार नेटवर्क, बिजली ग्रिड और कई दूसरे महत्वपूर्ण डिजिटल सिस्टम सटीक समय के लिए उपग्रह आधारित तकनीक पर निर्भर हैं। इनमें जीपीएस जैसे विदेशी सिस्टम भी शामिल हैं। इसलिए 'एक देश, एक समय' का मकसद सिर्फ सभी घड़ियों को एक समय पर लाना नहीं, बल्कि देश के महत्वपूर्ण डिजिटल और तकनीकी ढांचे को एक विश्वसनीय, सुरक्षित और स्वदेशी समय-स्रोत से जोड़ना है।

आज डिजिटल दुनिया में समय की कीमत बढ़ गई है। पहले घड़ी में कुछ सेकेंड का अंतर शायद किसी के लिए मायने नहीं रखता था, लेकिन डिजिटल लेन-देन और अत्याधुनिक तकनीकी प्रणालियों में मिलीसेकेंड और कई बार नैनोसेकेंड का अंतर भी महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी बैंकिंग लेन-देन का समय, शेयर बाजार में किसी आदेश का रिकार्ड, दूरसंचार नेटवर्क में डाटा का आदान-प्रदान या बिजली ग्रिड में विभिन्न इकाइयों का समन्वय, इन सभी के लिए सटीक समय जरूरी है। इसीलिए टाइम-स्टैंपिंग आधुनिक डिजिटल व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। टाइम-स्टैंप किसी कार्रवाई या घटना के समय का सटीक रिकार्ड होता है। यदि अलग-अलग सिस्टम की घड़ियों में थोड़ा भी अंतर हो तो घटनाओं का सही क्रम निर्धारित करने, लेन-देन का रिकार्ड रखने और विभिन्न प्रणालियों के बीच समन्वय में परेशानी आ सकती है।

सरकार अब भारतीय मानक समय यानी आइएसटी के सटीक प्रसार के लिए देश में आवश्यक बुनियादी ढांचा तैयार कर रही है। सरकारी विभागों और व्यावसायिक संस्थानों को अपनी घड़ियों और सर्वरों को अधिक सटीक तरीके से आइएसटी के साथ समायोजित करना होगा। इसका असर बैंकिंग और डिजिटल भुगतान से लेकर रेलवे, हवाईअड्डों, दूरसंचार, पावर ग्रिड और आधिकारिक डिजिटल रिकार्ड तक दिखाई देगा। इस व्यवस्था में भारत के स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन सिस्टम 'नाविक' की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके अलावा अन्य स्वीकृत भारतीय समय स्रोतों का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इससे समय के लिए विदेशी प्रणालियों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।

-शिशिर शुक्ला

खरी-खरी

युद्ध कला भी है, विज्ञान भी

प्रेमकुमारी नाहटा

जब कुछ लोग या देश लड़ रहे हों और विशेषकर जब वे शक्तिशाली हों तो बीच-बचाव की सोचो ही नहीं, क्योंकि बीच-बचाव करने वाले ही अक्सर मारे जाते हैं। अभी-अभी विश्व में युद्ध चल रहा था और लड़ने वाले शक्तिशाली ही थे। यह भारतवर्ष की बुद्धिमानी है कि वह चुप रहा। लड़ाई एक कला है और विज्ञान भी। जब युद्ध कला थी तो ज्यादा आकर्षण था, क्योंकि आमने-सामने युद्ध लड़ा जा रहा था। अब इस मशीनी युग में वह आसमानी हो गया है और मिसाइल, ड्रोन आदि द्वारा लड़ा जाकर विज्ञान हो गया है।

याद रखिए, मौन घर में मरघट सी शांति तो ला सकता है, पर रौनक, प्रसिद्धि, समृद्धि आदि लड़ाई के बाद ही आती है। कहावत है ना "जो बोले उसके बेर बिके" किंतु मेरा अपना मानना है कि बेर बिके या ना बिके, लड़ना अपने आप में एक सुखद अनुभव है। जैसे कला कला के लिए, वैसे ही लड़ाई सिर्फ लड़ाई के लिए।

तो मेरी बात मानिए और लड़िए। कारण हो या अकारण, न्याय के लिए या अन्याय के विरुद्ध लड़िए, सिद्धांतों के लिए लड़िए, स्वार्थ के कारण लड़िए, अपने लिए या अपने प्रिय लोगों के लिए लड़िए, दोस्तों के लिए या दुश्मनों के विरुद्ध लड़िए, बाहरी शत्रुओं से लड़िए, अपने भीतरी अवगुणों से लड़िए। अरिहंता बनिए और अपने तथा दूसरों के दोषों का अंत करिए, लड़ते रहिए, अनथके लड़िए, थक जाएं तो फिर से तरोताजा होकर लड़िए। दुनिया लड़ने वालों को सिर-माथे पर बैठाती है और शांत-निरीह लोगों को पैरों तले कुचलती है। यदि लड़े नहीं तो खरे सिक्कों की तरह बाजार से बाहर कर दिए जाओगे। लड़ना सिर्फ आगे बढ़ने के लिए नहीं, किंतु अपनी जगह पर बने रहने के लिए भी जरूरी है। साथ ही औरों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए भी लड़ाई जरूरी है। राजनीति में भी चुनाव लड़कर जो आते हैं, वे किसी की कृपा पर सांसद बने न बनें, पर सांसदों से ज्यादा ऊंचे ओहदे पर माने जाते हैं। याद रखिए, जिस देश का प्रत्येक व्यक्ति लड़ने को तैयार हो, वही प्रजातंत्र जिंदा रहता है। तो कम से कम प्रजातंत्र की सलामती के लिए लड़िए।

पोस्ट

कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता से बड़े शहरों में अवैध तरीके से पीजी खुल रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उनमें कई दुर्घटनाएं घट चुकी हैं।
गोविंद सिंह@govind24

डीयू में करीब 2.5 लाख छात्र हैं, पर छात्रावास की सुविधा है लगभग 7,000 के लिए। अब छात्रावास की कमी को लेकर जो हंगामा हो रहा है, वह पहले क्यों नहीं हुआ। चार दिन सब बोलेंगे, पर कुछ नहीं बदलेगा।
सुशांत सिन्हा@SushantBSinha

'नाराज फूफा' कोई और नहीं, बल्कि वह व्यक्ति है जो अपनी आदतन नकारात्मकता से खुद लाचार है। हर दिन जहर उगल-उगल कर देश की रफ्तार को रोकना चाहता है।
तुहिन सिन्हा@tuhins

'हनुमान अंश' ने भारतीय सिनेमा में मेरी उम्मीदों को जगा दिया। बिना किसी झिझक के आध्यात्मिक। पूरी तरह से भारतीय। कोई सुपरस्टार नहीं, फिर भी पूरी कास्ट ने इसे शालीनता के साथ निभाया है। कभी-कभी सिनेमा आपको शांत, संतुष्ट और खुद के करीब महसूस कराता है।
गीतांजलि जे. आंग्मो@GitanjaliAngmo

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या वैकल्पिक ईंधन वाली गाड़ियों की बिक्री में बढ़ोतरी एथनाल मिश्रित पेट्रोल पर घटते भरोसे को दर्शाती है?

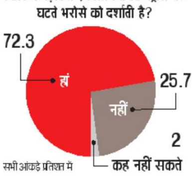

सभी आंकड़े प्रतिशत में

आज का सवाल

क्या 'हनुमान अंश' फिल्म की सफलता फिल्म जगत के दृष्टिकोण में बदलाव ला सकती है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है

जनपथ

चक्कर उपग्रह काटते अंतरिक्ष में जाय,
त्रुटि नक्शे में किसलिए रही निरंतर आय।
रही निरंतर आय करे हर देश शिकायत,
होय शिकायत दूर जल्द करके पंचायत।
सीमा त्रुटि दो इंच करा सकती है टक्कर,
होना चहिए खत्म गलतियों का यह चक्कर।
-ओम प्रकाश तिवारी

मध्य प्रदेश डायरी

जहरीली शराब से मौतों का जिम्मेदार कौन

धनंजय प्रताप सिंह
डिप्टी पालिटिकल एडिटर (स्टेट), मध्य प्रदेश

सागर जिले के बंडा से लगे गांवों में जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला इन दिनों चर्चा में है। यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश के मुरैना, मंदसौर, इंदौर सहित कई शहरों में जहरीली शराब के सेवन से लोगों की जान जा चुकी है। सवाल है कि आखिर प्रशासन ऐसे मामलों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं कर पा रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए बुरहानपुर, खंडवा, उज्जैन और सिरोंज जैसे शहरों की ओर देखना होगा, जहां कभी दंगे भड़कना आम बात थी। हालात तब बदले, जब सरकार ने सख्ती दिखाते हुए स्पष्ट कर दिया कि जिले में दंगा हुआ तो एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी तय होगी और उन्हें हटाया जा सकता है। इसके बाद प्रशासनिक जवाबदेही का असर दिखाई दिया और दंगों पर काफी हद तक अंकुश लगा। तो फिर जहरीली शराब के मामले में वही जवाबदेही क्यों नहीं दिखाई देती? आखिर एसपी और कलेक्टर कर क्या रहे हैं? उनके जिले में जहरीली शराब बन कैसे रही है, बाजार तक पहुंच कैसे रही है और खुलेआम बिक कैसे रही है? जब इस अवैध कारोबार का नतीजा लोगों की मौत के रूप में सामने आ रहा है, तब प्रशासन की जिम्मेदारी आखिर तय क्यों नहीं होती? सवाल सिर्फ जहरीली शराब से होने वाली मौतों का नहीं, बल्कि उस पूरे प्रशासनिक तंत्र का भी है, जिसकी नाक के नीचे यह कारोबार फल-फूल रहा है।

यह तो दिखाई दे रहा है कि पूरा प्रशासनिक तंत्र कमजोर हो चुका है। कभी कफ सिरप से, कभी शराब से, कभी दूषित पानी से मौतों का क्रम थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कैबिनेट मंत्री दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हुआ करते थे। अब मंत्री अपने प्रभार के जिलों में रात में रुकना तो दूर, दौरा तक नहीं करते। वहीं कलेक्टर भी दूरस्थ क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस के संरक्षण में ही अवैध रूप से जहरीली शराब का धंधा फल-फूल रहा है। लोकायुक्त संगठन या ईओडब्ल्यू जैसी संस्थाएं, जो भ्रष्टाचार और गड़बड़ी रोकने के लिए हैं, वे खुद भ्रष्टाचार का शिकार लगती हैं। सिस्टम के चरमरा जाने से नैतिक और अनैतिक का अंतर ही खत्म हो चला है।

प्रशासनिक तंत्र की नाकामी का शिकार होती जनता। फाइल

ये घटनाएं अचानक नहीं हुई हैं। सागर जिले में जिस जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, उसका सच जनसुनवाई में भी शिकायत के रूप में सामने आया था। घर के सामने अवैध तरीके से शराब बेचने के वीडियो फुटेज तक दिए गए थे, लेकिन आरोपितों पर कार्रवाई के बजाय शिकायतकर्ता पर ही एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर प्रताड़ित किया गया। लगता है प्रशासन ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने में रुचि नहीं रखता। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से जो मौतें हुई थीं, उसकी शिकायत भी पहले ही की गई थी, लेकिन प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई थी।

सस्ती शराब का लालच मौत की वजह बनता जा रहा है। इस अवैध धंधे को जड़ जमाने का मौका मिलने की वजह यह है कि सरकार ने वर्षों से शराब दुकानों की संख्या न बढ़ाने का संकल्प ले रखा है। शराब की दुकानों के बीच आबादी बढ़ गई और इसी का फायदा अवैध रूप से शराब बनाने वाले उठा रहे हैं। शराब की उपलब्धता पास में ही करने के लिए अवैध तरीके से शराब तस्करी कर रहे हैं और इसकी आड़ में जहरीली शराब भी बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी पुलिस या प्रशासन को न हो, पर लगता है पुलिस कुछ देखना, सुनना या समझना नहीं चाहती। यही वजह है कि अवैध शराब के धंधे पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। ऐसे में तो लोग पास में ही उपलब्ध सस्ती शराब के चक्कर में जहर पीते रहेंगे, उनकी मौतें होती रहेंगी और सरकार एवं विपक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगा आगे बढ़ते रहेंगे।

प्रशासनिक तंत्र की जवाबदेही तय होती नहीं दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल है कि जब ये मामले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ही सामने आते हैं तो आखिर पंच, सरपंच और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? संवेदनहीनता से कैसे काम चलेगा? आखिर जब दंगों पर कार्रवाई के लिए एसपी और कलेक्टर को चेतावनी दी जा सकती है तो अवैध शराब से मृत्यु के मामले में क्यों नहीं? अब ग्रामसभा को अधिकार संपन्न बना कर मजबूत करना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक मौके देने होंगे। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि संभाग या जिले स्तर पर पुलिस, प्रशासन या जनप्रतिनिधियों की व्यवस्था पर भरोसा करने लायक अब कुछ बचा नहीं है।

हिमाचल प्रदेश डायरी

जल संरक्षण जितना ही आवश्यक भाषा संरक्षण

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

विषय पर आने से पहले एक सत्यकथा आपकी प्रतीक्षा में है...आइए! कुछ वर्ष पूर्व पशुपालकों पर आधारित एक कार्यक्रम पटना में था जहां करीब 300 लोग बुलाए गए थे। इन्होंने सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होकर अपनी आर्थिक स्थिति को संवारा था। जितने अधिकारी बोले, सब अंग्रेजी में...बीज भाषण भी अंग्रेजी में हुआ और कार्यक्रम विषयक सूचना/सामग्री भी अंग्रेजी में रही। उसके बाद केंद्र से आए अधिकारी का संबोधन था और अंत में मंत्री का। केंद्रीय अधिकारी ने कहा, 'इस हाल में आठ दस लोग ही अंग्रेजी समझ सके होंगे, यह अन्याय है। केवल आठ दस लोगों को ही बात समझ में आई...सो हमें यह कार्यक्रम फ्रेंच या ग्रीक में करना चाहिए था, ताकि किसी को कुछ समझ न आए।' उसके बाद सब हिंदी में संवाद करने लगे।

यह कहानी इसलिए स्मरण हो आई, क्योंकि हाल में हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। नाम है 'ड्राप्स आफ चेंज, इंपेक्टफुल स्टोरीज आफ जल शक्ति विभाग हिमाचल प्रदेश।' इसमें 100 उदाहरण हैं या कहें कि सफलता की कहानियां हैं कि कैसे जल संरक्षण किया, पानी घर तक आया और कितनी पंचायतों की प्यास बुझी इत्यादि। कोई विभाग जब उत्कृष्ट कार्य करे तो उसे पुस्तक में सहेजना सराहनीय है। एक तो उत्कृष्टता दर्ज हो जाती है। दूसरे अन्य अधिकारी ही नहीं, समाज भी जल संरक्षण के कार्यों का अनुकरण कर सकता है। तीसरा लाभ यह कि जनता और अपने-अपने क्षेत्रों में डटे कर्मचारी भी अनुभव करें कि उनकी कर्तव्यनिष्ठा दर्ज हो रही है, लेकिन जल संरक्षण के लिए जो सदिच्छा या श्रम संवर्धन दिखाया गया, उसके साथ ही संप्रेषण और भाषा संरक्षण का ध्यान कौन रखेगा? हिंदी, हिंदी करते हुई हमारी समूची व्यवस्था ने यह कैसे मान लिया कि पंप आपरेटर से लेकर लाइनमैन और फिटर तक सब अंग्रेजी ही समझते हैं, हिंदी नहीं? सवाल अंग्रेजी बनाम हिंदी का तो है ही नहीं, यह तो सामान्य समझ की बात है कि कैसा कार्य, किस वर्ग को किस भाषा में पढ़ाया जाए कि वह अधिकाधिक लोगों तक पहुचे। जब तक, मक्खी पर मक्खी मारने को शोध और नवाचार का नाम दे देने के अभ्यस्त अधिकारी आसीन हैं, हिंदी को कहीं बाहर से घबराने की आवश्यकता क्यों हो? धन्यवाद इसलिए कि वेबसाइट खोलते ही एक दो संदेश हिंदी में हैं, लेकिन जब हिंदी चुनें तो 'प्रोग्राम्स' का शीर्षक कार्यक्रम में नहीं, 'कार्यक्रमों' में बदल जाता है।

जल शक्ति विभाग द्वारा हिंदी के बजाय अंग्रेजी में पुस्तक प्रकाशित करने पर सवाल। इंटरनेट मीडिया

हाल का एक और उदाहरण हिमाचल पथ परिवहन निगम के पचास वर्ष पूरे होने पर दिखा था जब एक काफी टेबल बुक अंग्रेजी में छपी। यकीनन उसमें उपलिब्धयां होंगी, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में बस संचालन आसान काम तो है नहीं। कई कठिन रास्ते हैं, कहीं हिमपात वाले क्षेत्र हैं। उन कहानियों के नायक चालक, परिचालक आदि ही रहे होंगे। 10853 कर्मचारियों और करीब 8000 पेंशनरों वाला निगम उसी पुस्तक के माध्यम से आसानी से कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकता था यदि वह हिंदी में रही होती। कुछ प्रतियां बसों में रखवाई जा सकती थीं, पर नहीं, उद्देश्य शायद और रहा हो। जैसे यह कि दिल्ली तक काम पहुंच जाए बस...और दिल्ली में तो किसी को हिंदी कहां आती है!

हिंदी के साथ त्रासदी यह है कि कार्यालयों में जहां हिंदी से काम चलना चाहिए, वहां मसूरी से लौटे अधिकारी अंग्रेजी को ही जलपान करवाते हैं और जब व्यक्ति थाने या न्यायालय में जाता है तो उसे क्षोभ होता है कि वहां जो भाषा प्रयोग की जाती है, उससे पिंड किस जन्म में छूटेगा। वहां, भाषा दिवस पर पुरस्कार के लिए प्रविष्ट होने के उद्देश्य से लिपि देवनागरी ही रहेगी, लेकिन घटनास्थल को जा ए बकूहा लिखा जाएगा, जबकि सही शब्द वकूआ है। आला अफसर यानी उच्च अधिकारी और वही आला ए वारदात हो जाता है तो हथियार बन जाता है। इलाका ए हदूद का रवाना आदि ऐसे शब्द हैं, जो थानों के रजिस्टरों पर, ई रोजनामचों पर अमिट काई की तरह बैठे हुए हैं। पावर आफ अटार्नी के लिए आज भी पावर आफ अटार्नी लिखा जाता है और देने वाले को मुख्तार देहिंदा। अधिकार पत्र लिखने से पता नहीं क्या समस्या है। अधिकार पत्र देने वाले अधिक हों तो उन्हें दहिंदगान लिखा जाता है। किंतु तहसील के बाहर टाइप करने वाले मुख्तार दहिंदागण लिखता है। एक बार विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई जब टाइप करने वाले ने देहिंदगान को दहिंदागण से भी आगे जाकर दरिंदागण लिख दिया।

इस कारण से या उस कारण से, इस प्रयोजन या उस प्रयोजन से यदि उद्देश्य यही है कि किसी को कुछ पता न चले तो यही शैली उपयुक्त है, पर यदि पर्दे उठाने हैं, जन की भाषा में जन तक पहुंचना है तो नीति नियंता हों या अधिकारी, हम हों या आप विचार अवश्य करना चाहिए। हिंदी का अपमान कहीं संप्रेषण का अपमान ही न बन जाए। क्या ऐसा करने वाले सम्मान के पात्र होंगे?

अच्छा प्रदर्शन कर रही भारतीय अर्थव्यवस्था : लाहिड़ी

नई दिल्ली: नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जल्द ही अपनी पुरानी रफ्तार हासिल कर लेगी और चालू खाता सरप्लस की स्थिति में लौट आएगी। लाहिड़ी ने आगे कहा कि भारतीय इकोनमी के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश की कुल जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की कम हिस्सेदारी है। (प्रेट्र)

रियल-टाइम पेमेंट में भारत की लीडरशिप से कई ऐसी अरबों डालर की फिनटे कंपनियां बन सकती हैं जो वैश्विक बाजार में सेवाएं दे सकें।
– हर्षिल माथुर, सीईओ, रेजरपे

सेंसेक्स	74,764.23 ▼ 813.35	निफ्टी	23,431.50 ▼ 203.60	सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,58,000 ▼ ₹ 100	चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,43,400 ▲ ₹ 2,300	डालर	₹ 95.08 ▲ ₹ 0.34	क्रूड प्रति बैरल	$ 100.5

जुलाई के बाद कच्चा तेल फिर 100 डालर पार

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा, भुगतान संतुलन और रुपये की कीमत व महंगाई पर पड़ेगा दबाव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पश्चिम एशिया में तेल संयंत्रों और टैंकर पर हमलों के बाद कच्चे तेल की कीमत जुलाई के बाद फिर 100 डालर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। तेल कंपनियों की मौजूदा प्राथमिकता वैश्विक अस्थिरता के बीच क्रूड की आपूर्ति बनाए रखना है। अंतरराष्ट्रीय जानकारों का अनुमान है कि कीमतें फिलहाल 100 डालर या इससे ऊपर बनी रह सकती हैं। इससे भारत के भुगतान संतुलन, रुपये की कीमत और महंगाई पर दबाव बढ़ने की आशंका है। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड का सबसे अधिक कारोबार वाला वायदा अनुबंध मंगलवार को 97.89 डालर प्रति बैरल पर था।

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक है और अपनी जरूरत का करीब 88 प्रतिशत हिस्सा आयात करता है। कच्चे तेल के 100 डालर प्रति बैरल से ऊपर रहने का सीधा मतलब आयात बिल में इजाफा, चालू खाता घाटा (सीएडी) का बढ़ना और रुपये पर दबाव है। वित्त मंत्रालय का एक पुराना आकलन है कि हर 10 डालर प्रति बैरल की बढ़ोतरी से भारत का वार्षिक आयात बिल करीब 13-14 अरब डालर बढ़ जाता है। इसका सीधा असर भुगतान संतुलन (अंतरराष्ट्रीय कारोबार में डालर के देश में आने और देश से बाहर जाने का अंतर) पर होता है और इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। इस साल रुपये की कीमत में भारी गिरावट के लिए कच्चे तेल की कीमतों को ही कारण बताया जाता है।

- क्रूड में 10 डालर प्रति बैरल की वृद्धि से वार्षिक आयात बिल में होती है 13-14 अरब डालर की बढ़ोतरी
- इस साल रुपये की कीमत में भारी गिरावट के लिए क्रूड की कीमतों को ही बताया जा रहा है असली वजह

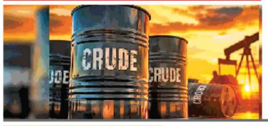

भारत ने सितंबर में 102 डालर प्रति बैरल पर खरीदा कच्चा तेल : सरकार की पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल (पीपीएसी) के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में भारत ने औसतन 102.11 डालर प्रति बैरल की दर से कच्चा तेल खरीदा है। यह अगस्त 2026 के मुकाबले 10 प्रतिशत से ज्यादा है। अगस्त में औसत खरीद मूल्य 90.19 डालर प्रति बैरल था। जुलाई में यह 82.04 डालर, जून में 83.22 डालर, मई में 106.23 डालर और अप्रैल में 114.48 डालर प्रति बैरल रहा। साफ है कि चार महीने बाद भारत फिर 100 डालर से ज्यादा कीमत चुका रहा है। इस वजह से ही चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल से जुलाई के दौरान आयात बिल 56 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 63.4 अरब डालर पहुंच गया, जबकि आयात की मात्रा लगभग पिछले साल जितनी (8.19 करोड़ टन) ही रही है। अप्रैल-जून तिमाही में ही बिल 50 अरब डालर हो चुका था। 2025-26 में भारत का कच्चा तेल आयात बिल 121.8 अरब डालर रहा था, जो इसके पिछले वर्ष के 137.2 अरब डालर से कम था।

पेट्रोल पर पांच तो डीजल पर 23 रुपये प्रति लीटर का नुकसान

कच्चे तेल के महंगा होने का असर सबसे ज्यादा सरकारी तेल कंपनियों पर हो रहा है। सितंबर महीने की अब तक की औसत कीमत पर सरकारी तेल कंपनियों को पेट्रोल पर पांच रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 23 रुपये प्रति लीटर की नुकसान हो रही है। जबकि घरेलू एलपीजी पर अंडर-रिकवरी 200 रुपये प्रति सिलेंडर चल रही है। वैसे यह अप्रैल, 2026 के मुकाबले काफी कम है।

रुपया 34 पैसे टूटकर 95.08 पर पहुंचा

मुंबई, प्रेट्र: रुपया बुधवार को डालर के मुकाबले 34 पैसे टूटकर 95.08 के स्तर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने कहा कि कमजोर शेयर बाजार और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) की बिकवाली से भी रुपये पर दबाव बढ़ा। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में डालर के मुकाबले रुपया 94.80 पर खुला, जो दिन का उच्चतम स्तर था। बाद में रुपया कमजोर होकर 95.22 के निचले स्तर तक आया। अंत में रुपया 95.08 प्रति डालर पर बंद हुआ।

आइटी शेयर लुढ़के, सेंसेक्स 813 अंक टूटकर तीन महीने के निचले स्तर पर

मुंबई, प्रेट्र : पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ कच्चे तेल की कीमत 100 डालर प्रति बैरल के पार पहुंचने से मानक सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 813.35 अंक यानी 1.08 प्रतिशत लुढ़क कर करीब तीन महीने के निचले स्तर 74,764.23 पर बंद हुआ। वहीं एनएसई निफ्टी 203.60 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,431.50 अंक पर बंद हुआ। 813 अंक लुढ़क कर तीन महीने के निचले स्तर पर आ गया। कारोबारियों के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी, एफएमसीजी, वित्तीय सेवाएं और तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और विदेशी निवेशकों की नए सिरे से पूंजी निकासी से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में एचसीएल टेक्नोलाजीज का शेयर सबसे अधिक 4.55 प्रतिशत टूटा। इन्फोसिस (4.43 प्रतिशत), टेक महिंद्रा (3.87 प्रतिशत) और टीसीएस (2.26 प्रतिशत) में भी गिरावट आई। इसके अलावा, नुकसान में रहने वाले शेयरों में एचडीएफसी बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर शामिल हैं। लाभ में रहने वाले शेयरों में अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील, ट्रेंट और एनटीपीसी शामिल हैं। अदाणी पोर्ट्स में सबसे ज्यादा 3.67 प्रतिशत की तेजी आई। एनरिच मनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पोनमुडी आर ने कहा, 'बिकवाली दबाव के साथ घरेलू शेयर बाजार में लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरावट जारी रही। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, वैश्विक तनाव बने रहने और बाजार में बढ़ती अस्थिरता ने निवेशकों का भरोसा प्रभावित किया। इससे जोखिम लेने की धारणा प्रभावित हुई।' उन्होंने कहा कि भारत अस्थिरता सूचकांक में छह प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। यह बाजार में बढ़ती सावधानी और निकट अवधि को लेकर सतर्क रुख को दर्शाती है।

- तेल एवं गैस कंपनियों के शेयरों में बिकवाली और विदेशी निवेशकों की नए सिरे से पूंजी निकासी से भी निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

एक नजर में

खास ईवी प्लेटफार्म पर बनी एसयूवी लांच करेगी हुंडई

नई दिल्ली: हुंडई इंडिया जल्द ही एक खास ईवी प्लेटफार्म पर बनी एसयूवी लांच करने जा रही है। माना जा रहा है कि यह नई ईवी 2026 अंत तक बाजार में आ जाएगी। पहले इसे मार्च 2027 तक लांच करने की योजना थी। कंपनी ने बताया कि मौजूदा ईवी पोर्टफोलियो में उसके पास अभी आयोनिक5 और क्रेटा इलेक्ट्रिक हैं। कंपनी लांच से पहले अपने सेल्स और सर्विस नेटवर्क को तैयार कर रही है और अपने डीलर कर्मचारियों को नई ईवी के लिए तैयार रहने की ट्रेनिंग दे रही है। (प्रेट्र)

जियो पेमेंट ने सीमा पार भुगतान सुविधा शुरू की

मुंबई: जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी जियो पेमेंट साल्यूशंस लिमिटेड ने सीमा पार भुगतान प्लेटफार्म शुरू करने का एलान किया है। इस सुविधा का मकसद भारतीय निर्यातकों को वैश्विक ग्राहकों से अंतरराष्ट्रीय भुगतान स्वीकार करने में मदद करना और उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है। यह पहल भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) से पेमेंट एग्रीगेटर फार क्रास बार्डर (पीए-सीबी) के रूप में काम करने की मंजूरी मिलने के बाद शुरू की गई है। इस सुविधा के तहत निर्यात और आयात दोनों लेनदेन आएंगे। (प्रेट्र)

लगातार तीसरे दिन सस्ता हुआ सोना, चांदी चढ़ी

नई दिल्ली: कम मांग से बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे सत्र में गिरावट आई और यह 100 रुपये टूटकर 1,58,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया। हालांकि, चांदी मंगलवार के 2,41,100 रुपये प्रति किलोग्राम के बंद स्तर से 2,300 रुपये बढ़कर 2,43,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। एचडीएफसी सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक सौमिल गांधी ने कहा, 'सप्ताह के आखिर में आने वाले अमेरिकी महंगाई आंकड़ों से पहले निवेशक सतर्क रुख अपना रहे हैं।' (प्रेट्र)

अदाणी एयरपोर्ट्स तीसरी सबसे मूल्यवान हवाई अड्डा कंपनी बनी

नई दिल्ली, प्रेट्र: अदाणी एयरपोर्ट कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे मूल्यवान हवाई अड्डा कंपनी बन गई है। टेमसेक, ब्लैकराक प्रबंधित फंड्स, अल्फा वेव ग्लोबल और प्रेमजी इन्वेस्ट जैसे वैश्विक और घरेलू निवेशकों से एक अरब डालर जुटाने के बाद कंपनी ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस सौदे के बाद अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स की वैल्यूएशन 19 अरब डालर हो गई है। अदाणी एयरपोर्ट से आगे स्पेन की एएना और एयरपोर्ट्स आफ थाईलैंड हैं। हालांकि, यह दोनों कंपनियां सार्वजनिक क्षेत्र की हैं

अदाणी एयरपोर्ट्स आठ एयरपोर्ट्स का संचालन करती है, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यह भारत के पैसेंजर ट्रैफिक का लगभग एक-चौथाई और एयर-कार्गो आकार का लगभग एक-तिहाई हिस्सा संभालती है। इस विस्तार ने इसे एयरपोर्ट्स की संख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपरेटर बना दिया है, हालांकि पैसेंजर वाल्यूम के मामले में जीएमआर बड़ी कंपनी है। स्पेन के एयरपोर्ट आपरेटर एएना का बाजार पूंजीकरण लगभग 46 अरब डालर है जबकि एयरपोर्ट्स आफ थाईलैंड का वैल्यूएशन 27 अरब डालर है। जीएमआर एयरपोर्ट्स का एमकैप 10.9 अरब डालर है।

एक अरब डालर जुटाने के बाद हासिल की उपलब्धि, स्पेन की एएना और एयरपोर्ट्स आफ थाईलैंड अदाणी एयरपोर्ट से आगे

सही वक्त पर होंगे अमेरिका से डील पर हस्ताक्षर

मुंबई, प्रेट्र: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित व्यापार समझौता लगभग अंतिम रूप ले चुका है और कुछ मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत जारी है। उन्होंने कहा कि समझौते पर उचित समय पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। किसी भी व्यापार समझौते में दोनों देशों को एक-दूसरे के बाजार में कुछ विशेष रियायतें देना जरूरी होता है। बता दें कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में कहा था कि अमेरिका द्वारा भारत को उसके प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में बेहतर शुल्क शर्तें देने के बाद ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते का ब्योरा घोषित किया जाएगा।

अग्रवाल ने कहा, 'वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अंतिम रूप ले चुका है। दोनों पक्ष कुछ मुद्दों पर अभी बातचीत कर रहे हैं और उचित समय पर समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।' उन्होंने कहा कि किसी भी व्यापार समझौते में दोनों देशों को एक-दूसरे के बाजार में कुछ विशेष रियायत के साथ प्रवेश देना जरूरी होता है। अग्रवाल ने कहा, 'भारत की ओर से यह करना आसान है, क्योंकि वह सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र के आधार पर शुल्क लगाता है। अमेरिका की शुल्क व्यवस्था अलग है। वहां कार्यकारी फैसलों के आधार पर शुल्क लगाए जा रहे हैं। इसलिए अमेरिका ऐसी व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिससे दोनों देशों के शुल्क में अंतर पैदा हो और भारत को विशेष बाजार पहुंच मिल सके। उचित समय आने पर दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर कर सकेंगे।' उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ रहा है। गोयल सितंबर के अंत में अमेरिका जाएंगे। वह मिलवाकी में होने वाली जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रीर के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ट्रेड डील से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। अमेरिका को भारत का वस्तु निर्यात अप्रैल-जुलाई में तीन प्रतिशत बढ़कर 34.5 अरब डालर हो गया, जबकि आयात 22.42 प्रतिशत बढ़कर 22.12 अरब डालर रहा।

- वाणिज्य सचिव बोले-दोनों पक्षों के बीच कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी जारी
- जी-20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने अमेरिका जाएंगे गोयल

देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में तेजी 110 कंपनियां जल्द बनेंगी यूनिकार्न

3 लाख करोड़ से ज्यादा है चीता इंडेक्स में शामिल कंपनियों का वैल्यूएशन

2,820 करोड़ रुपये है प्रत्येक कंपनी का औसत मूल्यांकन

1.1 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं इन 110 स्टार्टअप में

भारत में संभावित यूनिकार्न की संख्या बढ़ रही है और इसमें विविधता भी आ रही है। 2026 एएसके प्राइवेट वेल्थ हुरुन इंडिया 'चीता' इंडेक्स में स्टार्टअप्स की संख्या पांच साल में दोगुनी से ज्यादा यानी 110 हो गई है और इनके जल्द ही यूनिकार्न क्लब में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। अब फिनटेक और एसएएएस (साफ्टवेयर एज अ सर्विस) के साथ एआइ, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीनटेक और एयरोस्पेस कंपनियां भी इस खास सूची में जगह बनोन के लिए होड़ कर रही हैं। 2021 में जब यह इंडेक्स शुरू हुआ था, तब इसमें 54 कंपनियां थीं। यानी पांच साल में इसमें 104 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जो सालाना लगभग 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि बढ़ोतरी है।

चीता इंडेक्स में शामिल स्टार्टअप की विशेषता

इस इंडेक्स में 'चीता' का मतलब है एक ऐसा गैर सूचीबद्ध स्टार्टअप, जिसकी शुरुआत वर्ष 2000 या उसके बाद हुई हो और उसका वैल्यूएशन 20 करोड़ से 50 करोड़ डालर के बीच हो। इतना ही नहीं उस कंपनी के पांच साल के अंदर यूनिकार्न का दर्जा हासिल करने की संभावना है।

फिनटेक सेक्टर की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा

17 स्टार्टअप के साथ फिनटेक चीता इंडेक्स में सबसे बड़ा सेक्टर बनकर उभरा है। इसके बाद एसएएएस (16) और ई-कामर्स (12) का स्थान रहा। बेंगलुरु में सबसे ज्यादा 36 चीता कंपनियां हैं जबकि एनसीआर में 25 और मुंबई में इस तरह की 16 कंपनियां हैं।

भारत का उद्यमिता माहौल विकास के एक अहम दौर में प्रवेश कर रहा है। तेजी से बढ़ने वाले व्यवसायों की अगली पीढ़ी पारंपरिक टेक्नोलाजी सेक्टर से कहीं आगे निकलकर उभर रही है। यह विविधता भारत के उद्यमिता टैलेंट की गहराई और वैश्विक स्तर पर मुकाबला करने वाले व्यवसाय बनाने की बढ़ती महत्वाकांक्षा को दर्शाती है। -**राजेश सलूजा**, एमडी और सीईओ, एएसके प्राइवेट वेल्थ

इंडेक्स में मोबिलिटी, डिफेंस और एआइ कंपनियां शामिल

चीता इंडेक्स में शामिल होने वाली कंपनियों मे मोबिलिटी (ब्लू एनर्जी मोटर्स, मैटर, पीएमआइ इलेक्ट्रो मोबिलिटी, रिवर मोबिलिटी), एयरोस्पेस और डिफेंस (सागर डिफेंस इंजीनियरिंग, ध्रुवा स्पेस, दिगंतारा), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (सिंपलीस्मार्ट, राकेट, क्यूपीआइएआइ, फ्लेम, फ्रीहैंड) और सर्विसेज (स्नैबिट, प्रोंटो, आलहोम) से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार, एयरोस्पेस व डिफेंस में 'चीता' कंपनियों की संख्या 2023 में एक थी जो 2026 में बढ़कर पांच हो गई। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में यह संख्या चार से बढ़कर आठ और क्लीनटेक में तीन से बढ़कर पांच हो गई।

इनपुट-प्रेट्र जागरण इन्फो

घट सकता है एनएसई आइपीओ का आकार

नई दिल्ली, प्रेट्र: नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आइपीओ) का आकार घटकर 25,000-27,000 करोड़ रुपये रह सकता है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि कुछ शेयरधारकों के बिक्री से पीछे हटने के कारण पहले प्रस्तावित छह प्रतिशत के मुकाबले बिक्री पेशकश (ओएफएस) का आकार घटकर 5.2-5.5 प्रतिशत रह सकता है। ओएफएस का आकार घटने से कुल निर्गम का आकार पहले के अनुमानित 30,000 करोड़ रुपये के मुकाबले घटकर 25,000-27,000 करोड़ रुपये रह सकता है। इस आकार के साथ एनएसई भारत के अब तक के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम का रिकार्ड बनाने से पीछे रह सकता है। फिलहाल हुंडई मोटर इंडिया का 27,870 करोड़ रुपये का आइपीओ अब तक का सबसे बड़ा निर्गम है।

बताया जाता है कि ओएफएस का आकार घटने की वजह कुछ शेयरधारकों का आइपीओ के दौरान अपनी हिस्सेदारी नहीं बेचने का फैसला माना जा रहा है। उनका मानना है कि बाद में हिस्सेदारी बेचने पर उन्हें बेहतर मूल्यांकन मिल सकता है। उन्होंने कहा कि एनएसई आइपीओ को खुदरा निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाने की भी कोशिश कर रहा है। इसके तहत कीमत इस तरह तय की जा रही है कि ओएफएस में छोटे निवेशकों की अधिक भागीदारी हो और उन्हें लाभ मिल सके।

- कुछ शेयरधारकों के बिक्री से पीछे हटने से 25-27 हजार करोड़ रह सकता है आकार
- ओएफएस का आकार घटने से एनएसई सबसे बड़े आइपीओ का रिकार्ड बनाने से रह जाएगा पीछे

जियो प्लेटफार्म्स के आइपीओ से प्रतिस्पर्धा

एनएसई का निर्गम अरबपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाले समूह की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफार्म्स के प्रस्तावित निर्गम से प्रतिस्पर्धा करेगा। जियो का निर्गम करीब 37,700 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है, लेकिन इसकी समयसीमा की अभी घोषणा नहीं की गई है।

आइपीओ का प्राइस बैंड 1,700-1,785 रुपये रहने की उम्मीद

आइपीओ का मूल्य दायरा पहले के 2,000 रुपये प्रति शेयर के अनुमान के मुकाबले 1,700-1,785 रुपये प्रति शेयर रहने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार एनएसई का आइपीओ 18 सितंबर को खुलेगा खुलने और 22 सितंबर को बंद होगा। इसका शेयर 25 सितंबर को बाजार में सूचीबद्ध हो सकता है। सूचीबद्धता 26 सितंबर से शुरू होने वाले 'पितृ पक्ष' से पहले करने का लक्ष्य है।

छह आइपीओ खुले, तीन पूरी तरह सब्सक्राइब हुए

नई दिल्ली, प्रेट्र: बुधवार को छह आइपीओ खुले, जिनमें से रेंटोमोजो, करमतरा इंजीनियरिंग और एलसीसी प्रोजेक्ट्स के आइपीओ को पहले ही दिन पूरी तरह सब्सक्राइब हो गए। वहीं स्टीमहाउस इंडिया के शुरुआती शेयर बिक्री को 42 प्रतिशत जबकि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड (जिसे आर्सील के नाम से जाना जाता है) को 38 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी साल्यूशंस को मात्र 17 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला। रियल एस्टेट डेवलपर प्रणव कंस्ट्रक्शंस के 351 करोड़ रुपये के आइपीओ को आखिरी दिन 121 गुना सब्सक्राइब हुआ। उधर, ओयो की मूल कंपनी प्रिज्म चालू वित्त वर्ष में 6,650 करोड़ रुपये का आइपीओ लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित आइपीओ में नए शेयर जारी किए जाएंगे। मौजूदा शेयरधारक इसमें हिस्सा नहीं लेंगे।

चीनी रिफाइनरियां बाजार में बेचेंगी 2.50 लाख टन सफेद चीनी

नई दिल्ली, प्रेट्र: त्योहारी मौसम से पहले आपूर्ति बढ़ाकर चीनी की कीमतों पर अंकुश लगाने की कोशिशों के बीच देश की चीनी रिफाइनरियां घरेलू बाजार में करीब 2.5 लाख टन सफेद चीनी बेचने की योजना बना रही हैं। श्री रेणुका शुगर्स के एमडी और सीईओ सुशील कुमार ने भारतीय चीनी एवं जैव-ऊर्जा विनिर्माता संघ (इस्मा) के एक कार्यक्रम से इतर मीडिया को यह जानकारी दी।

भारत में श्री रेणुका शुगर्स समेत दो ऐसी चीनी रिफाइनरियां हैं, जो अग्रिम लाइसेंस योजना (एएलएस) के तहत कच्ची चीनी का आयात कर उसे रिफाइन कर निर्यात करती हैं। सरकार ने पिछले महीने इन रिफाइनरियों को एएलएस के तहत रिफाइन की गई चीनी को घरेलू बाजार में बेचने का आदेश दिया था। इसका उद्देश्य त्योहारी मौसम से पहले घरेलू बाजार में चीनी की आपूर्ति बढ़ाना है। कुमार ने कहा कि सरकार के इन कदमों के बाद घरेलू चीनी कीमतों में गिरावट आई है।

राष्ट्रीय फलक

मनी लांड्रिंग कानून के उल्लंघन पर क्रिप्टो एप को नोटिस, यूआरएल हटाने को कहा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो से जुड़े 15 सर्विस प्रोवाइडर्स को वित्त मंत्रालय की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआइयू) ने मनी लांड्रिंग कानून के उल्लंघन के आरोप में नोटिस किया है। साथ ही एफआइयू ने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन को रोकने के लिए सेवा प्रदाताओं को अपने यूआरएल और एप सेवा को भारत में तत्काल बंद करने को कहा है।

वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा जिन सेवा प्रदाताओं को नोटिस भेजा गया है उनमें वीक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज, बीएलएफ ग्लोबल लिमिटेड की ब्लोफिन, रेजोरक्स, बिटूनिक्स, डिजिफिनेक्स, पायोनेक्स जैसे प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज शामिल हैं। ये सभी एक्सचेंज बिना किसी पंजीकरण के अपना संचालन कर रहे थे और ये प्लेटफार्म मनी लांड्रिंग कानून के तहत निर्धारित नियम व शर्तों का भी पालन नहीं कर रहे थे। मार्च 2023 में वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोवाइडर्स को मनी लांड्रिंग कानून के दायरे में इसलिए लाया गया था, ताकि इनके माध्यम से आतंकवाद का वित्तपोषण नहीं हो सके।

देश का कानून यह कहता है कि देश में कार्यरत कोई भी वर्चुअल एसेट प्रोवाइडर्स जो वर्चुअल डिजिटल एसेट का विनिमय, हस्तांतरण, सुरक्षा व प्रबंध के काम में जुड़ा है, उन्हें एफआइयू के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना होगा और नियमों के तहत निर्धारित दायित्व का अनुपालन करना आवश्यक है। लेकिन ये प्लेटफार्म ऐसा नहीं कर रहे थे और इनका अवैध तरीके से संचालन हो रहा था।

गन्ना किसानों को समर्थन का मसला आस्ट्रेलिया ने डब्ल्यूटीओ में उठाया

नई दिल्ली, प्रेट्र: आस्ट्रेलिया ने भारत की घरेलू गन्ना और चीनी नीतियों को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में स्पष्टीकरण मांगा है। उसने दावा किया है कि भारत ने 2018-19 से 2024-25 के दौरान गन्ने के लिए डब्ल्यूटीओ नियमों के तहत तय सीमा से काफी अधिक समर्थन दिया। डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते के तहत इस तरह का समर्थन गन्ने के कुल उत्पादन मूल्य के 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है। भारत सरकार हर चीनी सत्र में गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य तय करती है। यह मूल्य प्रभावी रूप से चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत के रूप में काम करता है। आस्ट्रेलिया का कहना है कि गन्ना किसानों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने को प्रीमियम भी दिया जाता है।

क्षतिपूर्ति उपकर को शामिल कर जीएसटी राजस्व की तुलना 'शरारतपूर्ण' : सीबीआइसी

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) ने बुधवार को कहा कि मासिक जीएसटी राजस्व में वृद्धि के आंकड़े तुलनात्मक कर आधार पर निकाले जाते हैं। उसने पुराने क्षतिपूर्ति उपकर को शामिल कर अपने हिसाब से आंकड़ों की तुलना करने को 'भ्रामक और शरारतपूर्ण' बताया। स

सीबीआइसी ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग के इंटरनेट मीडिया पोस्ट के जवाब में कहा कि हर महीने जारी किए जाने वाले जीएसटी राजस्व के आंकड़े जीएसटी संग्रह के प्रदर्शन की सही तस्वीर पेश करते हैं और इनमें पूरी जानकारी दी जाती है। वृद्धि दर का उद्देश्य यह बताना है कि कर आधार में किस तरह बदलाव आया है।

> हर महीने जारी होने वाले जीएसटी राजस्व के आंकड़े कर संग्रह के प्रदर्शन की सही तस्वीर करते हैं पेश

सीबीआइसी ने कहा, 'वृद्धि दर तभी सार्थक होती है, जब उसकी गणना समान आधार पर की जाए, यानी तुलना के दोनों पक्षों में समान करों को शामिल किया जाए। अन्यथा यह सेब और संतरे की तुलना करने जैसा है।' गर्ग ने एक्स पर लिखा था कि सरकार का सकल जीएसटी संग्रह इस साल अगस्त में 1.99 लाख करोड़ रुपये रहा, जो गत वर्ष की तुलना में 14.8 प्रतिशत अधिक है। चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीनों में जीएसटी संग्रह 10.43 लाख करोड़ रुपये रहा, जो 11 प्रतिशत की वृद्धि है। उन्होंने लिखा, 'हालांकि, सरकार ने एक चाल चली है। 2025-26 के जीएसटी उपकर को चुपचाप आंकड़ों से हटा दिया गया है। इसे शामिल करने पर पांच महीने में सकल जीएसटी वृद्धि 4.08 प्रतिशत और शुद्ध वृद्धि केवल 1.30 प्रतिशत रह जाती है, जो बेहद खराब प्रदर्शन है।' इसके जवाब में सीबीआइसी ने कहा कि दो अलग-अलग आधार से आंकड़े चुनकर उनकी तुलना करने की कोशिश पूरी तरह 'भ्रामक' और शरारतपूर्ण' है। जीएसटी परिषद ने पिछले साल 22 सितंबर, 2025 से तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों को छोड़कर सभी वस्तुओं पर क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त करने का फैसला किया था। तंबाकू और संबंधित उत्पादों पर भी उपकर एक फरवरी, 2026 से हटा दिया गया। इसके बाद संबंधित अवधि में उपकर संग्रह नहीं हुआ।

आइफोन 18 प्रो की कीमत 1.70 लाख रुपये तक हो सकती है

प्रथम पृष्ठ से आगे

6.90 इंच डिस्प्ले वाले आइफोन 18 प्रो की कीमत 1.70 लाख रुपये तक हो सकती है। इसका फ्रंट कैमरा 18 और रियल कैमरा 48 मेगा पिक्सल का है, 12 जीबी रैम वाले फोन की स्टोरेज क्षमता 256 जीबी है। वहीं आइफोन 18 प्रो मैक्स में 6.30 इंच का डिस्प्ले है। कार्यक्रम की शुरुआत सीईओ टर्नस ने की और यह कुक के क्लोज अप से खत्म हुआ। इसी समय कुक ने टर्नस से कहा,'मैं नहीं यह काम आपका है।' टर्नस ने कहा, दूसरे लोग पर्सनल डेटा एकत्र व स्टोर करना चाहते हैं। कहा, "सच कहूं तो, भरोसा तभी तक काम आता है जब आपका डेटा आपके कंट्रोल में न हो। इसीलिए एपल इंटेलिजेंस डिवाइस पर ही चलता है।

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

लोकशाहीतील बहुमताची हुकूमशाही !

'बहुमतखोरीचा बळी' हा अग्रलेख (९ सप्टेंबर) वाचला. १९४७ पूर्वी ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली असलेला आपला भारत देश परकीय राजवटीत हालअपेष्टा सहन करून आता कुठे स्वातंत्र्य उपभोगत आहे असे वाटत असतानाच सध्या स्वकियांनीच बहुमताच्या नावाखाली वेठीस धरला आहे. लोकशाहीत चुकीच्या गोष्टींविरुद्ध आवाज उठवणे वाटते तितके सोपे राहिलेले नाही हेच गेल्या काही दिवसांत घडणाऱ्या घटनांतून स्पष्ट होते. आपल्याला जे पाहिजे तेच आणि तसेच झाले पाहिजे ही बहुमतातील लोकांची पाशवी मानसिकता होत चालली आहे. योग्य-अयोग्य काय याचा विचार न करता मुद्द्यांची लढाई गुद्द्यांवर आली आहे. बळाचा वापर करून असुरी विजयोत्सव साजरा करण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली आहे. सार्वजनिक उत्सव ही एका विशिष्ट काळातील गरज होती, त्यामागील हेतू लक्षात न घेता फक्त आता आपल्याला काय पाहिजे याचा विचार केला जाऊ लागल्यामुळे लोकहित मागे पडले आहे. काळानुसार प्रत्येक गोष्टीत सकारात्मक बदल होणे अपेक्षित असते, मात्र सध्या तरी सारे विपरीतच घडत आहे.

■ **प्रवीण शेलार,** बदलापूर

ही अराजकाची नांदी तर नव्हे ?

'बहुमतखोरीचा बळी' हे संपादकीय वाचले. लोकशाहीत मतमतांतरे अटळ, पण त्यासाठी वैचारिक, आर्थिक व राजकीय धोरणे हा आधार अपेक्षित आहे. गेल्या काही वर्षांत राजकारणात शंकास्पद निवडणूक प्रक्रिया आणि पक्ष फोडणे याद्वारे अनैसर्गिक बहुमत निर्माण केले जात आहे. मग असे बहुमत तयार करताना सामावून घेतलेले भ्रष्ट, गुन्हेगार पार्श्वभूमीचे नेते आणि त्यांचे 'गोंगाटसम्राट' कार्यकर्ते यांना बळ मिळते. दहीहंडी असो की कावडयात्रा यामध्ये भक्ती, धर्म, संस्कृती यापेक्षा अधिक अनुभवला तो गोंगाट आणि हिंसक उपद्रव. जेथे विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह कोसळून काहींचे प्राण गेले त्या शहरात गोंगाट नको म्हणणारे चोंगथम विक्रमसिंह यांना ठेचून मारले. विवेक हरवलेल्या समाजाची अनेक लक्षणे दिसू लागली आहेत. डॉ. दाभोलकर, कॉ. पानसरे, प्रा. कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांच्या हत्यांनंतर बहुमताने उच्छाद मांडला. धार्मिक उत्सव आणि राजकीय विजयोत्सव साजरा करताना गोंगाट, अश्लीलतेचे प्रदर्शन, हिंसा वाढली. पोलीस, न्यायपालिका आणि अनेक माध्यमे जणू काही बहुमताचे मांडलिक झाले आहेत. ही स्थिती अराजकाची नांदी ठरू शकते.

■ **अॅड. वसंत नलावडे,** सातारा

जंतर-मंतरवर झाली, ती हुल्लडबाजी नव्हती ?

'बहुमतखोरीचा बळी' हा अग्रलेख वाचला. अशाच विकृत मानसिकतेचे हुल्लडबाज लोक, हजारोंच्या संख्येने, जंतर-मंतरवरच्या आंदोलनात सामील होतात, हिंसाचार करतात, अश्लाघ्य भाषेत आणि आविर्भावात खुशाल टेलिव्हिजन कॅमेऱ्यासमोर अचकट-विचकट प्रतिक्रिया देतात, पत्रकारांना लक्ष्य करतात, धर्मांध शेरेबाजी करतात आणि इतके होऊनही (गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले वगळता) त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई होत नाही, या वास्तवाकडे 'लोकसत्ता' कसे पाहतो? अथवा पाहण्याचे का टाळतो? जेन-झीचा कौतुक सोहळा काही माध्यमांवर सुरू आहे, तो अविवेकी नाही का? जे जे म्हणून मोदी-विरोधी आहे त्याचे आणि तेवढ्याचेच कौतुक करायचे आणि एकंदर वास्तवाकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करायचे हा प्रकार एकांगी नाही का? आज, नवपिढी अनेक आघाड्यांवर, आंदोलनाच्या राजकारणात न पडता कौतुकास्पद कामगिरी करत आहे. त्यांच्यावर माध्यमांचा प्रकाशझोत नसेल पण हेच तरुण जेन-झीचे अस्सल प्रतिनिधी आहेत. त्यांच्या परिश्रमांतून आणि उपक्रमशीलतेतून उद्याचा भारत घडणार आहे. जयप्रकाश नारायण किंवा अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनांतून पुढे काही जण राजकारणात आले, (उदा.- लालूप्रसाद यादव आणि केजरीवाल) त्यांनी पुढे काय दिवे लावले, ते आपण पाहिलेच आहे. त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती होणार असेल तर त्याला कोण काय करणार?

■ **पी. डी. करंदीकर,** निवृत्त आयएएस अधिकारी, पुणे

लोकशाही संस्कारांची घसरण

'बहुमतखोरीचा बळी' हा अग्रलेख वाचला. देशात आज क्षुल्लक कारणावरून माणसांच्या अंगावर धावून जाण्याची प्रवृत्ती वाढत आहे. एखाद्याने काही सल्ला दिला, प्रश्न विचारला, जाब मागितला किंवा साधी असहमती दर्शवली तरीही अनेकांचा अहंकार दुखावतो. मग चर्चेची जागा शिवीगाळ घेते, शिवीगाळीची जागा धमकी घेते आणि शेवटी तिचे रूपांतर जमावाच्या हिंसेत होते. हा केवळ संताप नाही; तर ही लोकशाहीच्या संस्कारांची घसरण आहे. मतभेद हे लोकशाहीचे सौंदर्य आहे. प्रतिवाद करा, तर्क मांडा, चर्चा करा, पण कायदा हातात घेऊन एखाद्याला मारहाण करणे आपल्या युक्तिवादाचा पराभव मान्य करण्यासारखे आहे. दुर्दैवाने आज जमावाच्या बळावर आपले म्हणणे लादण्याची मानसिकता वाढत आहे, अशा वेळी प्रश्न फक्त एखाद्या कार्यकर्त्याचा, पत्रकाराचा किंवा कलाकाराचा राहत नाही. प्रश्न सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा असतो. उद्या एखाद्याने रस्त्यावर प्रश्न विचारला वा समाजमाध्यमावर मत व्यक्त केले किंवा एखाद्या निर्णयाला विरोध केला म्हणून त्याच्यावर जमाव चालून जाणार असेल तर सामान्य माणसाने जगायचे कसे? हिंसेला कारण कोणतेही असो, तिचे समर्थन मात्र होऊच शकत नाही.

■ **दिलीप कदम,** कांदिवली (मुंबई)

एमपीएससीद्वारे परीक्षा हाच पर्याय

'पारदर्शक भरतीआधी शैक्षणिक परिस्थिती जाणून घ्या!' हा प्रा. डॉ. सुधाकर शेलार यांचा लेख (९ सप्टेंबर) वाचला. एमपीएससीद्वारे परीक्षा घेतल्याशिवाय पारदर्शक प्राध्यापक भरती होऊच शकत नाही. प्राध्यापक भरतीचे जे अन्य मार्ग आहेत त्यांत पळवाटा निर्माण होऊ शकतात तसेच आर्थिक 'देवाणघेवाण' होऊन प्राध्यापक भरतीवर श्रीमंतांचीच मक्तेदारी निर्माण होऊ शकते. तसे झाल्यास समान संधीच्या तत्त्वाचा लोप होईल. त्यामुळे एखादा गरीब घरातील होतकरू तरुण पात्र असूनही त्याला संधी मिळणार नाही. तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांना या भरतीचा लाभ व्हावा ही मागणी रास्त आहे. आजच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाविद्यालयीन स्तरावरील सर्व कर्मचारी मेहनत घेत आहेत. अशातच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापक अनेक समस्यांनी भरडला जात आहे. त्याला त्याच्या कामाचा योग्य मोबदला दिला जात नाही. सरकार अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या समजून घेते, लाडक्या बहिणींना न मागता पैसे देते, मग तासिका तत्त्वावरील सहायक प्राध्यापकांकडे का दुर्लक्ष करते?

■ **प्रा. आदित्य भांगे,** नांदेड

'झाओ' नव्हे 'चाओ'

'डोकलाम-गलवानचे कमांडर झाओ झोंगकी यांना चीनने का हटवले?' हे विश्लेषण (९ सप्टेंबर) वाचले. मी चिनी भाषेचा अभ्यासक आहे. General Zhao Zongq यांच्या नावाचा उच्चार लेखामध्ये झाओ झोंगकी असा केला आहे. तो युरोपीय लोकांनी, त्यांना मूळ चिनी उच्चार जमत नसल्यामुळे, रोमन लिपीमध्ये फिनयीन पद्धतीप्रमाणे वेगळीच व्यंजने वापरून कृत्रिमरीत्या तयार केलेला उच्चार आहे. तो आपण का वापरावा? त्या शब्दांचा अस्सल चिनी उच्चार 'चाओ' ('चंद्रा'चा 'च' म्हणून zh) चोंगछी ('चामड्या'चा 'च' म्हणून z व अगदी q हा मृदु 'छ' - 'छत्री'तला 'छ' नव्हे) असा आहे. Xiला 'क्षी' म्हणणे आहेच- जो खरा 'षी' आहे ('शी' पण नव्हे). यातील प्रत्येक शब्दाला चिनी संस्कृतीत काही अर्थ आहे. त्यामुळे त्यांचे लेखन अचूक करणे अतिशय आवश्यक आहे.

■ **इन्द्रनील भोळे**

सुरक्षेची माहिती दर्शनी भागात हवी

''सत्य निकेतन'च्या ढिगाऱ्यामागील वास्तव' या लेखात (९ सप्टेंबर) वैभव खरात यांनी व्यवस्थेतील अव्यवस्थेवर प्रकाश टाकला आहे. दुर्घटना घडून जातात आणि यंत्रणा फक्त वरवरची मलमपट्टी करून शांत बसतात. झालेल्या दुर्घटनांपासून काही धडा शिकण्याची आवश्यकता कुठल्याच यंत्रणेला भासत नाही. 'सर सलामत तो डिग्री/ परीक्षा पचास' हे ध्यानात ठेवून विद्यार्थ्यांनीदेखील आपले राहण्याचे ठिकाण निवडताना सुरक्षिततेला अधिक प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. स्थानिक प्रशासनावर याची सर्वांत मोठी जबाबदारी आहे. संरचनात्मक परीक्षण, सुरक्षाविषयक मंजुऱ्या, आपत्काळात बाहेर पडण्याचा मार्ग इत्यादी माहिती इमारतीच्या दर्शनी भागात उपलब्ध करून देणे इमारत मालकांवर बंधनकारक करावे. त्यामुळे निवासस्थान निवडणे विद्यार्थ्यांना सुलभ होईल.

■ **सावळाराम मोरे,** नालासोपारा

बॉलीवूडमधील मुस्लिमांची प्रतिमा का बदलली?

समाजात दुभंगलेपण निर्माण करणारे साचेबद्ध सिनेमे व्यावसायिक नफा किंवा राजकीय लाभ देत असले, तरी ते सिनेमाला एका बोथट हत्याराचे स्वरूप देतात...

हरीश एस. वानखेडे
'जेएनयू'तील सहयोगी प्राध्यापक
enarish@gmail.com

सिनेकारण

हिंदी चित्रपटसृष्टीची लोकप्रियता समजून घ्यायची असेल, तर त्यात मुस्लीम कलाकारांच्या अफाट योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. शाहरुख खानपासून सोहा अली खानपर्यंतचे अभिनेते, इम्तियाज अलीसारखे दिग्दर्शक, जावेद अख्तरांपासून ए. आर. रहमान यांच्यापर्यंतचे गीतकार- संगीतकार आणि फरहान अख्तरसारखे निर्माते या सर्वांनी या उद्योगाला समृद्ध केले आहे. आधुनिक धर्मनिरपेक्ष संस्थांमध्ये, मुंबईच्या चित्रपटसृष्टीने मुस्लीम ओळख घडवण्यास एक महत्त्वपूर्ण आणि प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. चित्रपटसृष्टीच्या सुरुवातीपासूनच मुस्लीम विचारवंत, कलाकार आणि निर्मात्यांनी या व्यवसायाला आणि त्याच्या कलामूल्यांना जोपासण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. यामुळे या समुदायाला त्यांच्या सामाजिक- राजकीय संकटांवर आणि आकांक्षांवर चित्रपटामधून आत्मपरीक्षण करण्याची संधी मिळाली.

ऐतिहासिकदृष्ट्या, मुख्य प्रवाहातील लोकप्रिय चित्रपट त्याच्या सर्वसमावेशक, लोकशाहीवादी मूल्यांसाठी ओळखले जात असत. त्यांनी मुस्लीम प्रश्नांना बारकाईने आणि सुसंस्कृतपणे हाताळले, समभावाचे विविध पैलू आणि पात्रे प्रेक्षकांसमोर आणली. परंतु गेल्या दोन दशकांत यामध्ये एक चिंताजनक बदल झाला. लोकप्रिय चित्रपटसृष्टी हळूहळू हिंदुत्ववादी राजकीय विचारसरणीच्या प्रभावाखाली आली. त्यामुळे मुस्लिमांना गुन्हेगार, दहशतवादी वा हिंसक प्रवृत्तीचे म्हणून रंगवणाऱ्या संकुचित कथांचे प्रमाण वाढले आहे. हे चित्रण पूर्वीपेक्षा पूर्णपणे वेगळे आहे, जिथे मुस्लिमांना सहृदय व्यक्ती म्हणून दाखवले जात असे. या पार्श्वभूमीवर आशेचा किरणही दिसतो. इम्तियाज अली यांच्या नुकत्याच आलेल्या 'मैं वापस आऊंगा'ला मिळालेले व्यावसायिक यश आणि मिळालेली दाद या चौकटीला छेद देणारी आहे. यामुळे बॉलीवूडची धर्मनिरपेक्ष ओळख पुन्हा एकदा पुनरुज्जीवित होईल व अशा राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देईल, असा विश्वास निर्माण होतो.

मुघलकालीन वैभव ते शहरी वास्तव्य

हिंदी चित्रपटसृष्टीत मुस्लीम पात्रांना नेहमीच विविध जॉनर्सच्या (genres) माध्यमातून स्थान मिळाले आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात, 'बैजू बावरा', 'अनारकली' आणि 'मुगल-ए-आझम' यांसारख्या 'ऐतिहासिक' किंवा 'कॉस्च्युम ड्रामा' चित्रपटांनी मुघल साम्राज्याची भव्यता आणि मुस्लीम राजवटीचे वैभव मोठ्या पडद्यावर आणले. या चित्रपटांनी भारताच्या सांस्कृतिक वारशात इस्लामी संस्कृतीचे योगदान, तेथली समृद्ध वस्त्रभूषा, दागिने, शायरी, कव्वाली आणि सौंदर्यशास्त्र सादर केले. याद्वारे मुस्लिमांनी स्वतःला भारतीय इतिहासाचा एक अभिमानास्पद आणि अविभाज्य भाग म्हणून लोकांसमोर उभे केले. या सादरीकरणामुळेच हिंदी चित्रपट एक धर्मनिरपेक्ष आणि सर्वसमावेशक कलाप्रकार ठरू शकला.

दुसऱ्या बाजूला, मुस्लीम चित्रपट निर्मात्यांनी सिनेमात सामाजिक वास्तववाद आणण्यासाठी आणि समाजवादी मूल्यांचा प्रसार करण्यासाठी

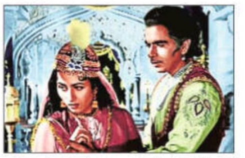

पुढाकार घेतला (मेहबूब खान यांचा 'मदर इंडिया' किंवा ख्वाजा अहमद अब्बास यांचा 'शहर और सपने' हे चित्रपट आठवून पाहा). याच काळात, शहरी भागातील बदलत्या सामाजिक- राजकीय परिस्थितीत मुस्लीम समुदायाला भेडसावणाऱ्या चिंतांवरही संवेदनशीलपणे भाष्य करण्यात आले.

१९७०-८० च्या दशकात शहरी कामगार वर्गातील मुस्लिमांच्या संघर्षाची गाथा चित्रपटांतून मांडली गेली. उदाहरणार्थ, 'गरम हवा' या चित्रपटाने फाळणीनंतरच्या काळात मुस्लिमांना सुरक्षितता देण्यास अपयशी ठरलेले राज्यकर्ते, वाढते आर्थिक अधःपतन आणि सामाजिक विभाजनाची वास्तव मांडणी केली. 'गमन' या चित्रपटाने शहरी भागात स्थलांतरित कामगारांचे जगणे किती हलाखीचे असते, हे दाखवले; तर 'सलीम लंगडे पे मत रो' या चित्रपटाने मुंबईतील कामगारांचे सांप्रदायिकीकरण चव्हाट्यावर आणले. अशा चित्रपटांनी मुस्लिमांना केवळ 'ऐतिहासिक नाटकांच्या' चौकटीत न ठेवता, विस्थापित झालेले, आर्थिक संकटात सापडलेले आणि अलिप्ततेच्या भावनेशी संघर्ष करणारे एक क्लिष्ट वास्तव म्हणून प्रेक्षकांसमोर आणले.

तसेच 'उमराव जान', 'निकाह' आणि 'बाजार' यांसारख्या चित्रपटांनी मुस्लीम समाजातील पुरुषसत्ताक व्यवस्थेवर कडाडून टीका केली. महिलांची दयनीय स्थिती आणि त्यांचे दैनंदिन जीवन यावर या चित्रपटांनी प्रकाश टाकला. जरी या दशकांवर व्यावसायिक समीकरणे आणि स्टार संस्कृतीचे वर्चस्व असले, तरी पडद्यावर दिसणारी मुस्लीम पात्रे विविधता जपणारी आणि जातीय-सांप्रदायिक पूर्वग्रहांपासून दूर राहिली. मात्र, १९८० च्या दशकापर्यंत मुस्लीम पात्रांना हळूहळू कथेच्या परिघावर ढकलले गेले. कधी त्यांना एक निष्ठावान मित्र म्हणून, तर कधी 'जंजीर' चित्रपटातील प्राणच्या भूमिकेसारख्या 'पठाण' या साचेबद्ध पात्रापुरतेच मर्यादित ठेवले गेले.

नवीन सिनेमातील खलनायकीकरण

भारतीय राजकारणात १९९० च्या दशकाची सुरुवात होताना मोठे बदल झाले. बाबरी मशीद विध्वंसानंतर निर्माण झालेला तणाव आणि हिंदूंमधील धार्मिक चिंता या पार्श्वभूमीवर हिंदी चित्रपटांनी एक स्पष्ट हिंदू-मुस्लीम असा दुजाभाव

करण्यास सुरुवात केली. जनमानसाला एकत्र आणण्यासाठी हिंदुत्ववादी अजेंडा राजकीय पातळीवर स्वीकारला जाऊ लागला आणि त्याचा थेट प्रभाव हिंदी चित्रपटसृष्टीवरही पडला. उजव्या विचारसरणीच्या राजकीय प्रचाराला पूरक ठरणाऱ्या अनेक कथा बॉलीवूडमध्ये येऊ लागल्या.

जरी १९९० आणि २००० च्या दशकात 'बॉम्बे', 'नसीम', 'जख्म', 'फिझा' आणि 'परजानिया' यांसारख्या संवेदनशील चित्रपटांनी जातीय दंगलींच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी हळूहळू या संवेदनशील प्रतिमेची जागा एका नवीन प्रकारच्या सिनेमाने घेतली. या नवीन सिनेमात मुस्लिमांना गुन्हेगार किंवा दहशतवादी म्हणून उघडपणे रंगवण्यात आले. मुस्लीम पुरुषांना पडद्यावर रूढीवादी पुरुषप्रधान वृत्तीचे ('पिंजर'), मुंबईचे अंडरवर्ल्ड गँगस्टर ('कंपनी') किंवा दहशतवादी ('सरफरोश', 'दिल से') म्हणून सातत्याने खलनायक ठरवले जाऊ लागले. परिणामी लोकांच्या मनातील जातीय भीती आणि सांप्रदायिक पूर्वग्रह बळकट होऊन एक साचेबद्ध मुस्लीम प्रतिमा तयार होऊ लागली. अगदी धर्मनिरपेक्ष विचार मांडणारे चित्रपटही शेवटी दंगली, जातीय दुजाभाव आणि पाकिस्तानविरोधी विखाराभोवतीच फिरताना दिसले (उदा. 'गदर : एक प्रेम कथा'). असे सादरीकरण एकच गोष्ट साधते ती म्हणजे- वाढत्या हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या दबावाखाली येऊन मुस्लीम पात्रांच्या आणि त्यांच्या कथांच्या कक्षा संकुचित करणे. दुर्दैवाने, या प्रवाहात मुस्लिमांचे सामाजिक प्रश्न, वर्गसंघर्ष आणि आर्थिक आकांक्षांवर नीट भाष्य केले गेले नाही.

गेल्या एका दशकात हा ट्रेंड वेगाने वाढला. हिंदुत्ववादी विचारसरणीची वाढती सांस्कृतिक हुकूमशाही आणि राजकीय वर्चस्व यामुळे हिंदी चित्रपटसृष्टीचे लोकशाहीवादी आणि चिकित्सक तेज झाकोळले गेले आहे. चित्रपटसृष्टी आता सत्ताधाऱ्यांच्या राजकीय हितसंबंधांची पूर्तता करणारे माध्यम झाले आहे. यामध्ये ऐतिहासिक महाकाव्ये ('पद्मावत'), अॅक्शन ब्लॉकबस्टर ('धुरंधर') आणि 'द कश्मीर फाइल्स'सारख्या डॉक्यु-ड्रामांचा समावेश आहे. या माध्यमातून मुस्लीम ओळखीला आक्रमक, पुरुषप्रधान, रानटी किंवा दहशतवाद्यांशी जोडले जात आहे. एके काळी हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या धर्मनिरपेक्षतेची साक्ष देणारी रचना आता नाहीशी झाली आहे. त्याऐवजी हिंदुत्ववादी राजकारणाच्या राजकीय हितसंबंधांना खतपाणी घालणाऱ्या कथांनी संपूर्ण अवकाश व्यापून टाकला आहे.

भविष्याचा मार्ग आणि नैतिक जबाबदारी

आज सामाजिक सलोखा आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या मूल्यांवर प्रकाश टाकणाऱ्या प्रभावी कथांचा दुष्काळ पडला आहे. हिंदुत्ववादी विचारसरणीचा प्रभाव आणि व्यावसायिक नफा मिळवण्याची लालसा यामुळे बॉलीवूड आज केवळ राजकीय प्रचाराचे एक साधन झाले आहे आणि त्याची सर्जनशील कलात्मक ओळख मागे पडली आहे. उत्तम चित्रपटाची खरी ताकद केवळ करमणूक करण्यात किंवा सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय हत्यार होण्यात नसते, तर पूर्वग्रहांना आव्हान देण्याची, अन्यायाला प्रश्न विचारण्याची आणि मानवी सहानुभूती वाढीस लावण्याची कलात्मक आणि नैतिक धमक दाखवण्यात असते. म्हणूनच, आजच्या या हिंदुत्ववादी सांस्कृतिक प्रभावाच्या काळात 'मैं वापस आऊंगा' या चित्रपटाचे यश मनाला उभारी देणारे, एक सुखावणारे अपवाद ठरते.

समाजात दुभंगलेपण निर्माण करणारे आणि विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य करणारे साचेबद्ध सिनेमे जरी तात्पुरता व्यावसायिक नफा किंवा राजकीय लाभ मिळवून देत असले, तरी ते सिनेमाला एखाद्या बोथट हत्याराचे स्वरूप देतात. हिंदी चित्रपटाला आपला समृद्ध, सर्जनशील आणि सर्वसमावेशक वारसा पुन्हा प्राप्त करायचा असेल, तर त्याला विभाजनाच्या सोप्या राजकारणापलीकडे जावे लागेल आणि सुसंस्कृतपणे कथा सांगण्याचे धाडस पुन्हा एकदा दाखवावे लागेल. केवळ करमणुकीच्या पलीकडे जाऊन मानवी मूल्यांची जपणूक करणारा जबाबदार सिनेमा हीच आजच्या काळाची सर्वांत मोठी गरज आहे.

कुतूहल

फ्रिजमध्ये अन्न का टिकतं?

फ्रिजमध्ये ठेवलेलं अन्न दीर्घकाळ टिकतं, म्हणजेच लवकर खराब होत नाही. खरं तर फ्रिजमुळे अन्न खराब होण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे थांबत नाही तर फक्त तिचा वेग मंदावतो.

अन्न खराब होण्यासाठी मुख्यत्वे तीन प्रकारचे सूक्ष्मजीव कारणीभूत असतात; जिवाणू, बुरशी आणि यीस्ट. ते आपल्या वातावरणात, हवेत व अन्नावर अस्तित्वात असतात. तापमान ४० ते ६० अंश सेल्सियसच्या दरम्यान असतं, तेव्हा जिवाणूंची संख्या दर २० मिनिटांनी दुप्पट होऊ शकते.

आपण अन्न फ्रिजमध्ये ठेवतो तेव्हा तिथलं तापमान सामान्यतः १ ते ४ अंश सेल्सियसच्या दरम्यान असतं. इतक्या कमी तापमानात सूक्ष्मजीवांची चयापचय क्रिया आणि पुनरुत्पादनाची क्षमता जवळजवळ गोठून जाते. ते सुप्त अवस्थेत जातात. त्यामुळे अन्न खराब होण्याची प्रक्रिया खूप लांबते.

अन्नामध्ये स्वतःचे काही नैसर्गिक घटकही असतात, ज्यांना एन्झाईम्स म्हणजे विकरं म्हणतात. ही विकरं फळं आणि भाज्या पिकवण्यासाठी आणि त्यांना मऊ करण्यासाठी कारणीभूत असतात. वनस्पती जमिनीतून काढल्यानंतरही किंवा फळ झाडावरून तोडल्यानंतरही ही विकरांची प्रक्रिया सुरूच राहते. त्यामुळे ठरावीक काळानंतर फळं अति पिकतात, काळी पडतात किंवा कुजतात.

विज्ञानाच्या नियमानुसार, तापमान कमी केल्यास रासायनिक अभिक्रियांचा वेग मंदावतो. फ्रिजमधील थंड वातावरण या विकरांची कार्यक्षमता अत्यंत कमी करतं. त्यामुळे भाज्यांचा ताजेपणा, त्यांचा रंग आणि कडकपणा जास्त काळ टिकून राहतो.

अन्नामध्ये असलेल्या पाण्याच्या प्रमाणामुळे जिवाणू आणि बुरशीला वाढण्यास मदत होते. आधुनिक फ्रिजमध्ये आर्द्रता नियंत्रित करण्याची यंत्रणा असते. फ्रिजमधली थंड आणि कोरडी हवा, अन्नावरचा अतिरिक्त ओलावा शोषून घेते, ज्यामुळे बुरशी वाढण्यासाठी आवश्यक ओलसर वातावरण मिळत नाही.

जेव्हा आपण अन्न फ्रिजरमध्ये म्हणजेच -१८ अंश सेल्सियसच्या किंवा त्याहून कमी तापमानाला ठेवतो, तेव्हा या तापमानात अन्नामध्ये असलेल्या पाण्याचं बर्फात रूपांतर होतं. सूक्ष्मजीवांना जिवंत राहण्यासाठी आणि वाढण्यासाठी द्रव रूपातील पाण्याची अत्यंत गरज असते. पाणी बर्फ झाल्यामुळे सूक्ष्मजीवांना ते उपलब्ध होत नाही, परिणामी त्यांची वाढ संपूर्णपणे थांबते. यामुळे फ्रिजरमध्ये ठेवलेलं अन्न कित्येक महिने सुरक्षित राहू शकतं.

फ्रिजमध्ये जरी अन्न सुरक्षित राहत असलं तरी 'लिस्टेरिया मोनोसायटोजिन्स'सारखे काही जिवाणू हे अगदी फ्रिजमधल्या कमी तापमानातही हळूहळू वाढू शकतात. म्हणूनच फ्रिजमध्ये ठेवलेलं अन्नही अनंत काळासाठी टिकू शकत नाही, तर त्यालाही एक कालमर्यादा असते.

-डॉ. अरुंधती जोशी
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

उलटा चष्मा

नवरात्रीत मांस-मासे हवेच!

__नवरात्रात मांसाहार__ नको या मागणीला प्रतिसाद म्हणून मोबाइलमधील टॉर्च सुरू करा असे आवाहन केले, पण फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. हरकत नाही, हळूहळू येतील सारे वठणीवर. दीदी नावाचा अडसर तर दूर झाला. आता बंगालींना आपल्या विचाराच्या मागे येण्याशिवाय पर्यायच काय, असा विचार करत बागेश्वर बाबा कोलकाता विमानतळाकडे निघाले. त्यांच्यासोबत बसलेले भाजपचे दोन नेते रागाने बघत असल्याचा भास बाबांना झाला, पण त्यांनी दुर्लक्ष केले. काहीही झाले तरी दहा वर्षांत देशाला शाकाहारी करायचेच असा निर्धार त्यांनी मनातल्या मनात पुन्हा एकदा केला.

तेवढ्यात एका नेत्याने फोनवरून देवीसाठी नैवेद्य म्हणून लागणाऱ्या बकऱ्यांची खरेदी कुठून करावी याच्या सूचना कार्यकर्त्यांना देण्यास सुरुवात केली. सगळ्यात चांगले बकरे मिदनापूरला मिळतात. तिथून दोन ट्रक भरून घेऊन या. यावेळची 'पाठाबोली' (नैवेद्यासाठी लसूण कांद्याशिवाय शिजवलेला बकरा) धडाक्यात व्हायला हवी अशी सूचना ते देत होते. ऐकून बाबांनी नाकाला रुमाल लावला. मग दुसऱ्या नेत्याचे फोन सुरू झाले. त्यांनी थेट बांगलादेशातील मासोळी व्यापाऱ्याशीच बोलणे सुरू केले. यंदा दहा हजार मंडपात पद्मा (भारतात गंगा) नदीत मिळणारा 'इलीश' मासा वाटायचा आहे. चार ट्रक पाठवा. या वेळी 'जोडाइलीश' (दोन मासे)चा नैवेद्य कमी पडू द्यायचा नाही. देवीच्या कृपेने आपली सत्ता आली आहे असे ते मोठ्याने सांगत होते.

ऐकून बाबांना मळमळू लागले. इतर राज्यांतील भाजपचे लोक आपण म्हणू तसे वागतात. पायावर लोटांगण घालतात. आवाहनानंतर क्षणात मांसाहार सोडतात. हे बंगाली नेते आपल्यालाच आव्हान द्यायला लागले. आता या दोघांचीही तक्रार दिल्लीला करायचीच. अगदी विमानतळावर उतरल्याबरोबर. समजतात काय हे स्वतःला. बाबांना संताप अनावर होऊ लागला. तरीही त्यांनी संयम बाळगला. हे बघा, आपल्याला एक देश, एक संस्कृती, एक विचार, एक आहार, एक धर्म, एक नेता यावर काम करायचे आहे. माझे येथे येण्याचे प्रयोजन हेच होते. तरीही तुम्ही माझ्याच समोर उघडपणे मांसाहाराचे समर्थन करत आहात. हा केवळ माझाच नाही तर परिवाराने ठरवलेल्या धोरणाचा अपमान आहे असे बाबांनी त्या दोघांना सुनावले, पण त्यांच्याना काडीचाही फरक पडला नाही. ते खरेदीच्या सूचना देण्यात व्यग्र होते. हे बघून बाबांचा आणखी तिळपापड झाला.

विमानतळ येताच तिरमिरीतच ते वाहनातून उतरले. ऑस्ट्रेलियावरून घेतलेली महागडी सुटकेस स्वतःच्या हाताने बाहेर काढल्यावर त्यांनी 'बाय' म्हणण्यासाठी वाहनाकडे बघितले तर दोन्ही नेत्यांनी 'बंगाली संस्कृती जिंदाबाद' म्हणत त्यांचा निरोप घेतला. हा तर आपला अपमानच असे पुटपुटत ते विमानात बसले. मध्य प्रदेशातील धाममध्ये परतल्याबरोबर त्यांना दिल्लीहून निरोप मिळाला. कोलकात्यात जे तुमच्याबाबतीत घडले त्याकडे दुर्लक्ष करा. आपले ध्येय दीर्घकालीन आहे. तुमच्या दौऱ्यामुळे बंगालमध्ये विकासाचा मुद्दा मागे पडून खानपानावर चर्चा सुरू झाली. हीच आपल्या धोरणात्मक यशाची सुरुवात. आता तुम्हाला ज्या राज्यात पाठवायचे आहे तेथील मांसाहारी खाद्य कोणते याची यादी पाठवत आहोत. तिथेही असेच बोलायचे. निरोप ऐकून बाबांचा राग थोडा शांत झाला.

राजवाडे विचारविश्व

स्वस्त्रीसमर्पणाच्या चालीतील बदल

'गृहस्थधर्माच्या पालनासाठी आपली पत्नी घरी आलेल्या अनोळखी अतिथीलाही उपभोगार्थ देण्याच्या सत्कृत्यामुळे सुदर्शनाची कीर्ती भुवनत्रयात अक्षय्य पसरली व त्याला इंद्रलोक प्राप्त झाला, असे पितामह भीष्मांनी धर्मराजाला सांगितलेले (महा)भारतात आढळते', हे जसे राजवाड्यांनी सांगितले, तसेच त्यांनी त्याच महाग्रंथाच्याच हवाल्याने 'अतिथीला स्वस्त्रीसमर्पण करण्याच्या चालीला पुढे आस्ते आस्ते आळा पडल्याचे' नमूद केले. त्याबद्दलचा खुलासा करताना त्यांनी लिहिले, 'शांतिपर्वाच्या २६६व्या अध्यायामध्ये भीष्मांनी युधिष्ठिराला सांगितलेली चिरकारीची कथा पाहावी. चिरकारीचा पिता गौतम अन्यत्र गुंतला असता इंद्र गौतमाश्रमात अतिथी म्हणून आला आणि चिरकारीच्या मातेचा उपभोग घेऊन चालता झाला. हे वृत्त गौतमास कळल्यावर त्याने चिरकारीस आपल्या मातेचा वध करण्यास पहिल्या झटक्यासरशी सांगितले व स्वतः रागाने अरण्याचा रस्ता धरला. इकडे मातेचा वध न करता चिरकारी तसाच बसून राहिला. अरण्यात राग शांत झाल्यावर गौतमाला स्वस्त्रीचा पुत्राने वध केला असेल या निश्चितीने फार वाईट वाटले. अतिथीसमागमाच्या असल्या अस्पष्ट अपराधाकरिता स्त्रीचा वध करणे अधर्म्य होय, असे वाटून, पश्चात्ताप होऊन तो घरी परतला. पुत्राने स्त्रीस ठार मारिले नाही असे पाहून त्या ऋषीने चिरकारीची प्रशंसा केली...'

ही कथा सांगून सुदर्शनाच्या व गौतमाच्या कथांची तुलना करीत राजवाड्यांनी भाष्य केले. 'सुदर्शन व गौतम दोघेही अतिथीला स्वस्त्रीसमर्पण करणे हा धर्म समजत होते. ह्या धर्माने सुदर्शनाला कृतकृत्यता वाटली तर गौतमाला पहिल्या झटक्याला क्रोध आला, विचारांती स्वस्त्रीने अतिथिधर्म पाळण्यात जे केले, ते धर्म्यच केले, असे त्याला वाटले. याचा अर्थ इतकाच की, ही अतिथिपूजनाची चाल समाजात किंचित गर्हणीय समजली जाऊ लागली होती, पण तिचा पगडा व्हावा तितका शिथिल झाला नव्हता'...

या चालीच्या उत्क्रांतीतील पुढची पायरी म्हणजे अतिथीला स्त्रीसमर्पण न करण्याची. ह्या पायरीचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून राजवाड्यांनी सर्वप्रसिद्ध जमदग्नीची कथा उद्धृत केली. त्यांनी लिहिले, 'रेणुका या जमदग्नीच्या बायकोने चित्ररथ गंधर्वाकडे नुसते सकामदृष्टीने पाहिले, तेणेकरून कोपाविष्ट होऊन जमदग्नीने आपला मुलगा परशुराम याजकडून तिला ठार केले. मानसिक व्यभिचारही ज्याला खपला नाही, त्या जमदग्नीने अतिथीला स्वस्त्रीसमर्पण कितपत सहन केले असते, ते वेगळे सांगायला नको. सुदर्शनाच्या कथेत अतिथीला उपभोग देणे हे दोघा नवराबायकोंना संमत होते; गौतमाच्या कथेत स्वस्त्रीदान नवऱ्याला पसंत नव्हते, परंतु बायकोला व मुलाला पसंत होते; परशुरामाच्या कथेत मात्र बापाला व मुलाला स्वस्त्रीसमर्पण नापसंत होते.'

या चालीबद्दचे विवेचन आटोपते घेताना राजवाड्यांनी पुढील पायरीचा ओझरता उल्लेख केला. 'ती पायरी राम व सीता यांची. रावण अतिथीचा वेश घेऊन सीतेपुढे आला व तिला तिच्या इच्छेविरुद्ध बळजबरीने घेऊन पळाला. अतिथीला स्वशरीर समर्पण करण्याची चाल जर सीतेला मान्य असती, तर रामायणाचा पुढील कथाभाग घडलाच नसता. रामाला व लक्ष्मणाला आणि तत्कालीन तमाम भारतीय समाजाला स्त्रीसमर्पणाची ही चाल बरीच गर्हणीय वाटू लागली होती, हे स्पष्ट आहे.'

यानंतर राजवाड्यांनी 'ती' चाल अस्तित्वात येण्यामागची कारणे स्पष्ट केली. त्यांनी लिहिले, 'प्राचीन काळी गाई, बैल, घर इत्यादींप्रमाणेच स्त्रीचा जिनगीत समावेश होत असे. स्त्री हा जिन्नस मालकीचा समजला गेल्यावर तिला मित्रास किंवा पाहुण्यांस उपभोगार्थ देऊन टाकण्याचा अधिकार सहजच उत्पन्न होतो... स्त्रियांवर पुरुषांची मालकी केव्हा उत्पन्न झाली? तर मनुष्य हा पशुकोटीतील प्राणी आहे व त्याचे अगदी जवळचे सगेसोयरे पशू म्हटले म्हणजे वानर होत. वानरांतील हुप्या इतर लहानमोठ्या वानरांना मारून किंवा हाकलून कळपातील सर्व माद्यांवर प्रजापतित्वाचा हक्क बजावतो म्हणजे हुप्या बहुपत्नीक असतो. पाशवदशेत माणूसही बहुपत्नीक असावा, तो टोळ्या करून राहू लागल्यावर बहुपत्नीकत्व आणि बहुपतित्व टोळ्यांत उत्पन्न झाले असावे, असे उपमानप्रमाणाने म्हणावे लागते'...

- आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

नरसंहाऱ्यास नकार!

युरोपातील देशांनी आता इस्रायलव्याप्त झालेल्या प्रदेशाशी व्यापार रोखला, ब्रिटिश परराष्ट्रमंत्र्यांनी तर 'वंशविच्छेद' असे इस्रायली वर्तनाचे वर्णन केले...

इंग्लंड, फ्रान्स, कॅनडा आणि अन्य नऊ देशांचे मनःपूर्वक अभिनंदन. इस्रायल ज्या रीतीने पॅलेस्टिनी भूमी गिळंकृत करत आहे आणि ज्या गतीने गाझा, पश्चिम किनारपट्टी- वेस्ट बँक- परिसरातील नागरिकांचे जीव घेत आहे ते पाहता इस्रायलची कृती हा शुद्ध 'वंशविच्छेद' (एथ्निक क्लीन्सिंग) ठरतो अशी स्वच्छ भूमिका या देशांनी घेतली ही सद्यःस्थितीत अत्यंत कौतुकाची बाब. या देश-समूहाचे कौतुक केवळ यासाठी नाही. तर एक पाऊल पुढे जाऊन या देशांनी इस्रायलवर आर्थिक निर्बंध लादण्याची हिंमत दाखवली ही बाब तर कमालीची कौतुकास्पद. इस्रायलचे पंतप्रधान नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या रक्तपिपासू वृत्तीविरोधात कोणी तरी बोलणे गरजेचे होतेच. ती हिंमत या युरोपीय देशांनी दाखवली. यामुळे काही देशांच्या नेतृत्वांत तरी नीरक्षीरविवेकाची क्षमता अजूनही शाबूत आहे हे दिसून आले. अमेरिकेसह अन्य अनेक देश इस्रायलबाबत अत्यंत हीन आणि मानवतेस काळिमा लावणारी भूमिका घेत असताना अथवा नरसंहारी नेतान्याहू यांच्या रक्तपिपासूपणाकडे काणाडोळा करत असताना या डझनभर देशांनी स्वतंत्र विचार करण्याची आपली क्षमता दाखवून दिली. ही बाब विशेष कौतुकाची कारण त्यांनी या मुद्द्यावर अमेरिकेचे बेभरवशी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनाही पार कोलवले. या एकमेव महासत्तेच्या श्रीमुखात ही आणखी एक सणसणीत चपराक. पूर्वसुरींच्या पुण्याईची आत्ममग्न नेतृत्वाकडून कशी माती होते त्याचे हे आणखी एक उदाहरण. युरोपने लाथाडले, चीन हिंग लावून विचारत नाही, रशियाही तोंडास पाने पुसतो आणि आता तर इराणसारखा देशही घायकुतीला आणतो हे आजच्या अमेरिकेचे वास्तव. त्याविषयी नंतर. तूर्त युरोपीय देशांच्या या खणखणीत इस्रायलविरोधी भूमिकेविषयी.

त्याचे श्रेय इंग्लंडचे नवे पंतप्रधान अँडी बर्नम यांस द्यावयास हवे. वास्तविक ते ज्या पक्षाचे आहेत त्याच पक्षाचे सरकार इंग्लंडात होते. तरीही माजी पंतप्रधान किएर स्टार्मर हे इस्रायलविरोधात इतकी खमकी भूमिका घेऊ शकले नाहीत. बर्नम यांनी मात्र ब्रिटिश पार्लमेंटमध्ये इस्रायलच्या पापाचा पाढा वाचावयास कमी केले नाही. ''इस्रायलचे वर्तन द्वि-राष्ट्र सिद्धांताच्या पूर्ण विरोधात असून वेस्ट बँक परिसरात या देशाची घुसखोरी अत्यंत निंदनीय आहे'', अशा प्रकारचे विधान इंग्लंड सरकारच्या वतीने केले गेले. त्यास अधिक धार आणली ती परराष्ट्रमंत्री एड मिलिबँड यांनी. ''आपण इस्रायलविरोधक गणले जाऊ किंवा काय; ही भीती आता सोडायला हवी... इस्रायल हा निःसंशयपणे पॅलेस्टिनींचा वंशविच्छेदच करत आहे'', असे मिलिबँड म्हणाले. इंग्लंडच्या या भूमिकेतून युरोपीय देशांच्या इस्रायलविषयक धोरणाने वेगळे वळण घेतल्याचे स्पष्ट दिसते. इस्रायल स्वतः आपण कसे बळी आहोत हे नाटक करतो आणि त्याच वेळी इतर निरपराधांचे शिरकाण करत राहतो. त्या देशावर 'हमास'ने तीन वर्षांपूर्वी केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करावा तितका थोडा. त्यात हजारभर इस्रायलींचा बळी गेला. तथापि त्यानंतर ज्या पद्धतीने नेतान्याहू यांनी त्या परिसरावर वरवंटा फिरवायला सुरुवात केली त्यात साधारण ७० हजार पॅलेस्टिनी मारले गेले. त्यात ६० टक्के महिला वा बालके आहेत. याची कसलीही खंत वा खेद या नरसंहारी नेतान्याहूंस नाही. त्यात त्यांना अमेरिकेचा असलेला पाठिंबा! खरे तर या महासत्तेने या नरसंहारींस थांबवायला हवे. ती हिंमत आता युरोपीय देश दाखवू लागले असतील तर फार उत्तम. याआधी दक्षिण आफ्रिकेसारख्या देशानेही नरसंहारी नेतान्याहूंविरोधात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितली. पण हाती काही लागले नाही. कारण अर्थातच अमेरिकेचा या नरसंहाऱ्यास असलेला पाठिंबा. हे युद्ध, हा हिंसाचार सुरू ठेवणे ही या नरसंहारी पंतप्रधानाची गरज आहे. याचे कारण हा माणूस

...याची गरज होती. स्वतः आपण कसे बळी आहोत हे सांगतानाच इतर निरपराधांचे शिरकाण करून नेतान्याहू आता या देशांशी राजनैतिक संबंध तोडतील, पण आर्थिक संबंध कसे तोडणार?

भ्रष्टाचारात अडकलेला आहे आणि युद्धजन्य परिस्थिती दूर झाली तर त्यांस शिक्षा होण्याची शक्यता आहे. ही वेळ येऊ नये म्हणून निरपराधांचे शिरकाण करण्यात त्यास काही वाटत नाही.

त्याचमुळे युरोपीय देशांनी त्याविरोधात 'वंशविच्छेद'सारख्या तीव्र शब्दाचा वापर केला. इस्रायलचा निषेध करत त्याविरोधात काही प्रमाणात आर्थिक निर्बंध लादणाऱ्या देशांत इंग्लंड, फ्रान्स, डेन्मार्क, फिनलंड, आयसलँड, आयर्लंड, नॉर्वे, पोलंड, पोर्तुगाल, स्पेन, स्वीडन आणि बिगरयुरोपीय कॅनडा यांचा समावेश आहे. याखेरीज हंगेरीसारख्या देशानेही इस्रायलच्या या हिंसाचाराविरोधात भूमिका घेतलेली आहे. या देशांचे म्हणणे इस्रायलला मान्य नाही, हे ओघाने आलेच. त्यांच्याविरोधात इस्रायलने नेहमीप्रमाणे कांगावखोरी सुरू केली असून आपणच कसे आंतरराष्ट्रीय कटाचे बळी आहोत असा टाहो फोडला आहे. हे नित्याचेच. खरे तर इस्रायलची भूमी मुळात पॅलेस्टिनींची. त्या परिसराचे नावही पॅलेस्टाईन असेच होते. बायबलमध्ये जॉर्डन नदीच्या काठी आपली स्वप्नभूमी असेल, तिथे जगातील सर्व यहुदी धर्मीयांनी यावे अशी मोहीम यहुदी धर्मीयांनी हाती घेतली आणि हलवायाच्या घरावर तुळशीपत्र ठेवावे त्याप्रमाणे ज्यावर आपला हक्क मुळातच नाही अशी भूमी तीवर राज्य करणाऱ्या इंग्रजांनी यहुदींस देऊ केली. अशा रीतीने दुसऱ्या महायुद्धानंतर इंग्लंडच्या अंगावरील महासत्तापदाची झूल उतरल्यानंतर इस्रायलचा जन्म झाला. त्याही वेळी कल्पना ही होती की पॅलेस्टिनी आणि यहुदी शेजारधर्माचे पालन करत त्या परिसरात नांदतील. सुरुवातीस अरबांच्या मूर्खपणाने शांतता कधी नांदली नाही आणि नंतर लबाड इस्रायलने ती कधी नांदू दिली नाही. अमेरिकेच्या महावृक्षावर बांडगुळाप्रमाणे पोसल्या गेलेल्या या देशाने त्या देशाच्या पाठिंब्यावर पॅलेस्टिनींची भूमी बळकावण्याचा चंगच बांधला. अमेरिकेत जेव्हा जेव्हा रिपब्लिकन सत्तेवर आले तेव्हा इस्रायलच्या कृष्णकृत्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले. याचे कारण अमेरिकेत अर्थ, मनोरंजन, वृत्तमाध्यम, उद्योग, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रात असलेले यहुदींचे प्राबल्य. हे यहुदी राहतात अमेरिकेत. पण पत्कर घेतात इस्रायलचा. त्यांची आर्थिक ताकदही भव्य. त्यामुळे स्थानिक राजकारणात ते दबाव गट म्हणून काम करतात आणि इस्रायलविरोधी भूमिका घेणाऱ्यांस नमवू पाहतात.

पण आता त्यांचीही पुण्याई आटू लागल्याचे दिसते. कारण अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जे. डी. व्हान्स यांनीच खुद्द इस्रायलच्या युद्धखोरीविरोधात जाहीर भूमिका घेतली आणि अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इस्रायलानुनय आपणास मान्य नसल्याचे दाखवून दिले. अमेरिकेत आगामी महिन्यात मध्यावधी निवडणुका आहेत. नरसंहारी नेत्यान्याहूंस मिळत असलेली अमेरिकी रसद हा त्यात एक महत्त्वाचा मुद्दा असेल अशी लक्षणे आताच दिसू लागली आहेत. युरोपीय देश आणि शेजारील कॅनडा यांची ही इस्रायलविरोधी कृती या निवडणूक प्रचारात ट्रम्प यांच्यावरील दबाव वाढवणार हे निश्चित. यानंतर इस्रायलने काही ब्रिटिश लोकप्रतिनिधींवर बंदीची घोषणा केली आणि तेथील राजदूतावासही बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तथापि हे देश इस्रायलला भीक घालण्यास अजिबात तयार नाहीत. ते योग्यच. कारण इस्रायलविना त्यांचे काहीही अडणारे नाही. अडेल ते इस्रायलचेच. कारण युरोपीय संघात असलेले इस्रायलचे आर्थिक संबंध. इस्रायलचा तिळपापड होतो आहे तो यामुळेच. त्या देशातही निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अमेरिकी उपाध्यक्ष व्हान्स यांची भूमिका, कॅनडा, हे युरोपीय देश यांची कृती ही नेतान्याहूंच्या नरसंहारास नकार देते. म्हणून त्याचे स्वागत.

शेतकरी आत्महत्याः अर्थकारणापलीकडचा प्रश्न

लेख

प्रा. डॉ. बाळ राक्षसे
संचालक,
टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था, तुळजापूर
bal.rakshase@tiss.ac.in

आज १० सप्टेंबर, जागतिक आत्महत्या प्रतिबंध दिन. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या माहितीनुसार महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक असल्याचे नमूद केले गेले आहे. महाराष्ट्रातही विदर्भ आणि मराठवाडा विभागात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आढळून आले असून, या प्रदेशाला आत्महत्याप्रवण क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांपैकी बहुतांश शेतकरी अल्पभूधारक किंवा सीमांत शेतकरी आहेत. एकूण कार्यरत भूधारणांपैकी अशा अल्प व सीमांत भूधारकांचे प्रमाण ८५.०१ टक्के आहे. प्रस्तुत लेखाचा उद्देश शेतकरी आत्महत्यांची कारणे आणि त्याचा उपाय यावर लक्ष केंद्रित करणे हा आहे. येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा सर्वांच्या निदर्शनास आणून देणे आवश्यक आहे की, कृषी मजूर आणि शेतकरी/ कास्तकार यांच्या आत्महत्यांना सरसकट 'शेतकरी आत्महत्या' असे संबोधणे योग्य नाही. या दोन्ही सामाजिक- आर्थिक गटांमध्ये मूलभूत फरक आहेत आणि आत्महत्यांच्या कारणांचे विश्लेषण करताना हा फरक स्पष्टपणे लक्षात घेतला पाहिजे.

आत्महत्या ही बहुआयामी आणि अत्यंत गुंतागुंतीची सामाजिक घटना आहे. शेतकऱ्यांमधील आत्महत्यांचे सर्वंकष आकलन करण्यासाठी विविध स्तरांवर कार्यरत असलेल्या गुंतागुंतीच्या घटकांना समजून घेणे आवश्यक आहे.

या घटकांचा अभ्यास करण्याचे दोन संभाव्य मार्ग आहेत.

पहिला मार्ग म्हणजे प्रत्यक्ष पद्धतीने मानस-सामाजिक घटकांचा अभ्यास करणे. यासाठी काही अभ्यासांमध्ये सर्वेक्षण आणि मुलाखतींच्या पद्धतींचा वापर करण्यात आला आहे. काळे, (२०११), दास (१९९८), मोहंती (२००१) आणि टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था (२००५) यांच्या अभ्यासांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येशी संबंधित मानसिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जोखमीच्या घटकांचे अधिक चांगले आकलन करून दिले आहे. या अभ्यासांमध्ये शेतकऱ्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कुटुंबीयांकडून माहिती संकलित करण्यात आली. या अभ्यासांनुसार कुटुंबातील शेतकऱ्याची भूमिका किंवा स्थान (उदा. कुटुंबप्रमुख असणे), तथाकथित सामाजिकदृष्ट्या तळच्या स्तरातील जात, कमी शैक्षणिक पातळी, गरिबी, वय आणि विभक्त/ लहान कुटुंबाची रचना हे मानसिक तणावाशी संबंधित महत्त्वाचे घटक असल्याचे आढळून आले आहे. बोंबले आणि लुंगडिम (Bomble and Lhungdim) (२०२०) यांच्या अभ्यासात शेतकऱ्यांमधील मानसिक तणावाची नोंद करण्यात आली आहे. या अभ्यासात ५८ टक्के शेतकऱ्यांनी मानसिक आरोग्याशी संबंधित तणाव असल्याचे सांगितले.

डुर्खाईम (Durkheim) यांच्या 'सुसाईड' या अभिजात समाजशास्त्रीय ग्रंथातून असे दिसून येते की, वर उल्लेख केलेल्या मानसिक परिणामांना केवळ वैयक्तिक मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून न पाहता समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेता येते.

कर्जाचा वाढता भार, उत्पन्नातील अस्थिरता आणि शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव हे शेतकरी आत्महत्या या प्रश्नाचे आर्थिक पैलू आहेत; पण त्याबरोबरच सामाजिक एकाकीपणा, कौटुंबिक ताण, सामाजिक-सांस्कृतिक दबाव आणि मानसिक आरोग्य समस्या यांचाही त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो. त्यामुळे शेतकरी ज्या सामाजिक, आर्थिक आणि मानसिक परिस्थितीत जगतो, तिचाही विचार केला पाहिजे.

मोहंती (२०१३) यांनी वरील घटकांचे चिकित्सक विश्लेषण करताना असे नमूद केले आहे की, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांमधील निराशा आणि हताशेमागे शेतीच्या उत्पन्नातील घट आणि कर्जबाजारीपणा हे घटक असले तरी, त्यांची मुळे वाढत्या सामाजिक एकाकीपणात आणि व्यक्तिवादात आढळतात. असा दृष्टिकोन स्वीकारल्यास शेतकरी हा केवळ आर्थिक उत्पादन करणारा घटक नसून एक सामाजिक व्यक्ती म्हणून आपल्याला समजतो. बदलती सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक घटक आणि राज्याची धोरणे यांचा त्याच्या जीवनावर कसा परिणाम होतो, हे या दृष्टिकोनातून समजून घेता येते.

अप्रत्यक्ष परिणाम समजून घेण्याचा दुसरा मार्ग म्हणजे उपलब्ध संशोधनाच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण करून अप्रत्यक्ष परिणामांचा शोध घेणे. दांडेकर (२००५), मिश्रा (२००६) आणि नारायणमूर्ती (२००६) यांसारख्या बहुतेक अभ्यासांच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण केले असता, शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्येची प्रवृत्ती निर्माण करणारे प्रमुख घटक आर्थिक स्वरूपाचे असल्याचे दिसते. त्यानुसार उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पिकांना मिळणारा अपुरा भाव; कर्जबाजारीपणा; अनिश्चित मान्सूनमुळे होणारे पीकअपयश; उत्पन्नातील अस्थिरता या घटकांमुळे शेतकऱ्यांचा स्वाभिमान, आत्मविश्वास आणि आशावाद कमी होऊ शकतो आणि त्याचा त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

शेतकरी ही एक सामाजिक व्यक्ती आहे आणि त्यामुळे तिला व्यापक सामाजिक आणि सांस्कृतिक व्यवस्थेच्या संदर्भात समजून घेणे आवश्यक आहे. विवाहव्यवस्था, हुंडा, कुटुंबातील सदस्यांच्या मृत्यूनंतरचे विधी, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च, अनपेक्षित वैद्यकीय खर्च तसेच मानसिक आरोग्याच्या समस्यांबाबतची जागरूकता आणि उपलब्ध मानसिक आरोग्य सेवा या बाबींचा पुरेसा अभ्यास झालेला नाही. हे घटक शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करणारे संयुक्त किंवा पूरक घटक म्हणून कार्य करू शकतात.

प्रतिबंधासाठी उपक्रम आणि धोरणे

शेतकरी आत्महत्यांच्या समस्येच्या संदर्भात सरकारने अनेक अभ्यास केले असून, त्यातून तीन महत्त्वपूर्ण अहवाल प्रकाशित झाले आहेत. त्यातून कर्जमाफी योजना, कर्जमुक्ती पॅकेज आणि उत्पन्नाचे विविधीकरण यांसारख्या उपाययोजना पुढे आल्या. या अहवालांमध्ये आर्थिक घटकांना महत्त्व देण्यात आले; परंतु शेतकरी समुदायातील मानस-सामाजिक समस्यांचा किंवा या समस्यांचा आर्थिक परिस्थितीशी असलेल्या गुंतागुंतीच्या परस्परसंबंधाचा पुरेसा अभ्यास करण्यात आलेला नाही.

परिणामी, भारत सरकारच्या अहवालांमधून सहकारी बँकांच्या माध्यमातून कुटुंबांना सक्षम करणे, संस्थात्मक कर्जव्यवस्था मजबूत करणे आणि आर्थिक दरी कमी करणे यांसारख्या अर्थव्यवस्था-केंद्रित उपाययोजना सुचवण्यात आल्या. मात्र, या उपाययोजनांची अंमलबजावणी आणि त्यांचे परिणाम अपेक्षित पातळीवर झालेले दिसत नाहीत. परिणामी, शेतकरी कुटुंबांमधील आत्महत्येचा धोका कमी झाल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत (काळे, २०१४).

आतापर्यंत सरकारने केलेल्या उपाययोजनांचा मुख्य भर आर्थिक भार कमी करण्यावर राहिला आहे. मात्र इतर मानसशास्त्रीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक घटकांचा धोरणात्मक आणि सातत्यपूर्ण पद्धतीने पुरेसा विचार झालेला नाही. याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्र शासनाने वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशन स्थापन केले. या मिशनच्या माध्यमातून आत्महत्याप्रवण भागांतील कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार, विविध कारणांमुळे आर्थिक अडचणींचा सामना करणारी सुमारे चार लाख शेतकरी कुटुंबे असल्याचे आढळून आले.

२१ नोव्हेंबर २०२२ रोजी भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने राष्ट्रीय आत्महत्या प्रतिबंधक धोरण (नॅशनल सुसाईड प्रीव्हेंशन स्ट्रॅटेजी- एलएसपीएस) जाहीर केले. या धोरणाचे उद्दिष्ट २०२० हे आधारभूत वर्ष मानून २०३० पर्यंत आत्महत्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे प्रमाण १० टक्क्यांनी कमी करणे हे आहे.

विविध राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य आणि आरोग्यविषयक कार्यक्रमांचा सध्याच्या धोरणांमध्ये समावेश आहे; मात्र, या विविध कार्यक्रमांमध्ये शेतकरी आत्महत्यांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरणात्मक भूमिका निश्चित केलेली दिसत नाही. परिणामी, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न सध्याच्या राष्ट्रीय धोरणांमध्ये तुलनेने कमी प्राधान्याचा विषय ठरतो.

समुदाय-आधारित प्रारूपांची भूमिका

शेतकऱ्यांमधील आत्महत्येच्या समस्येच्या मुळाशी असलेल्या विविध संदर्भांचा गुंतागुंतीचा परस्परसंबंध समजून घेण्यासाठी तसेच आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणे आणि उपाययोजनांच्या यश-अपयशाचे विश्लेषण करण्यासाठी समुदाय सहभागाचा दृष्टिकोन आणि सामाजिक- परिसंस्थात्मक प्रारूप ही सर्वाधिक व्यावहारिक आणि प्रभावी प्रारूपे ठरू शकतात. ही प्रारूपे केवळ व्यक्ती किंवा सरकारी धोरणांवर लक्ष केंद्रित न करता, शेतकऱ्याच्या भौतिक, सामाजिक आणि समुदायाच्या पर्यावरणाला केंद्रस्थानी आणतात. त्यामुळे आत्महत्या प्रतिबंधाचा दृष्टिकोन अधिक सर्वंकष होतो. जगभरात अशा समुदाय-आधारित दृष्टिकोनांना अलीकडच्या काळात वाढती मान्यता मिळत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने २०१८ मध्ये 'अ कम्युनिटी एंगेजमेंट टूलकिट' नावाचे मार्गदर्शक प्रकाशित केले. या मार्गदर्शकामध्ये समुदाय सहभाग हा तळागाळापासून वरच्या दिशेने होणारी प्रक्रिया असल्याचे अधोरेखित करण्यात आले असून, जगभरातील त्याच्या यशस्वी वापराची दखल घेण्यात आली आहे. जागतिक आरोग्य संघटने (२०१८) नुसार,

कॅनडाच्या मानसिक आरोग्य आयोगाने आत्महत्या प्रतिबंधक कार्यक्रम समजून घेण्यासाठी समुदायाच्या सहभागावर आधारित दृष्टिकोन यशस्वीपणे स्वीकारला आहे. जपानने २०१७ मध्ये स्वीकारलेल्या आत्महत्या प्रतिबंधक धोरणामध्ये समुदाय सहभागाच्या प्रारूपावर भर देण्यात आला आहे.

भारतामध्ये शेतकरी आत्महत्या प्रतिबंधासाठी अशा स्वरूपाची धोरणात्मक अंमलबजावणी स्पष्टपणे आढळून येत नसली, तरी इतर क्षेत्रांमध्ये भारत सरकार आणि केरळ, ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या राज्य सरकारांनी समुदाय सहभागावर आधारित काही नावीन्यपूर्ण प्रारूपे राबविली आहेत. त्याशिवाय राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातील ग्राम आरोग्य, स्वच्छता आणि पोषण समित्या; कुटुंबश्री मिशन; वनहक्क कायदा, २००६ अंतर्गत ग्राम वन समित्या इत्यादी. याशिवाय, भारतात आणि जगभरात समुदाय सहभागावर आधारित प्रारूपांच्या यशस्वीतेला मार्गदर्शन करणारे आणि आत्महत्या प्रतिबंधासाठी त्यांचा पाया मजबूत करणारे संशोधन मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे.

अशा प्रकारे, शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न केवळ आर्थिक किंवा वैयक्तिक मानसिक आरोग्याच्या समस्येपुरता मर्यादित न ठेवता, त्याकडे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, मानसिक आणि समुदायाच्या संदर्भांचा परस्परसंबंध असलेल्या बहुआयामी सामाजिक समस्येच्या रूपात पाहणे आवश्यक आहे. समुदायाला आत्महत्या प्रतिबंधाच्या प्रक्रियेत सक्रिय भागीदार बनविल्यास स्थानिक समस्या, जोखीम घटक आणि उपलब्ध संसाधने अधिक प्रभावीपणे ओळखता येऊ शकतात आणि स्थानिक गरजांशी सुसंगत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना विकसित करता येऊ शकतात.

अन्वयार्थ

आयफेल टॉवरवर मूल्यांचा संघर्ष!

आयफेल टॉवरच्या कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी 'काम बंद' आंदोलन केल्याने पर्यटक खोळंबले, याची बातमी झाली. पण यामागच्या घटनाक्रमाकडे फ्रेंच राज्यक्रांतीतून जगाला मिळालेली आधुनिक मूल्ये आणि सध्याच्या भारतातील एका प्रभावशाली धार्मिक गटाची रूढीग्रस्त मूल्ये यांचा सौम्यसा संघर्ष म्हणून पाहाता येईल. 'बोचासणवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण' संस्थेने (बीएपीएस) पॅरिसच्या पूर्व उपनगरात बांधलेल्या स्वामीनारायण मंदिराचे रविवारी, ६ सप्टेंबर रोजी उद्घाटन झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्लीतून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे हे उद्घाटन केले आणि भाषणही केले. उद्घाटन सोहळ्यासाठी पॅरिसला आलेला 'बीएपीएस' साधूंचा १०० जणांचा गट आदल्या दिवशी आयफेल टॉवर पहायला गेला. त्यापूर्वी त्यांनी त्याचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या कंपनीकडे या साधूंचा महिलांशी संपर्क येणार नाही याची खबरदारी घेण्याची विनंती केली आणि विशेष म्हणजे कंपनीने ती मान्य केली. त्यानुसार, हे साधू तिथे असताना महिला कर्मचाऱ्यांना तेथून हटवण्यात आले. या घटनेचे पडसाद सोमवारी उमटले. आयफेल टॉवरच्या संतप्त कर्मचाऱ्यांनी बंद पुकारला आणि जगातील सर्वात लोकप्रिय पर्यटन स्थळांपैकी एक असलेले हे ठिकाण दिवसभर बंद राहिले. सर्वसामान्य फ्रेंच नागरिकांपासून माजी अध्यक्ष फ्रांस्वा ओलांद ते अतिउजव्या मरी ले पेन या विविध पक्षीय नेत्यांपर्यंत सर्वांनी या प्रकाराचा निषेध केला.

या तीन दिवसांतील घडामोडींमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामध्ये आधुनिक मूल्ये विरुद्ध रूढीप्रिय मूल्ये; कंपनीचा व्यावसायिक दृष्टिकोन आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये मूल्यांविषयी जागरूकता; धार्मिक कारणांचे निमित्त करून स्त्रियांबद्दल भेदभाव बाळगण्याची मानसिकता, धर्माचे अर्थकारण असे मुद्दे आहेत. फ्रान्समध्ये अठराव्या शतकात (१७८७ ते १७९९) झालेल्या फ्रेंच क्रांतीमुळे इतिहासाने कलाटणी घेतली. संपूर्ण जगाला आधुनिक दृष्टी बहाल करणाऱ्या स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या मूल्यांवर आधारित लोकशाही तत्त्व या क्रांतीतून मिळाले. 'बीएपीएस'च्या साधूंसाठी आयफेल टॉवरवरील महिला कर्मचाऱ्यांना काही काळासाठी हटवण्याची मागणी मान्यही करण्यात आली, तेव्हा समतेच्या मूल्याला मात मिळाली का, असा प्रश्न उपस्थित झाला. पण त्याचे उत्तर अगदी दुसऱ्या-तिसऱ्या दिवशीच मिळाले. आयफेल टॉवरच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रकाराचा निषेध केला आणि संपही केला. यापूर्वी आयफेल टॉवर कधी बंद राहिलाच नव्हता, असे नाही. वित्तीय व्यवस्थापन आणि देखभाल यासारख्या मुद्द्यांवर तिथे संप झाले आहेत, पण लिंगाधारित भेदभावामुळे हे पर्यटन स्थळ बंद राहण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दुर्दैवाने त्याला कारणीभूत ठरलेला धार्मिक गट भारतातील आहे. एकीकडे 'सीईटीई'ने केवळ व्यावसायिक हेतू डोळ्यासमेर ठेवून 'बीएपीएस'ची मागणी मान्य केली. पण ही भूमिका इतरांना मान्य झाली नाही. त्यामुळे फ्रान्समधील मूल्ये अजूनही टिकून आहेत, असा दिलासा वाटून घ्यायला हरकत नाही. दुसरे म्हणजे, 'बीएपीएस'सारखी राजकीय वरदहस्त असलेली धनाढ्य धार्मिक संघटना आपल्या राजकीय, आर्थिक ताकदीचा वापर करून ते अन्य देशांमधील समाजनियम बदलण्याचा प्रयत्न करू पाहत आहेत का, हा प्रश्नही आहेच.

याबरोबरच स्वतःला साधूसंत म्हणवणाऱ्यांच्या धार्मिक आचरणाचाही विचार करणे आवश्यक आहे. 'बीएपीएस'चे सदस्य कठोर ब्रह्मचर्य व्रताचे पालन करतात म्हणून त्यांना स्त्रियांचा संपर्क नको असा युक्तिवाद केला जातो. पण इंद्रियांवर, मनावर संयम राखणे म्हणजे ब्रह्मचर्य- त्याचे व्रत 'बीएपीएस'च्या साधूसंतांनी स्वीकारले असेल तर, त्याचे पालन 'करू देण्याची जबाबदारी' इतरांवर- इथे महिला कर्मचाऱ्यांवर- कशी काय येते? ब्रह्मचर्याचे पालन करण्याची जबाबदारी व्रत स्वीकारण्याचीच आहे. स्वतःवर पुरेसा संयम असेल तर समोर महिला आहे वा नाही यातून फरक कसा काय पडू शकतो? एखाद्याने हे व्रत स्वीकारले आहे आणि समोर एखादी स्त्री आल्याने त्याच्या व्रतात अडथळा निर्माण होत असेल, तर त्याच्या संयमावर प्रश्न उपस्थित करायला हवा. या वर्तनाला ब्रह्मचर्य का म्हणावे, असा प्रश्न विचारला पाहिजे. अशा वेळी एका महिलेला नदी ओलांडण्यासाठी मदत म्हणून कोणताही विचार न करता तिला खांद्यावर घेऊन नदीपलीकडे नेणारा संन्यासी आणि त्या स्त्रीला स्पर्शही न करता त्याच घटनेचा निषेधात्मक विचार करत राहणारा दुसरा संन्यासी यांची कथा आठवत राहते!

नागपूर ते स्वीडन बनावट 'पेप्टाइड'चा प्रवास; औषध नियंत्रणातील पळवाट कुठे?

विश्लेषण

महेश बोकडे
mahesh.bokade@expressindia.com

नागपुरातील पेढीकडून स्वीडनमधील ग्राहकापर्यंत पोहोचलेल्या 'पेप्टाइड'च्या निमित्ताने 'संशोधनासाठी'च्या नावाखाली भारतातून परदेशी ग्राहकापर्यंत पोहोचणाऱ्या उत्पादनांवर नेमके कोणते नियंत्रण असते, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

नागपूर ते स्वीडन व्यवहारातून काय समोर आले?

स्वीडनमधील ग्राहकाने नागपुरातील पेढीकडून 'एमओटीएस-सी'सह पेप्टाइडच्या कुप्या खरेदी केल्या. त्यासाठी पंजाबमधील बँक खात्यात ९० हजार रुपये जमा केल्याचीही नोंद आहे. त्यामुळे पंजाब-नागपूर-स्वीडन अशी व्यवहाराची साखळी समोर येते. मात्र, यावरून संघटित आंतरराष्ट्रीय तस्करीचे जाळे असल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. परंतु त्यासाठी उत्पादनाचा मूळ स्रोत, पुरवठादार, खरेदी-विक्रीची कागदपत्रे आणि परदेशात माल पाठवण्याची प्रक्रिया तपासावी लागेल. ९० हजार रुपये मूल्याचा माल सीमाशुल्क तपासणी टाळण्यासाठी केवळ २०० अमेरिकी डॉलरचा दाखवण्यात आल्याचा आरोपही आहे. त्यामुळे या सीमापार व्यवहाराचा संपूर्ण माग काढणे महत्त्वाचे ठरते.

'संशोधनासाठी' मुक्त विक्री करता येते का?

केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या नियामक व्यवस्थेत नवीन आणि संशोधनाधीन औषधांसाठी स्वतंत्र प्रक्रिया आहे. नवीन औषधे व नैदानिक चाचणी नियम, २०१९मध्ये नवीन किंवा संशोधनाधीन औषधांची आयात, उत्पादन आणि मानवी चाचणीसाठी परवानगीची चौकट निश्चित करण्यात आली आहे. बाजारात एखाद्या उत्पादनाला 'रिसर्च पेप्टाइड' म्हटले जात असले, तरी तेच त्याच्या कायदेशीर मान्यतेचे प्रमाण ठरत नाही. त्यातील पदार्थ कोणता, तो कशासाठी वापरला जाणार आहे आणि त्यासाठी आवश्यक मान्यता किंवा परवानगी घेतली आहे का, हे तपासणे आवश्यक ठरते.

'केवळ निर्यातीसाठी'च्या कुप्यांचे महत्त्व काय?

तपासात इंजेक्शनसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या ३० मिलिलिटरच्या ९ हजार, १० मिलिलिटरच्या ९८४ आणि अन्य १० मिलिलिटरच्या १९ अशा एकूण १० हजार तीन कुप्या आढळल्या. त्यावर 'केवळ निर्यातीसाठी' असा उल्लेख होता. त्यातील दोन नमुने मुंबईतील शासकीय प्रयोगशाळेच्या तपासणीत गुणवत्ता निकषांवर अप्रमाणित ठरले. केवळ 'निर्यातीसाठी' असा उल्लेख केल्याने सर्व औषधविषयक नियमांतून सरसकट सूट मिळत नाही.

बनावट लेबल आणि कंपनीच्या पत्त्याबाबत कायदा काय सांगतो?

औषधाच्या गुणवत्तेइतकीच त्याच्या उत्पादकाची खरी ओळखही महत्त्वाची आहे. औषधे व सौंदर्यप्रसाधने कायदा, १९४०च्या कलम १७-ब मध्ये 'स्प्युरियस' म्हणजे बनावट औषधाची व्याख्या करण्यात आली आहे. दुसऱ्या औषधाची नक्कल करणे, ते दुसऱ्या उत्पादकाचे असल्याचे भासवणे किंवा अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्ती अथवा कंपनीचे नाव उत्पादक म्हणून वापरणे अशा बाबी या व्याख्येत येऊ शकतात. या प्रकरणात अमेरिकेतील 'पेप्टाइड सायन्सेस'च्या नावाचे लेबल व विश्लेषण प्रमाणपत्र बनावट असल्याचे संबंधित कंपनीने सांगितल्याचा उल्लेख तक्रारीत आहे. दुसरीकडे, उत्पादनांवर नवी मुंबईतील 'डॉ. ग्लेक्स फार्माकेम'चा पत्ता होता; मात्र त्या पत्त्यावर अशी कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्याचा दावा आहे.

औषध नियंत्रण यंत्रणेच्या यशाची कसोटी काय?

या प्रकरणाची सुरुवात भारतातील तपासणी यंत्रणेला उत्पादन सापडल्याने नव्हे, तर स्वीडनमधील ग्राहकाला गुणवत्तेबाबत संशय आल्याने झाली. उत्पादन परदेशी ग्राहकापर्यंत पोहोचल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासली गेली आणि त्यानंतर भारतातील पुरवठासाखळीपर्यंत चौकशी पोहोचली. त्यामुळे आता पेप्टाइडचा मूळ उत्पादक कोण, पंजाबमधून नागपूरपर्यंत माल कसा आला, स्वीडनला तो कोणत्या प्रक्रियेतून पाठवला, प्रत्येक टप्प्यावर आवश्यक परवानग्या होत्या का, याचा माग काढावा लागेल. या प्रश्नांची उत्तरे मिळाल्यानंतरच हा प्रकार एका व्यवहारापुरता होता की 'संशोधनासाठी'च्या उत्पादनांच्या सीमापार विक्रीवर अधिक काटेकोर देखरेखीची गरज आहे, हे स्पष्ट होईल.

संपादकीय

आम्ही झिजायचे आणि तुम्ही..?

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अर्थात एमपीएससी परीक्षेसाठी आयुष्यातील उमेदीची वर्षे पणाला लावणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्तपणे रस्त्यावर उतरून संतप्त सुरात केलेला, 'आम्ही झिजायचे आणि तुम्ही पेपर विकायचे?' हा रोकडा सवाल व्यवस्थेच्या कानाखाली आवाज काढणारा आहे. एमपीएससीच्या कारभाराभोवती अगोदरच अनेक वाद घोंगावत असताना नुकतीच औषध निरीक्षक पदाच्या परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटली आणि संपूर्ण भरतीप्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. प्रश्नपत्रिकेच्या सुरक्षेची जबाबदारी ज्यांच्यावर, त्यांच्याच सहभागाचा संशय यानिमित्ताने पुन्हा निर्माण होत असेल, तर विद्यार्थ्यांनी विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर? स्पर्धा परीक्षेची तयारी म्हणजे केवळ पुस्तके आणि अभ्यास नव्हे. घरापासून दूर एखाद्या शहरात छोटी खोली घेऊन राहणे, मेसचा खर्च भागवणे, पालकांच्या कष्टाच्या पैशांवर वर्षानुवर्षे अभ्यास करणे, नोकरीचे दुसरे पर्याय बाजूला ठेवणे आणि प्रत्येक निकालाबरोबर वयोमर्यादा जवळ येताना पाहणे, असा या विद्यार्थ्यांच्या जीवनाचा अस्वस्थ परीघ असतो. त्यांच्या आयुष्यातील चार-पाच वर्षे एखाद्या प्रश्नपत्रिकेच्या फुटीमुळे मातीमोल होत असतील, तर हा केवळ परीक्षेतील गैरप्रकार राहत नाही; तो तरुणांच्या आयुष्यावर घातलेला संघटित दरोडा ठरतो. एमपीएससीमधील गोंधळ हा काही आजचा मुद्दा नाही. अध्यक्ष बदलले, सचिव बदलले, सरकारे बदलली; पण प्रश्नपत्रिकांतील चुका, सदोष भाषांतर, चुकीच्या आन्सर की, प्रश्न रद्द करण्याची वेळ, परीक्षा पुढे ढकलणे, निकालांना विलंब आणि भरती प्रक्रियेतील संशय यांचे चक्र थांबलेले नाही. कधी तांत्रिक कारण, कधी प्रशासकीय अडचण, तर कधी बाह्य यंत्रणेवर जबाबदारी ढकलून आयोग मोकळा होतो. प्रत्येक गोंधळानंतर चौकशी समिती, उपाययोजनांची आश्वासने आणि काही दिवसांनी सारे विस्मृतीत. मग पुन्हा एक परीक्षा, पुन्हा चुका आणि पुन्हा विद्यार्थ्यांचा आक्रोश! प्रश्नपत्रिका फुटली तेव्हा आपण पदावर नव्हतो, असे जबाबदार अधिकाऱ्यांनी सांगणे तांत्रिकदृष्ट्या खरे असूही शकते; पण त्यामुळे यंत्रणेची जबाबदारी संपत नाही. खुर्चीवर बसताना केवळ अधिकार मिळत नसतात, तर जबाबदारी, उत्तरदायित्व आणि यंत्रणेतील चुकांचा वारसाही स्वीकारावा लागतो. विद्यार्थ्यांचा आताचा आक्रोश पाहिला तर त्यांना हवा आहे विश्वासार्ह आयोग, सुरक्षित परीक्षा आणि पैशाने खरेदी करता न येणारी गुणवत्तेची खात्री. पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर आणि नाशिकपर्यंत विद्यार्थ्यांचा संताप रस्त्यावर उतरला आहे. पुण्यात 'जंतर मंतर' उभे करण्याचा इशारा दिला जात आहे. राज्यकर्त्यांनी तो विरोधकांचा राजकीय कार्यक्रम म्हणून झटकून टाकण्याची चूक कदापि करू नये. कारण, उद्विग्न आणि अस्वस्थ झालेला तरुण रस्त्यावर उतरतो, तेव्हा त्याचा उद्रेक कोणत्याही एका पक्षाच्या नियंत्रणात राहत नाही. दिल्लीतील जंतर मंतरवर दीर्घकाळ चाललेल्या आंदोलनांचा धडा या सरकारसमोर आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेणे सरकारला आणि व्यवस्थेला परवडणारे नाही, तसेच केवळ फेरपरीक्षा घेऊन या प्रकरणावर पडदाही टाकता येणार नाही. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती परीक्षा केंद्रावर पोहोचेपर्यंतच्या प्रक्रियेचे स्वतंत्र 'फॉरेन्सिक ऑडिट' झाले पाहिजे. गुन्हे शाखेचा अहवाल सार्वजनिक व्हायला हवा. संबंधित प्रत्येक अधिकारी, मध्यस्थ आणि खासगी क्लास चालकांची साखळी उघड व्हायला हवी. गेल्या काही काळातील संशयास्पद परीक्षा आणि निवडींची स्वतंत्र विशेष तपास पथकामार्फत चौकशी व्हायला हवी. त्याबरोबरच दुसरीकडे 'एन्क्रिप्टेड' प्रश्नपत्रिका, केंद्रावर नियंत्रित मुद्रण, डिजिटल ट्रॅकिंग, अधिकाऱ्यांची पार्श्वभूमी तपासणी आणि प्रत्येक टप्प्याची निश्चित जबाबदारी ही व्यवस्था तातडीने अमलात आणायला हवी. शिवाय, दोषी अधिकाऱ्यांना केवळ निलंबित न करता सेवेतून बडतर्फीसोबतच कठोर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. एमपीएससी हा नोकऱ्या वाटणारा एखादा 'एम्प्लॉयमेंट ब्युरो' नाही, तर ती महाराष्ट्राच्या प्रशासनासाठी प्रामाणिक आणि गुणवत्तावान अधिकारी निवडणारी घटनात्मक संस्था आहे. तिच्याच दारात सतत असा पैशांचा बाजार आणि पेपरफुटीचा तमाशा होत असेल, तर त्याचे उत्तर सरकार आणि आयोगाला द्यावेच लागेल. केवळ चौकशीचे गाजर दाखवून भागणार नाही. कारण फुटलेली प्रश्नपत्रिका पुन्हा छापता येईल; पण तरुणांच्या विश्वासाला गेलेला हा तडा सहजासहजी सांधता येणार नाही. सध्या राज्यात सुरू असलेली विद्यार्थ्यांची उत्स्फूर्त आंदोलने म्हणजे ज्वालामुखीची खदखद आहे. ही 'छात्रों की गूंज' वेळीच समजून घ्यावी, अन्यथा एमपीएससीसह या सरकारचाही नक्षा उतरल्याशिवाय राहणार नाही.

माझ्या कार्यालयात 'लगान'चा सामना रंगला, तेव्हा...

व्यवस्थेतला बदल मोठ्या घोषणा करणाऱ्यांमुळे नाही, तर अनामिक लोकांच्या शांत, प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण कामातूनही घडत असतो.

व्ही. राधा
अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन, महाराष्ट्र

जवळपास दोन वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र शासनातील सुमारे पाच लाख कर्मचाऱ्यांच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापनाची जबाबदारी असलेल्या विभागाची सूत्रे माझ्याकडे आली. सेवा नोंदवही, पदोन्नती, बदल्या, निवृत्ती अशा प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याच्या सेवेशी निगडित अनेक महत्त्वाच्या बाबी या विभागामार्फत हाताळल्या जातात. माझ्या तीन दशकांच्या प्रशासकीय कारकिर्दीकडे मागे वळून पाहताना मी स्वतःलाच एक प्रश्न विचारते, या काळातील नेमकं काय माझ्या कायम लक्षात राहील?

प्रत्येक वेळी या प्रश्नाचं उत्तर एकच येतं 'माणसं'.

व्यवस्था परिपूर्ण नसते. तिच्यात अनेक त्रुटी असतात. पण तिच्या केंद्रस्थानी माणुसकी असू शकते, याची जाणीव करून देणारी माणसं आयुष्यभर लक्षात राहतात. माझ्या सध्याच्या टीमची आठवण झाली की मला 'लगान' चित्रपट आठवतो. पहिल्यांदा या टीमला भेटले, तेव्हा परिस्थिती फारशी आशादायक नव्हती. अनुकंपा तत्त्वावर सेवेत दाखल झालेला एक लिपिक. एक विभागीय अधिकारी अद्याप परिविक्षाधीन होता. एक तरुण महिला आपल्या आईच्या निधनाचं दुःख मनात घेऊन काम करत होती. आस्थापना शाखेत एक कवयित्री होती, कवितेच्या विश्वातून जणू प्रशासनाच्या कठीण जगात तिची बदली झाली होती.

एनआयसीची टीम जुनाट संगणकांवर काम करत होती. अपुरे पगार. अपुरी जागा. कपाटांमधून खाली गळणाऱ्या फायली आणि मध्यभागी मी. 'लगान'मधल्या भुवन सारखी. नेतृत्व करण्याची जबाबदारी माझ्यावर होती.

यानंतर जे घडलं, ते आजही मला आश्चर्यचकित करतं. एकेक करून या सगळ्यांनी कामाची जबाबदारी उचलली. ब्लॉकचेन प्रकल्प असो, पोर्टल असो, प्रक्रियांचं पुनर्रचनाकरण असो किंवा मोबाइल ॲप, ज्यांच्याकडे काम करण्यासाठी अगदी प्राथमिक सुविधा होत्या, त्यांनी त्याच साधनांमधून काहीतरी नवीन उभं करण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही इतर राज्यांमध्ये गेलो. तिथल्या उल्लेखनीय कल्पना समजून घेतल्या. त्या आपल्या व्यवस्थेला कशा लागू करता येतील, याचा विचार केला. आणि शक्य असेल तिथे त्या कल्पनांपेक्षाही काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रवासात अश्रू होते, हशा होता, मतभेद होते आणि प्रचंड थकवाही.

पण खरी कठीण लढाई त्यानंतर सुरू झाली. वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या नियमांकडे नव्याने पाहिलं गेलं. कालबाह्य झालेल्या नियमांचा फेरविचार करण्यात आला. गरज नसलेले नियम बाजूला करण्यात आले. वर्षानुवर्षे व्यवस्थेला अडवून ठेवणाऱ्या न्यायालयीन प्रकरणांमागची मूळ समस्या शोधली गेली. हळूहळू व्यवस्थेतील त्रुटी स्पष्ट दिसू लागल्या. आणि मग न्यायालयांनी वर्षानुवर्षे ज्या अन्यायाकडे बोट दाखवलं होतं, तो अन्याय दूर करण्यासाठी नियमांमध्ये बदल करण्यात आले.

प्रतिकात्मक

यातून एक नवी व्यवस्था उभी राहिली. सेवा पुस्तिकेची पुनर्रचना हा त्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा. कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण सेवेशी संबंधित माहितीचा प्रचंड भार घेऊन बसलेली जुनी व्यवस्था नव्याने उभारताना एक मूलभूत प्रश्न सतत समोर ठेवला गेला, 'जे लोक सरकारसाठी काम करतात, त्यांच्यासाठी सरकारची व्यवस्था अधिक चांगली करता येईल का?' याच प्रश्नातून पुढे एक अशी एकात्मिक व्यवस्था उभी राहिली, जी एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या सेवेत प्रवेश करण्याच्या पहिल्या दिवसापासून त्याच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत त्याच्यासोबत राहते.

आम्ही भारतीय प्रशासन व्यवस्थेतील सर्वोत्तम ह्युमन रिसोर्स प्रणाली उभी केली आहे का, हे मला माहीत नाही. त्याचा निर्णय इतिहास करेल. पण हे खरं, की माणसं उभी राहिली. एका लिपिकाने, एका परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याने, एका कवयित्रीने आणि जुन्या संगणकांनी पूर्णपणे कामात झोकून दिलं. कदाचित खरी सुधारणा हीच असते. व्यवस्था लोकांसाठी काय उभं करते, यापेक्षा ती लोकांना काय बनण्याची संधी देते, हे अधिक महत्त्वाचं असतं.

'इकॉनॉमिक सर्व्हे २०२५-२६'मध्ये राज्याच्या संस्थात्मक क्षमतेवर स्वतंत्र प्रकरण आहे. धोरण आखणे, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, बदलत्या परिस्थितीनुसार त्यात सुधारणा करणे आणि नागरिकांपर्यंत त्याचे परिणाम पोहोचवणे ही राज्याच्या संस्थात्मक क्षमतेची मूलभूत अंगं आहेत. भारताच्या विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात ही क्षमता आता सर्वात महत्त्वाची मर्यादा ठरत असल्याचं या सर्व्हेमध्ये अधोरेखित करण्यात आलं आहे.

शासन कोणतंही धोरण प्रत्यक्षात उतरवतं, ते आपल्या स्वतःच्या मनुष्यबळाच्या माध्यमातूनच. ही यंत्रणा बोथट असेल, तिचे नियम कालबाह्य असतील, तिच्या नोंदी वाचण्यास आणि समजण्यास कठीण असतील, तर वरच्या पातळीवर कितीही चांगलं धोरण आखलं, तरी त्याचा लाभ जिथे पोहोचायला हवा, तिथे तो पोहोचणार नाही. यात ग्लॅमर काहीच नाही. आणि कदाचित कधी असणारही नाही. काही कामं केवळ सरकारनेच करायची असतात, आणि त्यांची जबाबदारीही सरकारनेच स्वीकारायची असते.

राज्याची संस्थात्मक क्षमता महत्त्वाची आहे. 'विकसित भारत' घडवताना या क्षमतेला विकासाच्या अजेंड्यावर स्थान देणं ही केवळ प्रशासकीय गरज नाही, तर भारताच्या भविष्यासाठीची अत्यावश्यक प्राथमिकता आहे. या संपूर्ण प्रवासातून मला मिळालेला सर्वात मोठा धडा एकच- बदल नेहमी मोठ्या घोषणा करणाऱ्यांमुळेच घडतो असे नाही. कधी कधी अनामिक लोकांच्या शांत, प्रामाणिक आणि सातत्यपूर्ण कामातून बदल घडतो. या लोकांचं नाव कुठेही लिहिलं जात नाही. ते प्रसिद्ध नसतात. त्यांच्यावर प्रकाशझोत नसतो. त्यांच्या कामाची रोज दखल घेतली जात नाही. पण ते असतात, आपापल्या जागी उभे राहून, आपलं काम प्रामाणिकपणे करत असतात.

आणि शेवटी, व्यवस्था खऱ्या अर्थाने पुढे नेणारे हेच लोक अदृश्य नायक असतात!

अन्वयार्थ

'आपण यांना पाहिलंत का?' - त्यांचा शोध का लागत नाही?

हरवलेल्या व्यक्तींचा शोध गांभीर्याने घेतला जावा, यासाठी सुप्रीम कोर्टाचा हस्तक्षेप महत्त्वाचा मानला पाहिजे. पोलिस यंत्रणेची उदासीनता झटकायला हवी.

डॉ. खुशालचंद बाहेती
निवृत्त सहायक पोलिस आयुक्त व महाव्यवस्थापक- जनसंपर्क लोकमत

हरवलेल्या व्यक्तीला शोधण्यासाठी पोलिस यंत्रणेची भूमिका उदासीनतेची राहिली आहे. तक्रार अर्जाची नोंद घेणे, एक वायरलेस संदेश पाठवणे व अर्ज फायलीत ठेवणे यालाच शोधणे समजले जाते. नातेवाइकांनाच माहिती मिळाली तर कळविण्याच्या सूचनाही दिल्या जातात. यातही हरवलेल्या व्यक्तीचा शोध ही बाब 'कोण हरवले' यावर अवलंबून राहते. तरुण मुलगी किंवा प्रौढ व्यक्ती हरवली तर 'कुटुंबातील वाद', 'स्वतःच्या इच्छेने गेली' असे म्हणत अनेकदा दुर्लक्ष केले जाते. फक्त अल्पवयीन हरवले किंवा राजकीय-माध्यमांचा दबाव आला तरच यंत्रणा हालचाल करते. या निवडक उदासीनतेमुळे लाखो लोक बेपत्ता राहिले आणि तस्करीच्या जाळ्यांना मोकळीक मिळाली.

राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड ब्यूरोनुसार २०२४ मध्ये ५,२०,१६४ व्यक्ती हरवल्याची नोंद झाली. त्यात १,६७,४१४ पुरुष, ३,५२,७२९ महिला आणि २१ ट्रान्सजेंडर यांचा समावेश आहे. त्याच वर्षी पोलिसांनी ५,०३,६०२ व्यक्तींना शोधून काढले किंवा परत आणले. तरीही मागील वर्षाची थकबाकी धरता वर्षअखेरीस चार लाखांहून अधिक लोक अजूनही न सापडलेले राहिले. २०२३ मध्येही ४,८४,५८४ नवीन प्रकरणे नोंदली गेली आणि वर्षअखेरीस ४,०७,६७३ व्यक्ती अजूनही बेपत्ता होत्या. ही थकबाकी कमी होत नाही; एकूण बेपत्ता व्यक्तींचा विचार केल्यास शोध दर साधारण ५० ते ५५ टक्क्यांच्या आसपास राहतो. अर्थात यात अनेकदा व्यक्ती परत आली तरी त्याची नोंद होतेच असे नाही. नातेवाईक ती वर्दी देण्यास टाळाटाळ करतात, हा भागही आहेच.

मे २०१३ मध्ये 'बचपन बचाओ आंदोलन' विरुद्ध भारत सरकार या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने अल्पवयीन हरवल्यास एफआयआर नोंदवावा, सुरुवातीला अपहरण किंवा तस्करीची शक्यता गृहीत धरावी, असे आदेश दिले. तेरा वर्षांनंतर न्यायालयाने याची व्याप्ती वाढवली. मे व ऑगस्ट २०२६ मध्ये कोणतीही व्यक्ती हरवल्याची माहिती मिळताच ताबडतोब एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश दिले. यातही काही राज्यांनी 'व्यक्ती म्हणजे फक्त अल्पवयीन' असा अर्थ काढण्याचा प्रयत्न केला. न्यायालयाने त्याला 'हेतूपूर्वक आणि दुष्ट हेतूने उभारलेले ढोंग' म्हटले आणि अवमानाची कारवाई करण्याची धमकी दिली. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, 'व्यक्ती' या शब्दाचा अर्थ वय किंवा लिंग काहीही असो, प्रत्येक व्यक्ती असाच आहे.

एफआयआर ताबडतोब आणि अनिवार्य करून न्यायालयाने पोलिसांचा आवडता पहिला बचाव - 'प्रथम चौकशी करू' ही सवय - काढून टाकला आहे. एकदा अपहरण, किंवा तस्करी संबंधित कलमांखाली एफआयआर नोंदला की, तपास अनिवार्य ठरतो. सुप्रीम कोर्टाने म्हटल्याप्रमाणे पहिले २४ ते ४८ तास शोध घेण्यासाठी गोल्डन अवर्स असतात. गरज पडल्यास अँटी-ह्यूमन ट्रॅफिकिंग युनिट्सकडे तपास सोपवता येतो. पालकांच्या संमतीशिवाय लग्न करण्यासाठी घर सोडून जाणारे तरुण-तरुणी, विशेषतः मुलींची कुटुंबे अशा प्रकरणांत 'कुठेतरी गेली ती परत आलीच नाही' अशी तक्रार करतात, खरे तर ती पळून गेल्याचे त्यांना माहीत असते. पोलिसही आंतरजातीय किंवा आंतरधर्मीय वादांत अडकू नये म्हणून तक्रार दडपायला पाहतात. आता हा पर्याय संपला आहे. एफआयआर नोंदवावाच लागेल, तपास सुरू करावाच लागेल. व्यक्ती स्वेच्छेने गेली आहे आणि सुरक्षित आहे, की यामागे दबाव, तस्करी किंवा हिंसा आहे, हेही आता स्पष्ट होऊ शकते. प्रौढ वयातल्या जोडप्यांनी पळून जाण्याच्या प्रकरणांत पालकांना त्यांना बेकायदेशीर बंदिवान बनवता येणार नाही किंवा जबरदस्तीने परत आणता येणार नाही. तस्करीच्या प्रकरणात 'मिसिंग' दाखवता येणार नाही.

अनिवार्य एफआयआर तस्करी थांबवणार नाहीत किंवा प्रत्येक बेपत्ता व्यक्ती शोधून काढणार नाहीत. पण ते निष्क्रियतेचा पहिला आणि सर्वात सोपा टप्पा व सबबी काढून टाकतील. यंत्रणेला प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तीच्या तपासाची जबाबदारी घेण्यास भाग पाडतील. बचपन बचाओनंतर तेरा वर्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा प्रजासत्ताकाला आठवण करून दिली आहे की, व्यक्तीचे हरवणे हे फक्त खासगी दुःख नाही. ती सार्वजनिक जबाबदारी आहे. भारतातील पोलिस आपली कर्तव्य भावना विस्तारतील का?

जगभर

कंबरभर पाण्यात झालेल्या एका लग्नाची गोष्ट

लग्न ही खरं तर कोणासाठीही अविस्मरणीयच गोष्ट असते. सध्या तर आपलं लग्न केवळ आपल्याच नाही तर इतरांच्याही कायम स्मरणात कसं राहील, यासाठी आटापिटा केला जातो. कोणी उडत्या विमानात, कोणी पाण्याखाली जाऊन, कोणी बसमध्ये, तर कोणी ट्रेनमध्ये उभं राहून लग्न करतात. लग्न हा इव्हेंट तर झाला आहेच; पण त्याची जास्तीतजास्त चर्चा आपल्या परिवारात व्हावी, यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात.

पण लेआन लिझा गालांग आणि गिल्बर्ट चिको त्यातले नव्हते. पण, त्यांच्यावर वेळच अशी आली की, त्यांचं लग्न जगभर व्हायरल झालं.

गेल्या महिनाभरापासून सातत्याने कोसळणाऱ्या पावसामुळे फिलिपिन्समधल्या अनेक भागांतील जनजीवन विस्कळीत झालं आहे. लेआन आणि गिल्बर्ट मनिला शहरात राहतात. या दोघांचं लग्न डिसेंबर २०२६मध्ये होणार होतं; पण गिल्बर्टमुळे हे लग्न नियोजित तारखेआधीच करण्याची लगबग सुरू करावी लागली. गिल्बर्ट हा मध्य पूर्वेत 'रिगर' म्हणून काम करतो. छंद म्हणून तो बास्केटबॉल खेळतो. खेळताना त्याच्या पायाच्या घोट्याला दुखापत झाली. या दुखापतीमुळे गिल्बर्टला फिलिपिन्समधील घरी यावं लागलं. आरामासाठी म्हणून आलेल्या गिल्बर्टला बरं झाल्यावर पुन्हा कामाच्या ठिकाणी परतायचं आहे. आता मधेच यावं लागल्याने पुन्हा डिसेंबरमध्ये येणं शक्य होणार नाही, याचा गिल्बर्टला अंदाज होता. म्हणून डिसेंबरआधीच लग्न करायचं ठरलं.

मनिला शहराच्या उत्तरेला असलेल्या हागोनाय शहरातील 'सेंट जॉन द बॅप्टिस्ट चर्च'मध्ये त्यांचा विवाह होणार होता. पण, गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या पावसाने चर्चमध्ये पाणी साचलं. लग्नाच्या दिवसापर्यंत पाऊस इतका वाढला की, चर्चमध्ये कंबरेइतक्या उंचीचं पाणी साचलं. ही सगळी परिस्थिती पाहून प्रिस्टने लग्न पुढे ढकलण्याचा सल्ला

दोघांना दिला होता. पण, आता लग्न पुढे ढकललं तर ते फारच पुढे जाईल. त्यामुळे दोघेही १ सप्टेंबरलाच लग्न करण्यावर ठाम राहिले. त्यांचा आग्रह पाहून प्रिस्टने त्यांना विरोध केला नाही.

पाऊस पडतोय, पूर आलाय, आता कसं होणार, ही काळजी करण्यापेक्षा लेआन आणि गिल्बर्टने पुरातून वाट काढत लग्न कसं करायचं याचं नियोजन केलं. पाण्यात भिजून कपडे ओले होतील, ही भीती सारून दोघांनी लग्नासाठी म्हणून शिवलेला गाऊन आणि कोट घालण्याचं ठरवलं. फक्त पायघोळ गाऊन घालून पुराच्या पाण्यातून चालता येणार नाही, याचा अंदाज आल्याने लेआनने तिच्या गाऊनची उंची थोडी कमी केली.

लग्नाच्या दिवशी किमान चर्चमध्ये पोहोचेपर्यंत घातलेले कपडे कोरडे राहतील, याची काळजी दोघांनी घेतली. विशेष उंच रिक्षा आणि पुराच्या पाण्यात वापरल्या जाणाऱ्या बोटींचा आधार घेत ही दोघं आणि त्यांचे जवळचे नातेवाइक चर्चपर्यंत पोहोचले. घर ते चर्च हे छोटसं अंतर कापायला त्यांना १०,००० फिलिपिन्स पेसो (भारतीय चलनात १५ हजार १०० रुपये) खर्च करावे लागले. अंगठी घालणं, शपथ घेणं या विवाहाच्या रीती पार पडेपर्यंत लेआन आणि गिल्बर्ट दोघेही पूर्ण भिजले होते. त्यांच्या लग्नाला चर्चमध्ये केवळ १५ जण उपस्थित राहू शकले. बाकीचे सर्व त्यांच्या रिसेप्शनला आले. तिथे पुराचं पाणी नव्हतं. पण, तिथे गेल्यानंतरही या दोघांनी ओले कपडे बदलले नाहीत. त्यांच्या नातेवाइकांना, मित्रांना लग्नाच्या पोशाखातच दोघांसोबत फोटो काढायचे होते. ते काढून झाल्यावर मग त्यांनी कपडे बदलले.

या लग्नाचे फोटो आणि व्हिडीओ जगभर व्हायरल झाले.. एका लग्नाची अशीही गोष्ट!

जनमन

स्मार्ट मीटर : कोणाच्या फायद्यासाठी?

सध्या राज्यभर स्मार्ट मीटरला नागरिकांचा विरोध होत आहे. तरीही सुस्थितीत आणि योग्य रीडिंग दाखवणारे जुने मीटर काढून स्मार्ट मीटर बसवण्याचा निर्णय महावितरण घेत आहे. स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहकांना फायदा होईल, असा दावा केला जातो; मात्र हा फायदा नेमका कसा होणार, याचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. काही ग्राहकांनी स्मार्ट मीटरमुळे जास्त रीडिंग व वाढीव बिलांच्या तक्रारी केल्या आहेत. अर्थिंग लिकेजमुळे बिल वाढू शकते, असेही सांगितले जाते. सध्याचे मीटर योग्य प्रकारे काम करत असताना ते स्क्रॅपमध्ये टाकून एका स्मार्ट मीटरसाठी अंदाजे बारा हजार रुपये खर्च करण्याची सरकारला गरज काय? स्मार्ट मीटरमुळे रीडिंग घेणे आणि बिल ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याची कामे बंद होऊन अनेक रोजंदारी कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो. स्मार्ट मीटरद्वारे बिल न भरल्यास कार्यालयातूनच वीजपुरवठा बंद करता येतो. रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिक दिवसभर कामावर असताना त्यांचा वीजपुरवठा बंद झाल्यास त्यांना रात्री घरी आल्यानंतरच याची माहिती मिळेल. सर्वांकडे स्मार्टफोन किंवा ऑनलाइन बिल भरण्याची सुविधा नसल्याने त्यांना मोठा त्रास सहन करावा लागू शकतो. सरकारचे काम केवळ आर्थिक व्यवहार पाहणे नसून जनतेच्या सुविधा आणि रोजगाराचे संरक्षण करणेही आहे. म्हणून स्मार्ट मीटर खरोखर जनतेच्या फायद्यासाठी आहेत की महावितरण आणि मीटर उत्पादक कंपन्यांच्या फायद्यासाठी? याचे स्पष्ट उत्तर सरकारने द्यावे.

मोहन मनोहर खोतरेंदाळ (हुपरी), जि. कोल्हापूर

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : janman@lokmat.com

सेतू

विश्वास, शिस्त आणि चांगुलपणा जपणाऱ्या लोकांचा देश

पोलंडमध्ये चोरी हा प्रकार जवळजवळ नाहीच! एखाद्याची वस्तू हरवली, तर ती मालकापर्यंत परत पोहोचवण्यासाठी इथले लोक जिवाचं रान करतात.

अवनी दाते
पोलंड

उन्हाळ्यात एक दिवस मी आणि माझा छोटा मुलगा सोसायटीच्या पार्कमध्ये खेळायला गेलो होतो. त्याची नवी सायकलही नेली होती. खेळून, बाकीच्या आया आणि मुलांशी गप्पा मारून आम्ही घरी परत आलो, पण सायकल पार्कमध्येच राहिली. दोन दिवसांनी सोसायटीतल्या एका मैत्रिणीचा मेसेज आला. तिने सायकलीचा फोटो पाठवून विचारलं, "ही तुमचीच सायकल आहे ना?" तेव्हा आठवलं, परवा आम्ही सायकल तिथेच विसरलो होतो. दोन दिवस सायकल कुलपाशिवाय तिथे होती, पण कुणीही तिला हात लावला नव्हता. हीच पोलंडची खासियत.

या देशातले लोक प्रचंड प्रामाणिक आहेत. इथे चोरी हा प्रकार ना के बराबर! उलट एखाद्याची वस्तू हरवली तर ती मालकापर्यंत परत पोहोचवण्यासाठी इथले लोक जीवाचं रान करतात. रस्त्यावर, सिग्नलजवळ किंवा कुंपणावर टांगलेल्या टोप्या, हातमोजे, खेळणी अशा अनेक वस्तू दिसतात. ज्याच्या हरवल्या आहेत त्याला त्या सहज सापडाव्यात म्हणून टांगून ठेवलेल्या असतात. हरवलेल्या वस्तूंचे फोटो शेअर करणारे ग्रुप्सही असतात. वस्तू सापडली की फोटो टाकायचा आणि ज्याची असेल त्याने ती घेऊन जायची. विशेष म्हणजे, ज्याची वस्तू असेल तोच प्रामाणिकपणे आपलीच वस्तू परत घेऊन जातो.

एकदा मैत्रिणीसाठी वाढदिवसाचं गिफ्ट घेऊन मी ट्रामने तिच्या घरी निघाले होते. उतरताना गडबडीत गिफ्टची बॅग सीटवरच राहिली. मी खूप घाबरले, पण मैत्रीण भेटल्यावर तिनेच धीर दिला. ट्रामची वेळ

विचारून डेपोमध्ये फोन केला. त्यांनी ट्राम कुठल्या डेपोमध्ये आहे ते सांगितलं. तिथे गेलो तर माझी बॅग त्यांनी खिडकीजवळ ठेवली होती, जेणेकरून शोधायला आलेल्या व्यक्तीला लगेच मिळेल. माझ्या मैत्रिणीला तिचं बर्थडे गिफ्ट मिळालं आणि मला पोलंडच्या प्रामाणिकपणाचं आणि सुव्यवस्थेचं सरप्राईज गिफ्ट!

एका सकाळी मी पोहायला गेले होते. संध्याकाळी माझ्या कानातली हिऱ्याची सोन्याची रिंग गायब असल्याचं लक्षात आलं. ती नेमकी कुठे पडली असेल याचा अंदाजही नव्हता. मी लगेच स्विमिंग क्लबमध्ये फोन केला. त्यांनी चौकशी करून उलटा फोन केला. माझ्याकडे दुसऱ्या कानातल्या रिंगचा फोटो मागवला. स्विमिंग क्लबमधली रिंग माझीच याची खात्री झाल्यावर मला त्यांनी ती घेऊन जायला बोलवलं. रिंग शॉवर रूममध्ये पडली होती. स्वच्छता करणाऱ्या महिलेला मिळाली. तिने ती सिक्युरिटी स्टाफकडे दिली. रिंग परत देताना तिथली महिला हसत म्हणाली, "पोहायला येताना दागिने घरी ठेवायचे असतात!"

मी आणि माझा नवरा अक्षरशः अवाक् झालो! कुणालाही अगदी क्षणभरही मोह झाला नाही. उलट, ज्याची आहे तो शोधत येईल तेव्हा देऊ, या विचाराने त्यांनी ती जपून ठेवली.

त्या दिवशी मला माझी रिंग तर परत मिळालीच, पण पोलंडची माणुसकी, प्रामाणिकपणा यांचं नव्याने दर्शनही घडलं. पोलंडमध्ये राहणं म्हणजे फक्त एका नवख्या देशात राहणं नाही, तर विश्वास, शिस्त आणि चांगुलपणा जपणाऱ्या लोकांच्या सहवासात जगणं आहे.

neenaadate@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.)
'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

अवैध निर्माण पर प्रहार

जर्जर और अवैध भवनों को ध्वस्त करने की कोई भी कार्रवाई स्वागतयोग्य है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम को शहर के कई हिस्सों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और इस दिशा में मुस्तैदी से काम होना ही चाहिए। दिल्ली में सत्य निकेतन भवन के ढहने से हुई सात छात्रों की मौत को भुलाया नहीं जा सकता। इससे पुख्ता सबक लेने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि रात गई, बात गई जैसा कुछ फिर दोहराया जाए। गहरा अफसोस, भवन ढहने से मौत दिल्ली के लिए विरल बात नहीं है। यहां हर साल भवन गिरने से 1,000 से ज्यादा लोग जान गंवाते हैं, आगजनी की वजह से करीब 4,000 लोगों की जान जाती है। गौर करने की बात है, साल 2023 में दिल्ली में नगर नियोजन या निगरानी के अभाव में 6,054 और साल 2024 में 5,971 लोगों की जान गई थी। ये आंकड़े झकझोरते हैं, पर क्या शासन-प्रशासन की नींद टूट गई है?

अभी भवन ढहने का जो हादसा हुआ है, उसमें महज एक मंजिल की इजाजत थी और पांच मंजिला निर्माण हो चुका था। बगैर कंक्रीट पीलर के न जाने कितने भवन दिल्ली में खड़े हैं? ऐसे भवनों को गिराने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। क्या ऐसे भवनों को मजबूती या वैधता देने के लिए यथोचित अभियांत्रिक प्रयास हो सकते हैं? जिन भवनों को अंदर या बाहर से मजबूत बनाया जा सकता है, उन्हें बचाया जाए और बाकी तमाम जर्जर-जोखिम भरे भवनों को जल्द से जल्द ध्वस्त करने में हिचकना नहीं चाहिए। जर्जर भवनों को ध्वस्त करने का आदेश बीच में ही वापस नहीं लेना चाहिए। अधिकारियों को पूरी मुस्तैदी से इस आदेश को अंजाम देना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने उचित ही सभी वरिष्ठ एमसीडी अधिकारियों को ध्वस्त करने की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद रहने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा असुरक्षित भवनों के निर्माण और मंजूरी की जांच के आदेश भी सराहनीय हैं। जिम्मेदार अधिकारियों को कठघरे में खड़ा करने में कोई हर्ज नहीं है। पीजी आवासों, विशेष रूप से मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, लक्ष्मी नगर, सत्य निकेतन और साकेत जैसे छात्रों के रिहायशी इलाकों में भवनों की सुरक्षा की जांच युद्ध स्तर पर होनी चाहिए। असुरक्षित भवनों को ढहा देने में ही समाज व देश की सुरक्षा है। अगर सरकार नए पेइंग गेस्ट कानून बनाने की योजना बना रही है, तो यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। संरचनात्मक व अग्नि सुरक्षा ऑडिट, क्षेत्रवार किराया निर्धारण और पेइंग गेस्ट आवासों को सूचीबद्ध करने का काम होना ही चाहिए।

जोखिम भरे भवनों को जल्द से जल्द ध्वस्त करने में हिचकना नहीं चाहिए। ऐसे भवनों को ध्वस्त करने का आदेश बीच में ही वापस नहीं लेना चाहिए।

अब समय आ गया है, कोई भी राजनीतिक पार्टी अवैध निर्माण को प्रश्रय न दे। ज्यादातर पार्टियां अवैध निर्माणों के साथ राजनीति करती हैं। यहां विशेषज्ञों की राय और लोगों की जान ज्यादा कीमती है। देश में ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब विशेषज्ञ सलाह को नजरंदाज करने की कीमत अनेक लोगों को जान देकर चुकानी पड़ी है। मिसाल के लिए, साल 2011 में माधव गाडगिल के नेतृत्व में एक पैनल ने देश के पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी पर रिपोर्ट तैयार की थी। उस विशेषज्ञ रिपोर्ट की अवहेलना हुई और 30 जुलाई, 2024 की सुबह भारी बारिश की वजह से वायनाड, केरल में भयानक भूस्खलन हुआ, पहाड़ियां ढह गईं, 420 लोगों की मौत हुई, 397 घायल हुए और 118 लापता हो गए। वायनाड हो या दिल्ली या कोई अन्य जगह, विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप चलकर ही हम सबके लिए सुरक्षा कवच तैयार कर सकते हैं।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 10 सितम्बर, 1951

ग्राहम मिशन की विफलता

डा. ग्राहम संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से काश्मीर की समस्या का समाधान खोजने के लिए आये थे। जब उन्होंने यह दायित्व स्वीकार किया था, तभी समाधान की बहुत कम आशा थी। जिस प्रस्ताव के मातहत सुरक्षा परिषद ने उन्हें नियुक्त किया था, उसको भारत ने स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। किन्तु डा. ग्राहम ने विपरीत परिस्थितियों के आगे हार मानने से इन्कार कर दिया और आशावादी हृदय के साथ वह भारत और पाकिस्तान आये। उनके यहां आने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों में और भी तनाव पैदा हुआ।

पाकिस्तान के जिहाद के नारों और काश्मीर के प्रश्न पर युद्ध की तैयारियों ने वातावरण को अत्यधिक उग्र बना दिया। फिर भी डा. ग्राहम अपना प्रयत्न करते रहे। उन्होंने कराची और नई दिल्ली के अनेक चक्कर लगाये। दोनों देशों के भाग्य विधाताओं से अलग-अलग चर्चायें चलाईं और उनके दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने का उद्योग किया। किन्तु दोनों के बीच खाई इतनी चौड़ी हो चुकी है कि उसे किसी भी मध्यस्थ के लिए पाट सकना असम्भव-सा हो गया है। यद्यपि डा. ग्राहम ने अपने मिशन की सफलता अथवा विफलता के संबंध में कोई निश्चित घोषणा नहीं की है, किन्तु यह निश्चित-सा है कि उनके प्रयत्नों का कोई उल्लेखनीय परिणाम नहीं निकला है। डा. ग्राहम भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक बार भी काश्मीर के बारे में आपसी बातचीत के लिए एक जगह एकत्र नहीं कर पाये। डा. ग्राहम शीघ्र ही भारत और पाकिस्तान से विदा हो रहे हैं और जेनेवा में बैठकर सुरक्षा परिषद के लिए अपने प्रयत्नों की रिपोर्ट लिखेंगे। डा. ग्राहम के प्रयासों का जो परिणाम आया है, उसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता।

डा. ग्राहम ने फिलहाल उन सुझावों पर कोई भी रोशनी डालने से इन्कार कर दिया है जो उन्होंने भारत या पाकिस्तान के सामने अलग-अलग रखे होंगे। इसलिए उनके बारे में उनकी रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक प्रतीक्षा ही करनी पड़ेगी। सुरक्षा परिषद ने उन्हें आदेश दिया था कि काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निष्पक्ष जनमत-संग्रह करवाने के लिए सुरक्षा परिषद के पूर्व प्रस्तावों के आधार पर विसैन्यीकरण की योजना तय्यार करें और यदि उनकी योजना से दोनों पक्ष सहमत न हों तो यह बतायें कि मतभेद के कौन से मुद्दे हैं।

भारत-रूस की परखी हुई दोस्ती

यहां स्कैन करें

रहीस सिंह | वैश्विक मामलों के वरिष्ठ अध्येता

ब्रिक्स सम्मेलन से ठीक पहले नई दिल्ली में मोदी-पुतिन की भेंट तब हो रही है, जब रूस वैश्विक अलगाव एवं पश्चिमी दुनिया के वैचारिक-आर्थिक हमलों से गुजर रहा है।

भारत ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसके अपने निहितार्थ हैं और संदेश भी, लेकिन उससे भी अधिक मायने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के, जो ब्रिक्स की बैठक से एक दिन पहले ही हो रही है। यह भेंट क्रेमलिन की इस सोच के साथ हो रही है कि रूस, भारत को अपना रणनीतिक साझेदार मानता है और दोनों देशों के रिश्ते उसके लिए बेहद अहम हैं।

अहम इसलिए, क्योंकि पुतिन उस दौर में भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, जब रूस वैश्विक अलगाव एवं पश्चिमी दुनिया के वैचारिक-आर्थिक हमलों से गुजर रहा है और पूरी दुनिया की निगाहें पुतिन पर आ ठिठकी हैं। पुतिन के लिए यह तय करने का वक्त भी हो सकता है कि पुरानी और नई दोस्ती को कैसे देखें और किसे चुनें? कुछ विश्लेषक उन्हें स्टालिन के सर्वसत्तावादी चश्मे से देखते हैं, जिससे पुतिन में उन्हें डरना कम, डराना अधिक दिखता है। वैसे, इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि ऐसे वक्त में भी पुतिन दुनिया की अपेक्षा भारत की ओर देख रहे हैं। यह भारत के लिए मॉस्को की तरफ से मिलने वाला 'डिप्लोमैटिक डिवीडेंड' है, जो नई दिल्ली के लिए स्थितियों को अनुकूल बनाता है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि इन स्थितियों में पुतिन की भारत यात्रा रणनीतिक, सैन्य, आर्थिक और भू-राजनीतिक आयाम की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है?

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और संवेदनशील समय में होने जा रही मोदी-पुतिन बैठक में कुछ अहम मुद्दे शामिल हो सकते हैं। रक्षा, परमाणु ऊर्जा, ईंधन, व्यापार और भू-राजनीति से जुड़े द्विपक्षीय मुद्दों के अलावा संभावना यह भी है कि इसमें यूक्रेन युद्ध और फारस की खाड़ी में जारी तनाव जैसे मुद्दे भी होंगे। ये दोनों संघर्ष भू-राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाल रहे हैं, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। इसलिए इन पर चर्चा भी होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पुतिन खाड़ी में कायम तनाव से प्रभावित

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर तो मुखरता से बोलते हैं, मगर यूक्रेन के मामले में वह चुप्पी साध लेते हैं। यह देखा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन युक्रेन युद्ध को रोकने की सलाह या ऐसे किसी वक्तव्य पर सहज नहीं होते। ऐसे में, यूक्रेन युद्ध को लेकर किसी शांति पहल की वकालत करने के बजाय भारत को कूटनीतिक सहयोग को मजबूत करने वाले मुद्दों पर आगे बढ़ना चाहिए।

इस बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। जैसा कि क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से बताया गया है कि रूस द्वारा पांचवीं पीढ़ी का स्टील्थ तकनीक (जिसे रडार न पकड़ सकें) वाला जेट फाइटर सुखोई 57 (एसयू-57) भारत को देना रूसी एजेंडे में शामिल है। इसके साथ ही बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग एक अहम मुद्दा हो सकता है।

पुतिन की पिछली भारत यात्रा दिसंबर 2025 में हुई थी। नौ महीने में यह उनकी दूसरी भारत यात्रा है, इसलिए भारत-रूस मैत्री और मोदी-पुतिन केमिस्ट्री को समझने की आवश्यकता होगी। हालांकि, यह मैत्री नई नहीं है, पिछले 55 वर्षों से चली आ रही है। यद्यपि बीच में यह कुछ गड़बड़ाई और अभी भी इसे संभाले रखने की चुनौती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि इसका असर रक्षा, भू-रणनीति और ऊर्जा रणनीति पर पड़ सकता है।

कूटनीति में 'फॉरवर्ड', 'बैलेंसिंग', 'रीसेट' और 'रीबैलेंसिंग' एक चक्रीय क्रम में चलता रहता है, इसलिए ठहरने के बजाय आगे बढ़ने की जरूरत होती है और भारत और रूस इन मामलों को लेकर गंभीर हैं। यही कारण है कि रूस ने अमेरिका के विरोध के बावजूद भारत के साथ एस 400 डील की और भारत ने यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद भी उससे तेल खरीद जारी रखी। हालांकि, ट्रंप की टैरिफ नीतियों के चलते यह प्रक्रिया कुछ हद तक प्रभावित हुई, जैसा कि दुनिया के अन्य देशों के साथ भी हुआ।

भारत और रूस को नई वैश्विक परिस्थितियों में साझेदारी के अन्योन्याश्रित मॉडल को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है। ध्यान रहे, आज भी भारत के लगभग 55 से 60 प्रतिशत हथियारों और प्रौद्योगिकी का रूस से ही सरोकार है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर एस-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम तक शामिल हैं। ये हमारी सुरक्षा क्षमता बढ़ाते हैं। भारत और रूस के ऊर्जा संबंध (विशेषकर कच्चे तेल की आपूर्ति) भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए 'बूस्टर' का काम कर सकते हैं। दोनों देश रुपया-रूबल आधारित व्यापार, लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर और एनर्जी परियोजनाओं (रोसनेफ्ट, सखालिन) की ओर कदम बढ़ाकर नए कूटनीतिक अध्याय लिख सकते हैं।

भू-राजनीतिक दृष्टि से नई दिल्ली-मॉस्को इस समय बहुध्रुवीय विश्व को मजबूत करके वाशिंगटन धुरी को संतुलित करने का काम कर सकते हैं। भारत और रूस की दोस्ती अभी भी चल रही है, इसका अहम कारण यह है कि नई दिल्ली मानती है कि पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर कई आधारभूत बदलाव आए, कई तरह के भू-राजनीतिक समीकरण उभरे, किंतु इनके बावजूद भारत-रूस मित्रता अडिग रही है।

सोवियत युग के समाप्त होने के बाद भारत-रूस मैत्री में कुछ उतार-चढ़ाव आए, क्योंकि नई दिल्ली मॉस्को के बजाय वाशिंगटन की ओर देखने लगी थी। कारण था- पूंजीवाद के नए युग का आरंभ और उसका नेतृत्व वाशिंगटन द्वारा किया जाना। भारत ने भी नई जरूरतों के अनुरूप स्वयं को बदलने की कोशिश की, लेकिन दोनों देशों के बीच स्थापित रक्षा और रणनीति के रिश्तों में कोई बड़ी दरार नहीं आ पाई। आज दोनों देश '2+2 डिप्लोमैसी' के जरिये आगे बढ़ रहे हैं और नई बुनियाद रखने की कोशिश में हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि दो नए दोस्तों के मुकाबले एक पुराना दोस्त ज्यादा अच्छा है।

भारत और रूस के रिश्तों की उम्र 55 साल के आसपास हो गई है, यानी पूरी तरफ से परिपक्व, इसलिए ये दोनों न केवल द्विपक्षीय जरूरतों, बल्कि तमाम अड़चनों के बावजूद भावी विश्व-व्यवस्था के अनुरूप आकार ग्रहण अवश्य करेंगे। भारत बहुत से लोकाचारों और संकोचों को तोड़ते हुए 'सॉफ्ट पावर ऑफ सिविलाइजेशन' की दावेदारी के लिए तैयार है। यह बात और है कि *सिर पर लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिन्दुस्तानी* की प्रतिध्वनि अब वैसी नहीं है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पश्चिम से उत्तर भारत तक आसान हुई माल ढुलाई

यहां स्कैन करें

विजय दत्त | सेवानिवृत्त अतिरिक्त सदस्य, रेलवे बोर्ड

दो दशक पुराना सपना पूरा हुआ है। 2,843 किलोमीटर लंबे समर्पित माल ढुलाई गलियारे (डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर) पर मालगाड़ियां अब दौड़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वडोदरा दौरे में वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डब्ल्यूडीएफसी) के आखिरी करीब 326 किलोमीटर हिस्से को राष्ट्र के नाम किया, जिसके बाद माल ढुलाई को समर्पित ईस्टर्न और वेस्टर्न, यानी पूर्वी और पश्चिमी, दोनों गलियारों पर सेवाएं पूरी तरह से शुरू हो गईं। ईस्टर्न से जहां कोयला और अयस्कों आदि की ढुलाई हो रही है, वहीं वेस्टर्न से सामानों से लदे कंटेनर ढोए जाएंगे।

'वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर' के पूरी तरह शुरू हो जाने से कुछ अन्य उपलब्धियां भी भारत के खाते में जुड़ गई हैं। मिसाल के लिए, हम दुनिया के इकलौते देश बन गए हैं, जिसके पास पूरी तरह बिजली से चलने वाला 'डबल-स्टैक कंटेनर' फ्रेट कॉरिडोर का नेटवर्क है। यानी, एक के ऊपर दूसरा कंटेनर लादकर माल ढुलाई की जा सकेगी। इतना ही नहीं, दुनिया भर में पारंपरिक ओवरहेड तार लगभग 5.5 मीटर पर होते हैं, लेकिन डब्ल्यूडीएफसी में तारों की ऊंचाई करीब 6.4 मीटर है, जिससे एक ही वैगन पर दो या कम ऊंचाई वाले तीन कंटेनरों को लादना संभव हो सकेगा। कंटेनरों के निर्माण में भी खास ध्यान रखा गया है, ताकि तूफान जैसी विपदाएं इसका रास्ता नहीं रोक सकें।

हम दुनिया के इकलौते देश बन गए हैं, जिसके पास पूरी तरह बिजली से चलने वाला 'डबल-स्टैक कंटेनर' फ्रेट कॉरिडोर का नेटवर्क है।

कहने को यह कॉरिडोर नवी मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट (जेएनपीटी) को एनसीआर के दादरी से जोड़ता है, लेकिन इससे पिपावाव, मुंद्रा, कांडला जैसे प्रमुख बंदरगाहों पर उतरने वाले सामान को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे पश्चिम और उत्तर भारत के औद्योगिक शहरों में पहुंचाना आसान होगा। इसके लिए दादरी, कोटा, वडोदरा जैसी तमाम जगहों पर बड़े-बड़े कंटेनर डिपो बनाए गए हैं, जो सड़क मार्ग से जुड़े हुए हैं। इससे 'प्वाइंट-टु-प्वाइंट कनेक्टिविटी' संभव हो सकेगी। हालांकि, इस गलियारे से सिर्फ राज्यों की अर्थव्यवस्था को फायदा नहीं होगा, बल्कि राष्ट्र की आर्थिकी पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे भारत की कुल लॉजिस्टिक लागत, जो अभी जीडीपी की 14 फीसदी है, घटकर सात प्रतिशत पर आ सकती है, जिससे वैश्विक बाजार में भारतीय सामान को प्रतिस्पर्द्धा करने में सहूलियत होगी।

पर्यावरण के लिहाज से भी यह कॉरिडोर काफी काम का साबित होगा। तथ्य यही है कि बिजली से चलने वाली ट्रेनें कार्बन उत्सर्जन को बिल्कुल शून्य कर देती हैं। माना जा रहा है कि एक डबल-स्टैक मालगाड़ी में 250 ट्रकों के बराबर माल ढोया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि इतने ट्रकों से पर्यावरण को जो नुकसान होता, वह नहीं होगा। वैसे भी, 'कॉप-26' की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रल (शून्य उत्सर्जक) बनाने का लक्ष्य रखा है।

फ्रेट कॉरिडोर पर चलने वाली गाड़ियों की तेज गति भी काफी काम की साबित होंगी। असल में, सामान्य मालगाड़ियां आमतौर पर 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसी कारण 'मेन लाइन' पर पीछे चलने वाली यात्री गाड़ियों की गति पर इसका नकारात्मक असर पड़ता था। इस मामले में डब्ल्यूडीएफसी से दोतरफा फायदा होगा। एक, इस पर मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गुजर सकेंगी। चूंकि यह समर्पित गलियारा है, इसलिए उनको यहां 'क्लीयरेंस' भी आसानी से मिल सकेगा, जिससे सामान की ढुलाई तेज हो सकेगी। दूसरा फायदा यह होगा कि यदि मालगाड़ी को मेन लाइन पर लाना भी पड़े, तो उसकी गति यात्री गाड़ियों को प्रभावित नहीं करेगी। चूंकि सभी गाड़ियों की गति कमोबेश समान होगी, इसलिए एक ही पटरी पर कई गाड़ियों को दौड़ाना आसान होगा।

साफ है, माल ढुलाई के लिहाज से यह एक ऐसा कदम है, जिसका दूरगामी असर पड़ेगा। अच्छी बात यह भी है कि मालगाड़ियों के अब ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से गुजरने के कारण मेन लाइन पर यात्री गाड़ियों को अधिक वक्त मिल सकेगा। इससे कई नई ट्रेन चलाने के रास्ते खुल सकेंगे। इससे अंततः रेलयात्रियों को ही फायदा होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

स्वाद के लिए लगाव जरूरी

आप चाहे जिस किसी क्षेत्र में हों, यदि अपने आप को उसमें पूरी तरह शामिल करके उत्साह से काम नहीं करेंगे, तो आपको आत्मसंतोष नहीं मिलेगा। काम करने की जगह ही नहीं, अपने माता-पिता, पत्नी या पति और बच्चों के प्रति पूरा लगाव न रखें, तो जिंदगी एक ऐसा फंदा या जाल बन जाएगी, जिसमें आप अनजाने ही फंस गए हों। लगाव रखने पर वह स्वर्ग होगा, लगाव के बिना वही नरक बनेगा।

ऐसी किसी एक चीज का नाम बताइए, जिसका पूरी लगाव के बिना आपने स्वाद लिया हो। सोचकर देखिए, अपने मन और शरीर को पूर्ण रूप से लगाए बिना आपने कोई सफलता या उपलब्धि पाई है? आप जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, आपकी ज्यादातर कामयाबी को तय करने वाला प्रमुख पहलू क्या है? अपने मन और शरीर को आप किस हद तक उस काम में झोंक सकते हैं, यही वह खास पहलू है।

एक नेता के लिए आवश्यक लक्षण क्या-क्या हैं? अपने कार्य में उसे पूरी तरह से जुटे रहना चाहिए। पूर्ण रूप से अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। हार से हौसला खोए बिना, एक नए अवसर के रूप में लेते हुए, उसे स्वीकार करने की मनोदशा होनी चाहिए। जीवन का सबसे सरल पक्ष यही है कि यदि आपका अंतःकरण पूरी तरह से शांत रहे, तो चाहे सफलता हो या हार, जीवन का प्रत्येक पक्ष सरल लगेगा। जिंदगी बिना संघर्ष के सहज रूप से चलेगी। यदि मन में शांति नहीं है, तो हरेक चीज मुश्किल लगेगी। छोटी-छोटी बात भी उलझन से भरी लगेगी। यही सारे पहलू खेल-कूद में भी पाए जाते हैं।

खेल-कूद में दूसरों को अपने में शामिल करने की प्रवृत्ति रहती है। अपने दल का आदमी मानकर दूसरे को किसी तरह के राग-द्वेष से परे होकर मिला लेते हैं। टीम के सभी लोग अपनी विभिन्नताओं को भूलकर एक ही उद्देश्य से, एक ही लक्ष्य को मन में रखकर सक्रिय रहते हैं। दूसरों को अपने साथ मिलाने की प्रकृति स्वयं एक अच्छे समूह के निर्माण का आधार है। हजार घंटों तक आध्यात्मिक उपदेश देने के बजाय केवल एक घंटा खेल-कूद में लगाने पर आप देख सकते हैं कि एक समूह किस तरह अपने को दृढ़ता से स्नेहपाश में बांध रहा है।

जिंदगी भी खेल की तरह है। जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए उत्साह और लगन पूर्ण रूप से आवश्यक हैं। आधी-अधूरी जिंदगी बिताना यातना ही है।

खेल का सबसे बड़ा पहलू क्या है? इसमें आधे-अधूरे मन से लगना संभव नहीं है। मैदान में खेला जाने वाला कोई भी खेल हो, जिसमें आपका शरीर और मन लगा रहेगा, सही ढंग का खेल होगा, नहीं तो वह भी नरक बन जाएगा। एक गेंद को उठाकर फेंकना है और अगर उससे पूरा लगाव नहीं है, तो वह आसानी से संभव नहीं होगा। जिंदगी भी खेल की तरह है। जीवन को संपूर्ण बनाने के लिए उत्साह और लगन पूर्ण रूप से आवश्यक हैं। आधी-अधूरी जिंदगी बिताना यातना ही है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

प्रल्हाद जोशी | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

शिक्षा का ऐसा इकोसिस्टम बने, जो सुलभ, नवाचारी और भविष्य के अनुकूल हो। इसमें उच्च शिक्षा को मजबूत करने, अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देने, छात्रों और युवाओं के लिए अवसर बनाने और केंद्र-राज्य के बीच बेहतर तालमेल जैसे विषय हों।

खुदकुशी की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक

हर वर्ष 10 सितंबर को 'विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस' मनाया जाता है। हालांकि, सिर्फ एक दिन इसे मनाने से समाज में आत्महत्या नहीं रुक सकती। बड़े-बुजुर्ग ही नहीं, छात्र और युवा भी अपनी जान लेते रहे हैं। आखिर क्यों? आत्महत्या यानी खुद को मारना, निहायत ही कठिन कार्य है। क्या खुदकुशी करने से उनकी समस्याएं सुलझ जाती हैं? यकीनन नहीं। ऐसे में, समाज को आगे आना होगा। अगर हमारा समाज वाकई आत्महत्या जैसी चीज को खत्म करना चाहता है, तो उसे सबसे पहले सभी में जुड़ाव बढ़ाना होगा। हमें आपस में जुड़ना चाहिए। यह जुड़ाव ऐसा हो कि किसी को अकेलेपन जैसा महसूस न हो। मृत्यु तो अटल सत्य है, लेकिन इसके पहले जो खूबसूरत जिंदगी और सुंदर दुनिया को देखने और महसूस करने का मौका मिला है, उसको खुदकुशी करके खत्म तो नहीं करना चाहिए। समाज में लोग बाहरी मुखौटा लगाकर खुश रहने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वे बेहद शून्य और अकेले होते हैं। इसी परिस्थिति को खत्म करने की जिम्मेदारी समाज को ही निभानी होगी।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

जब कोई व्यक्ति अपनी संवेदनाओं और विचारों के झंझावात में इस कदर उलझ जाता है कि उसे जीवन का हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, तब उसके भीतर उठने वाली खामोश पुकार पूरे समाज की चेतना पर एक गहरा प्रश्नचिह्न लगाती है। प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाए जाने वाला विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस वास्तव में आत्मनिरीक्षण का अवसर है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि एक सभ्यता और समाज के रूप में हम कहां चूक रहे हैं? क्या हम अपने आसपास छिपी उस असीम पीड़ा को महसूस करने में अक्षम हो चुके हैं, जो किसी जीवन को असमय समाप्त करने की त्रासद स्थिति तक पहुंचा देती है? सरकारी नीतियों और सरकारी तंत्र के प्रयासों के साथ-साथ जब तक सामुदायिक स्तर पर संवेदनशीलता का विस्तार नहीं होगा, तब तक इस बाबत कोई भी अभियान पूर्ण सफल नहीं हो सकता। आत्महत्या कोई विफलता या महज क्षणिक आवेग का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह उस गहरे अवसाद और संवादहीनता की परिणति होती है, जिससे व्यक्ति लंबे समय तक अकेले जूझता रहता है। यदि हम सचमुच इस त्रासदी को रोकना चाहते हैं, तो हमें एक समाज के रूप में अपनी सुनने और समझने की क्षमता को पुनर्जीवित करना होगा। हमें लोगों के व्यवहार में सूक्ष्म परिवर्तनों के प्रति सजग रहना होगा और उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि वे अकेले नहीं हैं।

देवेंद्रराज सुथार, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

आत्महत्या रोकथाम

आत्महत्या रोकने के लिए सरकारें गंभीर

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, हर वर्ष देश में बड़ी संख्या में लोग आर्थिक संकट, बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, परीक्षा के दबाव और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण अपनी जान ले लेते हैं। आंकड़ों की मानें, तो वर्ष 2017 में प्रति एक लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की दर 9.9 थी, जो 2022 में बढ़कर 12.4 तक पहुंच गई। ऐसे में, यह कहना उचित नहीं लगता कि आत्महत्या को सिर्फ व्यक्तिगत प्रयासों से रोका जा सकता है। इसमें सरकार की नीतियां और संस्थागत हस्तक्षेप भी जरूरी है।

सबसे पहला काम, जो सिर्फ सरकारें कर सकती हैं और कर रही हैं, वह है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 ने मानसिक स्वास्थ्य को नागरिक का अधिकार माना और आत्महत्या के प्रयास को अपराध की बजाय मानसिक संकट के रूप में देखने का प्रावधान किया। इसके बाद राष्ट्रीय टेली-मानस कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसके माध्यम से देश भर में चौबीसों घंटे निःशुल्क मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराया जाने लगा है। यह पहल उन लोगों के लिए मददगार साबित हुई है, जो समय पर विशेषज्ञ के पास नहीं जा पाते। दूसरा, आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा आत्महत्या रोकने का प्रभावी माध्यम है। किसानों की आत्महत्या के मामलों ने यह स्पष्ट किया कि केवल सलाह पर्याप्त नहीं होती। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, मनरेगा और विभिन्न ऋण राहत योजनाएं आर्थिक असुरक्षा कम करने के उद्देश्य से लागू की गईं। जब आय और रोजगार का भरोसा मिलता है, तो लोगों में निराशा भी कम होती है। तीसरा काम शिक्षा के क्षेत्र में उठाए गए कदम हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परीक्षा-केंद्रित संस्कृति को कम करने, परामर्श सेवाएं बढ़ाने और समग्र विकास करने पर जोर देती है। कोटा जैसे कोचिंग केंद्रों में छात्र-आत्महत्या की घटनाओं के बाद कई राज्यों ने हॉस्टलों में हेल्पलाइन, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश अनिवार्य कर दिए हैं।

सरकारों के प्रयास कितने जरूरी हैं, इसकी तस्दीक विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस सलाह से भी होती है कि प्रभावी सरकारी नीतियां, हेल्पलाइन, आवश्यक दिशा-निर्देश और स्वास्थ्यगत सेवाएं आत्महत्या को रोकने के लिए जरूरी कदम हैं। भारत में मानसिक स्वास्थ्य कानून, टेली-मानस, किसान और छात्र कल्याण योजनाएं इसी दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इसलिए आत्महत्या रोकने की सबसे प्रभावी शुरुआत सरकार के संगठित और संवेदनशील प्रयासों से ही होती है।

दीपक वत्स, टिप्पणीकार

अंतरिक्ष विज्ञान में करियर की उड़ान

कल की तैयारी

अंतरिक्ष में हो रहे प्रयोग और नई तकनीकें अब आम आदमी की जिंदगी से जुड़ रही हैं। इससे स्पेसटेक और ड्रोन मैन्यूफैक्चरिंग में करियर की नई संभावनाएं बन रही हैं। सरकारी एजेंसियों के साथ निजी क्षेत्र भी अवसरों के द्वार खोल रहा है। भारत में करीब 440 स्पेसटेक स्टार्टअप पंजीकृत हैं। तकनीक के साथ डाटा, प्रबंधन और वित्त से जुड़े युवाओं के लिए भी अवसर बढ़ रहे हैं। यहां करियर बनाने के लिए क्या पढ़ें और क्या प्रशिक्षण लें, बता रहे हैं सोनिक सौरभ

बीती जुलाई में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंपनी स्काईरूट एयरोस्पेस ने विक्रम-1 नामक पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च करके इतिहास रच दिया। यह है भारत में उभरते स्पेसटेक की झलक। स्पेसटेक को भविष्य में रोजगार देने वाले अहम क्षेत्रों में गिना जा रहा है। छोटी-बड़ी कई कंपनियां इस समय इस सेक्टर में सक्रिय हैं। जैसे नालंदा के सुब्रत शांडिल्य, जिन्होंने एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के बाद स्पेसटेक को अपनाया। वे करीब 2 किलो-न्यूटन क्षमता वाले जेट इंजन पर काम कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल ड्रोन और यूएवी में हो सकता है। इस क्षेत्र में एयरोस्पेस, ड्रोन, प्रोपल्शन, डिजाइन और 3डी प्रिंटिंग के विशेषज्ञों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं।

कैसा था बीता कल : देखा जाए, तो अर्थ2 ऑर्बिट जैसे शुरुआती स्पेस स्टार्टअप 2009 में ही आ चुके थे, लेकिन वर्ष 2020 के बाद नीतिगत बदलावों से इस क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए मैन्यूफैक्चरिंग के रास्ते खुले। वहीं, स्वतंत्र नोडल एजेंसी इन-स्पेस के जरिए अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली कंपनियों को मंजूरी, तकनीक और सुविधाओं तक पहुंच आसान बनी।

भारतीय स्पेस स्टार्टअप्स में करीब 618.5 मिलियन डॉलर का निवेश हो चुका है। 30 से अधिक देशों के साथ सहयोग से भारतीय कंपनियों के लिए निर्यात, तकनीकी सहयोग और वैश्विक सप्लाई चेन से जुड़ने के मौके बढ़े हैं। छोटे उपग्रह, पुनः उपयोग होने वाले रॉकेट और अंतरिक्ष-आधारित संचार सेवाओं के विस्तार से रोजगार बढ़ रहा है। इससे तकनीक, डाटा, संचालन व कारोबार से जुड़े कौशलों की मांग बढ़ रही है। ग्लैक्सआई स्पेस जैसे स्टार्टअप इस बदलाव के उदाहरण हैं।

ड्रोन निर्माण पर जोर : कमर्शियल ड्रोन इंडस्ट्री को आकार देने वाले शीर्ष 10 देशों में भारत को दूसरा स्थान मिला है। वहीं, मार्केट्सएंडमार्केट्स के अनुसार भारत का ड्रोन बाजार 2030 तक 1.39 अरब डॉलर हो सकता है। ड्रोन नीति 2021 ने सेल्फ-सर्टिफिकेशन और आसान अनुमति प्रक्रिया के जरिए उद्योग को रफ्तार दी है। आने वाले वर्षों में यह सेक्टर 5 लाख रोजगार दे सकता है। कृषि, सर्वेक्षण, मैपिंग, आपदा राहत, फिल्म-मीडिया, निगरानी और डिलीवरी में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। इसलिए मांग सिर्फ ड्रोन पायलटों की नहीं, बल्कि इंजन, प्रोपल्शन, डिजाइन, सेंसर, डाटा प्रोसेसिंग व मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञों की भी बढ़ेगी।

वेतन : इसरो में वैज्ञानिक/इंजीनियर का वेतन 56 हजार रुपये प्रतिमाह से शुरू होकर अनुभव के साथ 2 लाख रुपये तक संभव है। निजी स्पेस कंपनियों में अच्छे पैकेज हैं। ड्रोन के क्षेत्र में पद अनुसार वेतन 25 से 80 हजार प्रतिमाह या अधिक हो सकता है।

भारत की स्पेस इकॉनमी अगले दस वर्षों में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 40-45 अरब डॉलर हो सकती है।

क्या होंगी भूमिकाएं

- **एयरोस्पेस व एवियोनिक्स इंजीनियर :** रॉकेट और उपग्रह की संरचना व डिजाइन के लिए
- **रिमोट सेंसिंग व जियोस्पेशियल डाटा एनालिस्ट :** उपग्रह से मिलने वाले डाटा के विश्लेषण के लिए
- **गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल विशेषज्ञ :** उपग्रह व रॉकेट की दिशा-नियंत्रण प्रणाली के लिए
- **प्रशिक्षित ड्रोन पायलट :** सर्वेक्षण, मैपिंग, कृषि, निगरानी और आपदा प्रबंधन जैसे कामों के लिए
- **स्पेस साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ :** उपग्रहों और अंतरिक्ष प्रणालियों की साइबर सुरक्षा के लिए।
- **स्पेस पॉलिसी और लॉ विशेषज्ञ :** अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े नियम, नीतियों और कानूनी मामलों के लिए
- **प्रोपल्शन इंजीनियर :** रॉकेट/उपग्रहों के इंजन, ईंधन और थ्रस्ट सिस्टम के डिजाइन, टेस्ट और विकास के लिए

भविष्य में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी थ्रीडी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन व एडवांस्ड मैटेरियल्स जैसी तकनीकों की समझ रखने वाले युवाओं की मांग भी बढ़ सकती है।

कदम-दर-कदम आगे बढ़ें

किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने की जल्दबाजी न करें। पहले गणित, भौतिकी और तकनीक की बुनियादी समझ मजबूत करें। इसके बाद विमान, रॉकेट, ड्रोन, अंतरिक्ष और इनसे जुड़े दूसरे क्षेत्रों को समझें। जैसे-जैसे आपका ज्ञान बढ़े, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और रिसर्च के अवसर तलाशें। एयरोस्पेस में एक अच्छा करियर रातोरात नहीं, बल्कि धीरे-धीरे कदम-दर-कदम बनता है।

- प्रो. राज कुमार पंत, आईआईटी बॉम्बे

किस तरह की पढ़ाई जरूरी होगी?

■ बीटेक एयरोस्पेस या एवियोनिक्स इंजीनियरिंग के लिए जेईई या संबंधित संस्थान की प्रवेश परीक्षा देनी होगी। ■ बीटेक/बीएससी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिजिक्स के बाद एमटेक/एमएस किया जा सकता है। ■ ड्रोन टेक्नोलॉजी में करियर बनाने और मान्यता प्राप्त रिमोट पायलट सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 10वीं पास होना अनिवार्य है। ■ सैटेलाइट इमेज, मैपिंग और भौगोलिक डाटा के विश्लेषण के लिए रिमोट सेंसिंग और जीआईएस की पढ़ाई उपयोगी है। ■ गैर-तकनीकी पृष्ठभूमि वाले युवा स्पेस पॉलिसी, स्पेस लॉ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस और डाटा एनालिटिक्स में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कर सकते हैं।

शिक्षण-प्रशिक्षण की सुविधा कहां?

■ **स्पेसटेक के लिए :** आईआईएसटी, तिरुवनंतपुरम में एयरोस्पेस और एवियोनिक्स की पढ़ाई की जा सकती है। आईआईटी, आईआईएससी और आईआईआरएस, देहरादून भी अच्छे विकल्प हैं।

■ **ड्रोन तकनीक के लिए :** डीजीसीए से मान्यता प्राप्त आरपीटीओ जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (आईजीआरयूए, उत्तर प्रदेश), ड्रोन डेस्टिनेशन (गुरुग्राम), गरुड़ एयरोस्पेस और स्काईलार्क ड्रोन्स (बेंगलुरु) से प्रशिक्षण लिया जा सकता है।

■ **अपस्किलिंग के लिए :** इसरो का भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान रिमोट सेंसिंग, जीआईएस और जियोडाटा एनालिटिक्स के ऑनलाइन एवं अल्पकालिक पाठ्यक्रम कराता है। जियोडाटा प्रोसेसिंग के लिए पाइथन और मशीन लर्निंग, एआई/एमएल फॉर जियोडाटा एनालिसिस तथा रिमोट सेंसिंग-जीआईएस जैसे विकल्प शामिल हैं।

युवा इस क्षेत्र में कैसे आएं : स्कूल स्तर से भौतिकी, गणित और रोबोटिक्स में रुचि बढ़ाएं। प्रोजेक्ट, हैकाथॉन व इंटर्नशिप से अनुभव लें। गैर-तकनीकी युवा डाटा विश्लेषण, कानून, नीति, प्रबंधन, कारोबार और निवेश जैसे क्षेत्रों में अवसर पा सकते हैं। ड्रोन प्रशिक्षण के लिए डीजीसीए ने 63 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है, जिन्होंने 5,500 से अधिक रिमोट पायलट सर्टिफिकेट जारी किए हैं।

विशेषज्ञ की राय

पिछले कुछ सालों में स्पेस सेक्टर तेजी से बदला है। पहले अवसर इसरो तक सीमित थे, अब निजी कंपनियां भी रॉकेट बना रही हैं और उपग्रह लॉन्च कर रही हैं। युवाओं को यह सोचना चाहिए कि वे इस इकोसिस्टम के किस हिस्से में योगदान दे सकते हैं-डिजाइन, निर्माण, डाटा विश्लेषण या नीति-निर्माण! **-के राव, अधिकारी,** भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, देहरादून

इंजीनियरिंग की असली शुरुआत तब होती है, जब आप किसी विचार को हकीकत में उतारने लगते हैं। किताबें आपको सिद्धांत और बुनियादी बातें सिखाती हैं, लेकिन जब आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई वास्तविक चीज तैयार करते हैं, तभी पता चलता है कि उसे हकीकत में बदलना कितना चुनौतीपूर्ण है। **-पवन कुमार चंदना,** सह-संस्थापक, स्काईरूट एयरोस्पेस

जॉब/करियर

■ संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कंबाइन्ड जियो-साइंटिस्ट इग्जामिनेशन-2027 के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी किया गया है।
कुल पद : 127
अंतिम तिथि : 22 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन माध्यम से। यूपीएससी की वेबसाइट है - **upsc.gov.in**

■ कर्मचारी चयन आयोग जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। आवेदन प्रक्रिया जारी है।
कुल पद : 1748
अंतिम तिथि : 22 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। देखें यह वेबसाइट - **ssc.gov.in**

■ भारतीय स्टेट बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पद भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।
कुल पद : 207
अंतिम तिथि : 25 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन माध्यम से। बैंक की वेबसाइट है - **sbi.bank.in**

■ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के पद रिक्त हैं। आवेदन ऑनलाइन कर सकते है।
कुल पद : 225
अंतिम तिथि : 28 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है - **uiic.co.in**

■ बैंक ऑफ बड़ौदा में लोकल बैंक अधिकारी के पद भरे जाएंगे। योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
कुल पद : 2482
अंतिम तिथि : 17 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट देखें- **bankofbaroda.bank.in**

■ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में ग्रेजुएट, टेक्निशियन एवं ट्रेड अप्रेंटिस की रिक्तियां निकली हैं। प्रशिक्षण अवधि बारह माह होगी।
कुल पद : 326
अंतिम तिथि : 20 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट **rcfltd.com** पर लॉगइन करें।

■ जनपद बलरामपुर, उत्तर प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण परिक्षेत्रों में आंगनबाड़ी सहायिकाओं एवं कार्यकत्रियों के पद भरे जाएंगे। केवल महिला उम्मीदवार आवेदन की पात्र होंगी।
कुल पद : 495
अंतिम तिथि : 23 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। इस वेबसाइट **upanganwadibharti.in** पर जाएं।

■ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स (भारतीय डाक) ने ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर दी गई है।
कुल पद : 23,757
अंतिम तिथि : 19 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : ऑनलाइन। देखें यह वेबसाइट **indiapost.gov.in**

■ नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर में साइंटिफिक/टेक्निकल असिस्टेंट-ए के पद पर ऑनलाइन आवेदन का मौका है।
कुल पद : 376
अंतिम तिथि : 30 सितंबर 2026
आवेदन प्रक्रिया : वेबसाइट है- **nic.gov.in**

(नोट : आवेदन करने से पहले आधिकारिक वेबसाइट से अपने स्तर पर जांच कर लें)

भेजें अपना सवाल

करियर या शैक्षिक कोर्स संबंधी आपके मन में कोई उलझन है या कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें अपने सवाल नीचे दी गई ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ उसके जवाब देंगे। इस ईमेल आईडी का उपयोग करें **nayiraheincareer@gmail.com**

कमजोर अंग्रेजी के बावजूद यूपीएससी में कैसे सफल हों?

एक्सपर्ट टिप्स

डॉ. संजीब कुमार आचार्य
सीनियर करियर काउंसलर

■ **मैं हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी अंग्रेजी बेहद कमजोर है। अंग्रेजी में पास होने के लिए 300 अंक चाहिए। अंग्रेजी में पास होने के लिए कैसे तैयारी करूं?**
कुंदन कुमार

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अंग्रेजी का पेपर केवल क्वालिफाइंग है। इसलिए न्यूनतम अंक हासिल कर पेपर पास करने पर ध्यान दें और तैयारी की शुरुआत बुनियादी व्याकरण से करें। टेंस, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट-वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव और पैसिव वॉयस डायरेक्ट और इन्डायरेक्ट स्पीच तथा वाक्य-सुधार जैसे विषयों का नियमित रूप से अभ्यास करें। रोज लगभग 20-30 मिनट किसी सरल अंग्रेजी अखबार या आसान अंग्रेजी लेख को पढ़ें।

शुरुआत में हर शब्द का अर्थ समझने की कोशिश न करें। पहले पूरे वाक्य और लेख का समग्र अर्थ समझने पर ध्यान दें। धीरे-धीरे आपकी शब्दावली मजबूत होती जाएगी। एआई की मदद लें। यह व्याकरण सुधारने, शब्दावली बढ़ाने और अभ्यास कराने में मदद कर सकता है। रोज 100-150 शब्द लिखें और एआई से गलतियां सुधारने को कहें। धीरे-धीरे कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग का अभ्यास शुरू करें। पिछले वर्षों के यूपीएससी अंग्रेजी प्रश्नपत्रों को हल करें। इससे परीक्षा में पूछे जाने वाले अंग्रेजी के स्तर को समझने और अपनी कमजोरियों पहचानने में मदद मिलती है। नियमित मॉक टेस्ट दें और अपनी गलतियों की समीक्षा करें। छह से बारह महीने के नियमित अभ्यास से जरूरी स्तर तक पहुंचना संभव है। यूपीएससी की मुख्य तैयारी हिंदी में जारी रखें और अंग्रेजी पर इतना समय न दें कि सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय की तैयारी प्रभावित हो।

■ **मुझे आईआईटी से एमएससी या एमटेक करना है। कौन-कौन से आईआईटी एमएससी और एमटेक कराते हैं? अगर मैं आईआईटी से केवल एमएससी करूं, तो क्या एमएससी छात्रों का प्लेसमेंट अच्छा होता है?** **- निशा चौहान**

आईआईटी की डिग्री से करियर के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। हालांकि, सही विकल्प चुनने से पहले छात्रों को एमएससी और एमटेक के बीच का अंतर समझना चाहिए। कई आईआईटी में एमएससी के कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इनमें आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी (आईएसएम) धनबाद शामिल हैं। अधिकांश एमएससी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए संबंधित विषय में स्नातक डिग्री और आईआईटी जेएएम प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होता है।

आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, रुड़की, गुवाहाटी और हैदराबाद समेत प्रमुख आईआईटी में एमटेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं। प्रवेश के लिए संबंधित विषय में बीटेक/बीई या विज्ञान में मास्टर डिग्री और आमतौर पर वैध गेट स्कोर जरूरी होता है। एमएससी मुख्यतः विज्ञान और शोध पर केंद्रित है, जबकि एमटेक तकनीक और इंजीनियरिंग विशेषज्ञता के लिए है। एमएससी गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, कंप्यूटर साइंस व डाटा साइंस में रुचि रखने वालों के लिए है, जबकि एमटेक इंजीनियरिंग, एआई, सॉफ्टवेयर और डेटा साइंस में विशेषज्ञता चाहने वालों के लिए बेहतर रहेगा। आईआईटी से एमएससी के बाद डाटा साइंस, एनालिटिक्स, रिसर्च, टेक्नोलॉजी और शिक्षा में करियर के अवसर मिलते हैं। आगे पीएचडी भी की जा सकती है। हालांकि, सिर्फ आईआईटी की डिग्री से नौकरी तय नहीं होती। तकनीकी कौशल, प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और विशेषज्ञता भी महत्वपूर्ण हैं। विज्ञान, गणित और रिसर्च में रुचि हो तो एमएससी, जबकि टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता के लिए एमटेक बेहतर विकल्प हो सकता है। **(www.sanjibacharya.com)**

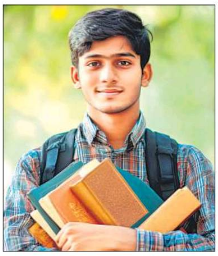

हिन्दुस्तान क्विज-22

हिन्दुस्तान अर्थात भारत की विकास यात्रा बहुआयामी रही है। इसी महायात्रा से हम पाठकों के लिए कुछ प्रश्न लेकर आए हैं, जो सामान्य ज्ञान के लिए उपयोगी हैं। पेश हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा के दस सवाल और उनके जवाब...

1. हिन्दुस्तान की वह कौन सी जगह है, जहां पर अंग्रेजों द्वारा बर्मा के आखिरी शासक को कैद / नजरबंदी में रखा गया था?
2. हिंदुस्तान के उस सम्राट का नाम बताएं, जिन्होंने श्रवणबेलगोला में संन्यासी जीवन बिताया?
3. आजादी पूर्व दिल्ली का लोदी गार्डन किस नाम से मशहूर था?

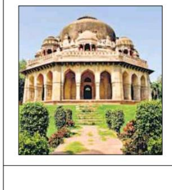

4. हिन्दुस्तान के किस वायसराय की पत्नी ने काजीरंगा रिजर्व फॉरेस्ट की स्थापना की थी?
5. मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल नामक महिला को हिन्दुस्तान में किस नाम से जाना जाता है?
6. किस मशहूर हिन्दुस्तानी गायिका का नाम उनके पिताजी द्वारा लिखे नाटक के चरित्र पर रखा गया था?
7. हिन्दुस्तान में धामेक स्तूप नामक प्रसिद्ध स्मारक कहां स्थित है?
8. भारतीय डाक विभाग द्वारा किस हिन्दुस्तानी को पहली बार डाक टिकट पर दर्शाया गया था?
9. हिन्दुस्तान में केवल एक ही महिला रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन शासक हुई है। उसका नाम क्या था?
10. भगवान विश्वकर्मा ने भगवान कृष्ण के कौन से दिव्य अस्त्र का निर्माण किया था?

उत्तर : 1. रत्नागिरी 2. चंद्रगुप्त मौर्य 3. लेडी विलिंगडन पार्क 4. लार्ड कर्जन की पत्नी ने 5. सिस्टर निवेदिता 6. लता मंगेशकर 7. सारनाथ 8. महात्मा गांधी 9. बेगम समरू (सरधना की शासक) 10. सुदर्शन चक्र

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्चों में वृद्धि होगी।

वृष : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर भी मिलेंगे। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी।

मिथुन : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। संयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।

कर्क : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। पिता और संतान की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। परिवार का साथ मिलेगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

सिंह : मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। वाणी के प्रभाव में वृद्धि होगी। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। किसी संपत्ति से आय के साधन बन सकते हैं।

कन्या : आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे, परंतु संयत रहें। धैर्यशीलता भी बनाए रखें। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ बढ़ेगी।

तुला : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं, परंतु आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नए कारोबार में निवेश कर सकते हैं। पिता और परिवार के किसी बुजुर्ग से धन मिल सकता है।

वृश्चिक : मन परेशान रहेगा। सेहत के प्रति सचेत रहें। संतान सुख में वृद्धि होगी। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी।

धनु : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्यक्षेत्र में वृद्धि के साथ स्थान परिवर्तन हो सकता है।

मकर : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु मन परेशान हो सकता है। कारोबार के लिए परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर जाना हो सकता है। खर्च बढ़ेंगे।

कुंभ : मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। संतान की सेहत का ध्यान रखें। शैक्षिक कार्यों में व्यवधान आ सकते हैं।

मीन : शैक्षिक कार्यों में मन लगेगा। परिवार में सुख-शांति रहेगी। अफसरों से व्यर्थ के वाद-विवाद से बचें। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

10 सितंबर, गुरुवार, **शक संवत्** : 19, भाद्रपद (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग** : 25, भाद्रपद मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 27, रबि-उल्लावल, 1448, **विक्रमी संवत्** : भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी तिथि प्रातः 10.34 मिनट तक पश्चात अमावस्या तिथि, मघा नक्षत्र दोपहर 02.05 मिनट तक पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, सिद्ध योग सायं 07.18 मिनट तक पश्चात साध्य योग, चन्द्रमा सिंह राशि में (दिन रात)। **सूर्य दक्षिणायन**। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 3 बजे तक राहुकालम्। पिठोरी अमावस। गंडमूल दोपहर 02.05 मिनट तक।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कौन से छोटे-छोटे संकेत हमें आने वाले समय के लिए आगाह करते हैं?

- घर में लाल चींटियां अधिक नजर आएं, तो यह बीमारियों का संकेत होता है।
- यदि घर में मकड़ी के अत्यधिक जाले बार-बार लगने लगे हैं और हटाने के बाद भी जल्द लग रहे हैं, तो यह आपके शत्रु बढ़ने का संकेत हो सकता है।
- यदि घर में कबूतर बहुत अधिक संख्या में आने लगे हैं, तो यह संकटों का संकेत हो सकता है। साथ ही आपके जीवन की स्थिरता भी प्रभावित हो सकती है।
- घर में छछूंदर का आना अनावश्यक खर्च एवं आर्थिक हानि का और चमगादड़ का बार-बार आना अशांति एवं नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है।

वर्ग पहेली : 8447

■	1	2		3	■	4	■	5
6	■		■	7				
8				■	■		■	
	■		■	9	■	■	10	
	■	11				12	■	
13		■	■		■		■	
	■	14	■	■	15			
16				17	■		■	
	■		■	18				■

बाएं से दाएं
1. धूमधाम से होने वाला उत्सव; बड़ा कार्यक्रम; भारी आयोजन (4)
7. बल खाता हुआ; लहराता हुआ; जोशीला (5)
8. बूंद-बूंद कर निकलना; गिरना (4)
10. कंगाल; गरीब; दरिद्र; धनहीन (2)
11. क्रोध से नथने फुलाना; घृणा प्रकट करना; हेय दृष्टि से देखना (2,3)
13. जनोपयोगी कार्य; लोक हितकारी काम; वैतनिक कार्य; नौकरी; खिदमत; टहल; परिचर्या (2)
15. परिक्षेत्र; परिधि; भवन क्षेत्र (4)
16. स्वलिखित; अपने हाथ का लिखा हुआ (5)
18. अनवरत; अविराम; निरंतर; बिना थके; सतत (4)

ऊपर से नीचे
2. छोड़ देना; बख्श देना; मुक्त करना; क्षमा करना; माफी देना (2,3)
3. समाधान; कृषियंत्र (2)
4. तह; पपड़ी; सतह; स्तर (3)
5. इहलोक त्यागना; परलोक जाना; स्वर्गवास हो जाना; मरना (4,4)
6. तड़क-भड़क के साथ रहना; सज-धज कर शान से रहना (2,2,1,3)
9. लाभ; बचा हुआ अंश; शेष (3)
12. नागरिक होने का भाव; निवासी होने का अधिकार (5)
14. कुंजी; चाबी; सारिणी; फेहरिस्त (3)
17. आधार; नीचे का भाग; पेंदा; हथेली (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8446

■	1 वा	2 द	वि	वा	3 द	क	4 र	ना
5 ग	■	म	■	■	या	■	सा	■
6 ब	ल	दा	य	7 क	■	8 सं	य	9 म
न	■	र	■	ल्प	■	■	10 न	द
क	■	■	11 चु	ना	व	■	■	द
12 र	13 वा	■	■	शी	■	14 दे	■	क
15 ना	म	क	■	16 ल	ह	र	दा	र
■	द	■	17 स	■	■	गा	■	ना
18 प	ल	ड़ा	भा	री	र	ह	ना	■

सुडोकू : 8401

*आसान

8	3						4	9
7	9			5			1	3
		5				8		
	8		9		2		7	
			4		8			
	6		5		3		8	
		4				7		
9	2			8			3	1
3	7						6	5

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8400

8	6	2	3	7	9	5	1	4
7	1	5	8	2	4	6	9	3
3	9	4	1	6	5	8	7	2
4	2	8	5	3	1	9	6	7
6	7	1	9	4	2	3	5	8
9	5	3	7	8	6	2	4	1
1	4	6	2	5	8	7	3	9
2	3	9	6	1	7	4	8	5
5	8	7	4	9	3	1	2	6

कल्पमेधा

तारों को छू लेने की चाह एक महत्त्वाकांक्षा है, जबकि दिलों को छू लेने की चाह अक्लमंदी है।
– माया एंजिलो

व्यवस्था पर सवाल

देश के तमाम छोटे-बड़े शहरों में ढांचागत विकास के साथ-साथ जर्जर और कमजोर इमारतों की समस्या भी भयावह रूप अख्तियार कर रही है। देश के अनेक शहरों में ऐसी इमारतें मौजूद हैं, जिनकी दीवारों में दरारें हैं, छतें कमजोर हो चुकी हैं और सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त भी नहीं हैं। इसके बावजूद इनमें लोग रह रहे हैं, दुकानें, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इन इमारतों की वजह से जब कोई बड़ा हादसा होता है, तो शासन-प्रशासन अचानक सक्रिय हो जाता है। जांच के आदेश दिए जाते हैं, कुछ कर्मियों का निलंबन होता है और मुआवजे की घोषणा की जाती है। फिर धीरे-धीरे सब कुछ उसी ढर्रे पर लौट आता है और इंतजार किया जाता है किसी दूसरे हादसे का। राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में एक छात्रावास की इमारत के ढहने से विद्यार्थियों समेत सात लोगों की मौत की घटना के बाद भी यही सब हो रहा है। दिल्ली सरकार ने एलान किया है कि पेइंग गेस्ट (पीजी) को कानूनी दायरे में लाने के लिए सुरक्षा नीति बनाई जाएगी। साथ ही शहर में अवैध निर्माणों को गिराने के आदेश जारी किए गए हैं।

अहम सवाल यह है कि हादसे के बाद हरकत में आने वाले सरकारी अमले को पहले कुछ दिखाई क्यों नहीं देता है? जर्जर एवं असुरक्षित भवनों के संभावित खतरे का पता लगाने और उनकी नियमित निगरानी करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता! बड़े शहरों में तो किसी इमारत का नक्शा पास होने से लेकर उसके बनने तक एक लंबी विभागीय प्रक्रिया होती है। नियमानुसार संरचनात्मक स्थिरता प्रमाण-पत्र और अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र समेत कई निर्धारित मानकों की जांच के बाद किसी इमारत के इस्तेमाल की अनुमति दी जाती है। इसके बाद भी भवनों की सुरक्षा एवं मजबूती को लेकर समय-समय पर उनकी जांच करने का प्रावधान है। अगर कोई इमारत जर्जर हालत में पाई जाती है, तो उसे असुरक्षित घोषित कर खाली कराया जाता है। जाहिर है कि इन तमाम नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। समस्या केवल भवन मालिकों की लापरवाही तक सीमित नहीं है। स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है। भवनों की नियमित जांच, संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन और असुरक्षित इमारतों को समय रहते खाली कराने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए।

सरकार अब पीजी सुरक्षा नीति लागू करने की तैयारी कर रही है। हालांकि राजधानी में इस तरह के प्रयास वर्ष 1993 से जारी हैं, लेकिन अभी तक ठोस नियम जमीनी स्तर पर लागू नहीं हो पाए हैं। ऐसे में जरूरत सिर्फ नीतियां या कानून बनाने की नहीं हैं, बल्कि उनका प्रभावी असर दिखे, यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है। पीजी में रहने वालों से मोटी रकम किराए में वसूली जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा को हाशिए पर डाल दिया जाता है। खासकर विद्यार्थियों को इस तरह की जोखिम भरी परिस्थितियों में इसलिए रहना पड़ता है, क्योंकि शिक्षा संस्थान उन्हें अपने स्तर पर छात्रावास उपलब्ध कराने में विफल रहते हैं। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की बात की जाए, तो इससे संबद्ध 77 में से 57 कालेजों में छात्रावास की सुविधा नहीं है। सवाल सिर्फ किसी एक शहर का नहीं है, बल्कि देश भर में उन हजारों जर्जर इमारतों का है, जिनका नियमों की परवाह किए बगैर व्यावसायिक इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बीते मंगलवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि वह देश भर में भवनों की सुरक्षा जांच के मसले पर विचार करेगा।

प्रदूषण की परवाह

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण-2026 का परिणाम एक ओर कुछ शहरों के लिए राहत भरा है, तो दूसरी ओर इसने कई शहरों की चिंता बढ़ा दी है। दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उत्तर प्रदेश के लखनऊ का पहला स्थान निश्चित ही उत्साह जगाता है, मगर इसी सूची में दिल्ली का 21वें पायदान पर होना और शीर्ष दस में हिमाचल प्रदेश के सिर्फ एक शहर का शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। पहाड़ों को हम स्वच्छ हवा, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता का पर्याय मानते रहे हैं और यदि वहां भी प्रदूषण की दस्तक तेज हो रही है, तो समस्या विकास को लेकर हमारे दृष्टिकोण की भी है। हालांकि, वायु गुणवत्ता में सुधार के मामले में चंडीगढ़ का उदाहरण महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2024 में वह 27वें स्थान पर था, 2025 में आठवें पायदान पर पहुंचा और अब सातवें स्थान पर है। जिन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, उसके पीछे कई कारण हैं। हरित क्षेत्र बढ़ाने, निर्माण स्थलों की धूल नियंत्रित करने, कचरे के वैज्ञानिक निपटान, इलेक्ट्रिक वाहनों और यातायात प्रबंधन जैसे उपायों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है।

सवाल सिर्फ यह नहीं है कि कौन-सा शहर सूची में ऊपर है, बल्कि यह भी महत्त्वपूर्ण है कि किस शहर ने सुधार की राह पर चलकर अपने नागरिकों के लिए हवा को स्वच्छ बनाया और कौन केवल कागजी आंकड़ों में ही उलझा रहा। पहाड़ी प्रदेशों में वायू प्रदूषण का बढ़ाना भी गंभीर चिंता पैदा करता है। हैरत की बात है कि हिमाचल का इकलौता शहर कांगड़ा का डमटाल ही स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की सूची में शीर्ष दस में जगह बना पाया है। यह इस बात का संकेत है कि अगर समय रहते नहीं चेते, तो पर्यटन, निर्माण, यातायात और कचरे का दबाव पहाड़ों की हवा को सांस लेने योग्य नहीं छोड़ेगा। सवाल यह भी है कि आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारें, नगर निकाय, प्रदूषण नियंत्रण संस्थाएं, उद्योग, वाहन या फिर आम नागरिक। इसमें दोराय नहीं कि प्रदूषण को कम करने में सभी की भागीदारी जरूरी है, लेकिन नीति निर्माताओं और कानून प्रवर्तन एजंसियों की जिम्मेदारी अधिक है। स्वच्छ हवा सभी नागरिकों का अधिकार है और इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जाने की जरूरत है।

पूर्वाग्रहों की परतों में पलती संकीर्णता

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी नींव विविधता के सम्मान पर टिकी है। मगर कई बार पूर्वोत्तर के लोगों के प्रति नकारात्मक पूर्व-धारणाएं अफसोसनाक और चिंताजनक हालात पैदा करती हैं।

गिरीश पंकज

पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश की घाटियों से गूंजी एक नन्ही बच्ची कार्गा टिंकल गोंगो की तोतली आवाज ने पूरे देश के अंतर्मन को झकझोर कर रख दिया था। अपने मासूम चेहरे, खिलखिलाती मुस्कान और तुतलाती जुबान में उसने हाथ जोड़कर पूरे अधिकार से राष्ट्रगान गाया और फिर सहज भाव से यह गुहार लगाई कि 'हमको चीनी मत बोलो, इंडिया बोलो'। उसकी अनुगूंज अभी शांत भी नहीं हुई थी कि छह सितंबर की रात दिल्ली में मणिपुर के प्रख्यात गिटारवादक चोंगथाम विक्रम सिंह की हत्या ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के लोगों को दुख पहुंचाया। इस घटना के विरोध में मणिपुर की युवा पीढ़ी में गहरा आक्रोश है। समय-समय पर पूर्वोत्तर के लोगों को लेकर उत्तर भारत के कुछ अल्पज्ञ लोगों की मानसिकता विचलित करती है। जबकि पूर्वोत्तर के लोग न केवल इस देश से, बल्कि यहां की भाषा से भी प्यार करते हैं। मणिपुरी साहित्य का हिंदी में अनुवाद करने वाले कम नहीं हैं। इसी वर्ष जनवरी माह में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास नई दिल्ली द्वारा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में वहां के लेखकों के साथ एक नवलेखन कार्यशाला आयोजित हुई थी। वहां अरुणाचल का लगभग हर व्यक्ति भलीभांति हिंदी बोल रहा था, समझ रहा था। मणिपुर में भी हिंदी प्रेमियों की कमी नहीं। वहां विश्वविद्यालय में हिंदी का अध्ययन हो रहा है। वहां के लोग विशुद्ध रूप से अपने आप को हिंदुस्तान से ही जुड़ा महसूस करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर भारत के कुछ लोग नादानीवश वहां के लोगों के रंगरूप को देखकर कुछ और दुराग्रह पाल लेते हैं।

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी नींव विविधता के सम्मान पर टिकी है। यहां भाषा, खान-पान, वेशभूषा और शारीरिक बनावट हर कुछ सौ किलोमीटर पर बदल जाती है। इसके बावजूद, यह अफसोस की बात है कि जब उत्तर-पूर्व का कोई नागरिक देश के अन्य राज्यों, विशेषकर दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु या कोलकाता जैसे महानगरों में कदम रखता है, तो उसे अक्सर तिरछी और अजनबी नजरों का सामना करना पड़ता है। चेहरे की बनावट, विशेषकर 'मंगोली' नैन-नक्श के कारण उन पर कुछ अपमानजनक टिप्पणियां करना एक आम विकृति बन चुकी है। किराए पर मकान ढूंढ़ने से लेकर शैक्षणिक संस्थानों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक परिवहन तक, पूर्वोत्तर के युवाओं को लगातार यह अहसास कराया जाता है कि वे 'यहां के नहीं हैं'! जब उन्हें विदेशी कहकर पुकारा जाता है, तो उनके भीतर एक गहरी मनोवैज्ञानिक टूटन पैदा होती है।

अरुणाचल प्रदेश, जिसे 'उगते सूरज की भूमि' कहा जाता है, भारत का वह सीमांत प्रहरी है, जो देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात अडिग खड़ा रहता है। यहां के लोग प्रतिकूल परिस्थितियों, कठोर मौसम और पड़ोसी देशों की विस्तारवादी गिद्ध-दृष्टि के बावजूद पूरे गर्व से सीना तानकर भारतीय होने का जयघोष करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र देश की सुरक्षा व्यवस्था का सबसे संवेदनशील और महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। असम का बिहू, नगालैंड का हार्नबिल, मणिपुर की रासलीला, मिजोरम का चेराव और अरुणाचल के जीवंत जनजातीय उत्सव भारत की सांस्कृतिक पूंजी को अद्वितीय बनाते हैं।

पूर्वोत्तर के लोग जब सीमा पर भारतीय सेना के साथ मिलकर 'जय हिंद' का नारा लगाते हैं, तो उनकी देशभक्ति पर संदेह करना या उन्हें सिर्फ उनके चेहरे के आधार पर 'पराया' समझ लेना राष्ट्र के प्रति एक नैतिक अपराध के समान है। पूर्वोत्तर के प्रति मुख्यधारा के समाज में व्याप्त इस भेदभाव की जड़ें नफरत से ज्यादा गहरी अज्ञानता में हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली और सामाजिक विमर्श में पूर्वोत्तर को कभी वह स्थान मिला ही नहीं, जिसका वह हकदार था।

> राष्ट्र की अवधारणा किसी चेहरे की लंबाई, आंखों के आकार या त्वचा के रंग से तय नहीं होती। राष्ट्र का निर्माण उन साझा मूल्यों, संविधान और भावनात्मक जुड़ाव से होता है, जो नागरिकों को एक सूत्र में पिरोते हैं। विडंबना देखिए कि जब ओलंपिक या अंतरराष्ट्रीय खेलों में मैरी काम, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन देश के लिए पदक जीतकर तिरंगा लहराती हैं, तब सभी भारतीय गर्व से सीना फुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंच से नीचे उतरती हैं, उसी क्षेत्र के एक आम छात्र को दिल्ली या बंगलुरु की सड़कों पर अपनी पहचान के लिए जूझना पड़ता है। यह अब जरूरी हो गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों, लोककथाओं और भूगोल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए।

दशकों तक हमारे स्कूली इतिहास और भूगोल की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर गंगा-यमुना के मैदानों तक का विवरण तो विस्तार से पढ़ाया गया, लेकिन अहोम साम्राज्य, लचित बोरफुकन का पराक्रम, रानी गाइदिनल्यू का संघर्ष, ब्रिटिश सेना को रोकने वाले तिरोत सिंग और माटीमुर्ती कनकलता बरुआ के बलिदानों को एक-दो पन्नों में समेट दिया गया। दिल्ली या मध्य भारत में बैठे औसत नागरिक को यह तक ठीक से ज्ञात नहीं होता कि पूर्वोत्तर के आठ राज्यों, जिन्हें 'अष्टलक्ष्मी' भी कहा जाता है, उनकी राजधानियां, भाषाएं और जनजातीय परंपराएं क्या हैं। जब तक देश का समाज यह नहीं समझेगा कि भारत सिर्फ आर्य और द्रविड़ बनावट तक सीमित नहीं है, बल्कि 'मंगोलायड' और 'आस्ट्रो-एशियाटिक' नस्लें भी इस मिट्टी की उतनी ही सच्ची संतानें हैं, तब तक कार्गा टिंकल जैसी बच्चियों को अपने भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ेगा।

वर्ष 2014 में दिल्ली के लाजपत नगर में अरुणाचल प्रदेश के 19 वर्षीय छात्र निडो तानिया की उसके बालों और नैन-नक्श पर फब्तियां कसने के बाद पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। कोविड-19 महामारी के दौरान पूर्वोत्तर के नागरिकों के साथ हुए दुर्व्यवहार, उन्हें किराए के घरों से निकाले जाने और उन पर छींटाकशी किए जाने की घटनाएं यह साबित करती हैं कि हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी गंभीर पूर्वाग्रहों का बंधक है। राष्ट्र की अवधारणा किसी चेहरे की लंबाई, आंखों के आकार या त्वचा के रंग से तय नहीं होती। राष्ट्र का निर्माण उन साझा मूल्यों, संविधान और भावनात्मक जुड़ाव से होता है, जो नागरिकों को एक सूत्र में पिरोते हैं।

विडंबना देखिए कि जब ओलंपिक या अंतरराष्ट्रीय खेलों में मैरी काम, मीराबाई चानू या लवलीना बोरगोहेन देश के लिए पदक जीतकर तिरंगा लहराती हैं, तब सभी भारतीय गर्व से सीना फुलाते हैं, लेकिन जैसे ही वे मंच से नीचे उतरती हैं, उसी क्षेत्र के एक आम छात्र को दिल्ली या बंगलुरु की सड़कों पर अपनी पहचान के लिए जूझना पड़ता है। यह अब जरूरी हो गया है कि प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक की पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर के इतिहास, स्वतंत्रता सेनानियों, लोककथाओं और भूगोल को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसी पहलों को केवल सरकारी आयोजनों तक सीमित न रखकर स्कूलों, विश्वविद्यालयों और युवा मंडलों के बीच नियमित विनिमय कार्यक्रमों के रूप में जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। भारतीय सिनेमा और धारावाहिकों में पूर्वोत्तर के कलाकारों को रूढ़िवादी किरदारों से बाहर निकालकर मुख्यधारा की भूमिकाओं में समान अवसर दिया जाए। कार्गा टिंकल गोंगो की तोतली जुबान ने देश को जो संदेश दिया है, वह एक चेतावनी भी है और एक विनम्र आह्वान भी।

अब समय आ गया है कि हम अपनी संकीर्ण दृष्टि को त्यागें। कार्गा टिंकल की मासूम पुकार का वास्तविक सम्मान तभी होगा, जब किसी भी भारतीय को यह साबित न करना पड़े कि वह विदेशी नहीं, बल्कि इस भारत भूमि का सच्चा सपूत है। मणिपुर के जाने-माने गिटारवादक विक्रम सिंह इसी देश के नागरिक थे। उनके साथ दिल्ली में जो हुआ, वह एक तरह से अलगाव को बढ़ावा देता है। एक व्यक्ति या उसका समाज अगर किसी भी समुदाय के प्रति पूर्वाग्रह या दुराग्रह रखता है, तो इसका नुकसान केवल उसे नहीं, बल्कि उसके समाज और देश को भी उठाना पड़ता है।

तुलना का पैमाना

दुनिया मेरे आगे

शिशिर शुक्ला

तुलना मानव जीवन की सबसे सहज, लेकिन सबसे घातक प्रवृत्तियों में से एक है। संसार में जन्म लेने के साथ ही हम तुलना के समांतर जगत में भी प्रवेश कर जाते हैं। जीवन के लगभग हर पड़ाव पर हमारे हाथ में एक अदृश्य मापनी थमा दी जाती है- 'तुलना की मापनी'। धीरे-धीरे हम स्वयं को अपने भीतर से नहीं, बल्कि दूसरों के संदर्भ में देखना सीख जाते हैं। यही वह क्षण है, जब हमारा आत्ममूल्य अंतस की मापनी को छोड़कर बाहरी पैमानों का मोहताज होने लगता है। स्वस्थ तुलना बुरी नहीं है। समस्या तब उत्पन्न होती है, जब यही तुलना प्रेरणा की जगह हीनता, ईर्ष्या, असंतोष और आत्मग्लानि को जन्म देने लगती है। ऐसी दशा में तुलना व्यक्ति को ऊपर उठाने के बजाय भीतर से खोखला करने लगती है।

हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि प्रत्येक मनुष्य की यात्रा अलग है। दो व्यक्तियों के सामने दिखाई देने वाले परिणाम समान हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की परिस्थितियां कभी समान नहीं होतीं। सत्य यह है कि हम केवल किसी के जीवन के दृश्य भाग से ही परिचित हो पाते हैं, उसका अदृश्य संघर्ष हम नहीं देख सकते। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को अपनी असफलताओं की मापनी बना लेना एक बड़ी और हानिकारक मानसिक भूल है। किसी के जीवन की द्युतिमान तस्वीर के पीछे छिपी बेचैनी, संघर्ष, ऋण, असफलताएं, पारिवारिक तनाव या अकेलापन दिखाई नहीं देता। परिणाम यह होता है कि हम अपने वास्तविक जीवन की तुलना दूसरों के जीवन के उस पहलू से करने लगते हैं, जो हमें दिख रहा होता है। यह तुलना स्वाभाविक रूप से हमें असंतोष की ओर ले जाती है।

अगर तुलना करनी ही है, तो सबसे सार्थक तुलना अपने कल के व्यक्तित्व से होनी चाहिए। आज मैं कल से कितना बेहतर हूं? मेरे विचारों में कितना परिष्कार हुआ? मेरे व्यवहार में कितनी विनम्रता आई? मैंने क्रोध पर कितना नियंत्रण पाया? मैंने अपने कर्तव्यों को कितनी ईमानदारी से निभाया? मैंने किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए क्या किया? उपलब्धि की परिभाषा यह नहीं कि हम किसी दूसरे से आगे निकल गए, बल्कि यह है कि हमने स्वयं को कल से बेहतर बना लिया। प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव दूसरे से भिन्न होता है। आम के बीज से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह गुलाब की तरह खिले।

> जीवन में हर व्यक्ति की समय-तालिका अलग होती है। जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होता। तुलना का मूल कारण भीतर का असंतोष होता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को केवल बाहरी पहचान से जोड़ना बंद कर देता है, तब तुलना की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है।

जीवन में हर व्यक्ति की समय-तालिका अलग होती है। कोई बीस वर्ष की उम्र में सफल हो जाता है, कोई चालीस में, कोई साठ में और कोई शायद कभी उस अर्थ में सफल नहीं होता, जिसे समाज सफलता कहता है। क्या इसका अर्थ यह है कि उसका जीवन व्यर्थ हो गया? बिल्कुल नहीं। जीवन का मूल्य केवल उपलब्धियों से निर्धारित नहीं होता। तुलना का मूल कारण भीतर का असंतोष होता है। जब व्यक्ति अपने अस्तित्व को केवल बाहरी पहचान से जोड़ना बंद कर देता है, तब तुलना की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। फिर दूसरे की सफलता ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेरणा का कारण बनती है। दूसरे की प्रशंसा अपने अपमान का प्रतीक महसूस नहीं होती।

संतोष का अर्थ है प्रयास करते हुए भी परिणाम के प्रति भीतर से टूट न जाना। व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए पूरी मेहनत करे, अपनी कमियों को दूर करे, ऊंचाइयों को प्राप्त करने का प्रयास करे, लेकिन किसी भी दशा में अपनी आत्मशांति को उपलब्धियों की शर्त न बनाए। जीवन को केवल उपलब्धियों की सूची बनाकर देखना ठीक उसी प्रकार है, जैसे किसी संगीत को केवल उसकी अवधि से मापना। किसी गीत की सुंदरता उसकी अवधि में नहीं, उसकी अनुभूति में होती है। हमें समझना होगा कि सबसे कठिन प्रतियोगिता बाहर नहीं, भीतर है। क्रोध से धैर्य की ओर जाना, अहंकार से विनम्रता की ओर जाना, भय से विश्वास की ओर जाना, लोभ से संतोष की ओर जाना और स्वार्थ से सेवा की ओर जाना- यही वास्तविक विजय है। इस यात्रा में किसी दूसरे को हराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां विजेता और पराजित दोनों एक ही व्यक्ति होता है और वह है स्वयं हम।

खुशहाली के लिए जीवन की मापनी बदलने की आवश्यकता है। यह मापनी होनी चाहिए- चरित्र की, आत्मशांति की और आत्मतोष की। जीवन की सबसे सुंदर स्थिति वह है, जब मनुष्य दूसरों को देखकर यह नहीं सोचता कि 'मैं उनसे कितना पीछे हूं?', बल्कि स्वयं से यह प्रश्न करता है- 'मैं उनसे क्या सीख सकता हूं... क्या आज मैं कल से थोड़ा बेहतर मनुष्य बना?' ये प्रश्न जीवन की दिशा बदल सकते हैं। तुलना की मापनी बाहर से भीतर की ओर मोड़नी होगी। अपने जीवन का मूल्यांकन हमें स्वयं करना होगा। मापनी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें मनुष्य किसी दूसरे से बड़ा नहीं, बल्कि अपने भीतर से बेहतर बनने का प्रयास करे। जहां सफलता का अर्थ किसी को पीछे छोड़ना नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार को थोड़ा कम करना हो।

जहां समृद्धि का अर्थ केवल संग्रह नहीं, बल्कि बांटने की क्षमता हो। जहां ऊंचाई का अर्थ पद नहीं, दृष्टि की ऊंचाई हो। और जहां जीवन का अंतिम प्रश्न यह न हो कि 'मैं दूसरों से कितना आगे था?', बल्कि यह हो कि 'मैं अपने होने को कितना सार्थक कर पाया?' जब तुलना समाप्त होती है, तो आत्मबोध शुरू होता है और जब आत्मबोध शुरू हो जाता है, तब मनुष्य समझ पाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, एक यात्रा है। कोई परीक्षा नहीं, एक अनुभव है। कोई मापनी नहीं, एक साधना है। इस साधना में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि यात्रा पूरी होने पर हम स्वयं से कह सकें- 'मैंने किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं की, मैंने पूरी निष्ठा से स्वयं बनने का प्रयास किया। मैंने सदैव बाहरी परिस्थितियों एवं दूसरों की उपलब्धियों से अपने अंतर्मन को विरत रखते हुए आत्मोन्नति एवं आत्मपरिष्कार की चेष्टा की।' स्वयं से तुलना और फिर सार्थक प्रयास ही आत्मविकास का एकमात्र आधार है।

गुम होता बचपन

इन दिनों दुनिया भर में बच्चों के बढ़ते 'स्क्रीन टाइम' को लेकर चिंता बढ़ रही है। जिस मोबाइल फोन को कभी सुविधा और ज्ञान का साधन माना गया था, अब वही बचपन को लील रहा है। आस्ट्रेलिया ने सोलह वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, कनाडा, इटली, पुर्तगाल और दक्षिण कोरिया सहित अनेक देश बच्चों की डिजिटल दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत भी अब इस बहस से बाहर नहीं है। मुद्दा केवल मोबाइल फोन देखने में बीतने वाले समय का नहीं है, बल्कि उस दौरान बच्चे के दिमाग पर पड़ने वाले प्रभाव का भी है। समस्या यह है कि स्क्रीन बच्चे से केवल समय नहीं छीनती, वह खेल का मैदान, किताब, परिवार से बातचीत, नींद और उसकी कल्पनाशक्ति को पीछे धकेल देती है। सवाल तकनीक को बच्चों से छीनने का नहीं, बल्कि बचपन को तकनीक के प्रभाव से बचाने का है। पढ़ाई के लिए डिजिटल साधन चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाजार के लिए बच्चा एक ग्राहक हो सकता है, लेकिन माता-पिता और सरकार के लिए उसका भविष्य जरूरी है।

– विभूति बुपक्या, दिल्ली

उपेक्षित होते बुजुर्ग

'बुजुर्गों की सुध' (संपादकीय, 9 सितंबर) पढ़ा। परिवार की नींव रखने वाले बुजुर्ग आज उपेक्षा, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं। पारिवारिक ढांचे में आए बदलाव, संयुक्त परिवारों का विघटन और उपभोक्तावादी सोच ने बुजुर्गों को हाशिए पर ला दिया है। उनके साथ शारीरिक हिंसा और मानसिक प्रताड़ना बढ़ी है। वृद्धाश्रमों में भी उनकी उपेक्षा हो रही है। आज देश में साठ वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या दस करोड़ से अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में आधे बुजुर्ग दुर्व्यवहार के शिकार हैं। लिहाजा विद्यालयों से लेकर सामाजिक मंचों तक बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता की शिक्षा दी जानी चाहिए। बच्चों को शुरू से ही बड़ों का आदर करना सिखाया जाना चाहिए। बुजुर्गों के साथ समय बिताना, उनकी बातों को सुनना और निर्णयों में उन्हें शामिल करना जरूरी है। वे हमारे लिए अतीत के संरक्षक भविष्य के पथप्रदर्शक और सम्मानीय हैं।

– हिमांशु शेखर, गयाजी

लापरवाही की कड़ियां

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत का ढहना महज एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हमारी शहरी व्यवस्था के चरमराते ढांचे की भयावह तस्वीर है। इस हादसे में सात लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की त्रासदी के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार किसी इमारत का पहले गिरना जरूरी है और तभी व्यवस्था जागेगी? आखिर दुर्घटना के बाद ही प्रशासन सक्रिय क्यों होता है। मौके पर अधिकारी पहुंचते हैं, राहत-बचाव शुरू होता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिलता है। फिर सियासी आरोप-प्रत्यारोप का अध्याय खुलता है। कुछ दिनों बाद मलबा हट जाता है और मामला फाइलों में दब जाता है। असल विडंबना यह है कि हमारी व्यवस्था हादसे के बाद बहुत सक्रिय और हादसे से पहले लगभग निष्क्रिय दिखाई देती है। पुराने भवनों की नियमित जांच अब अनिवार्य रूप से लागू की जानी चाहिए।

– इशरत अली कादरी, भोपाल

जमाखोरी की समस्या

पिछले करीब एक महीने में देश में चीनी के दाम बढ़े हैं। इससे सभी वर्ग प्रभावित हुए हैं। मूल्यवृद्धि रोकने के लिए समय रहते कदम उठाना चाहिए था। सरकार चेत जाती, तो दामों को काबू में किया जा सकता था। जिस तरह से चीनी के दाम बढ़े हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि आने वाले त्योहारों के दौरान इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। इसका एक कारण एथेनाल बताया जा रहा है। एथेनाल बनाने में मक्के का खूब इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके अलावा गन्ने का भी काफी उपयोग होता है। बेहतर होता कि सरकार इस पर स्थिति स्पष्ट करती। अब समय आ गया है कि चीनी की जमाखोरी पर नियंत्रण किया जाए। जो लोग इस तरह के अवैध कारोबार में संलिप्त है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, ताकि जमाखोरी के कारण आवश्यक वस्तुओं के दाम न बढ़ें।

– एमएम राजावत राज, शाजापुर

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

चिंतन

अर्थव्यवस्था पर दबाव डालेगा कच्चे तेल का बढ़ता मूल्य

मध्य-पूर्व में बढ़े तनाव के बीच कच्चे तेल का 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंचना भारत के लिए किसी मामूली आर्थिक खबर की तरह नहीं देखा जा सकता। भारत की अर्थव्यवस्था भले ही आज पहले के मुकाबले अधिक मजबूत और सक्षम हो, लेकिन उसकी ऊर्जा जरूरतों की एक बड़ी निर्भरता अब भी आयातित तेल पर है। इसलिए दुनिया के किसी हिस्से में युद्ध या तनाव बढ़ता है और कच्चे तेल की कीमत 100 डॉलर के पार जाती है तो उसकी तपिश भारत के बाजार से लेकर आम आदमी की रसोई तक महसूस की जा सकती है। दिलचस्प यह है कि महंगे तेल की यह चुनौती ऐसे समय आई है जब भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी मजबूती का शानदार प्रदर्शन किया है। अप्रैल से जून की तिमाही में भारत की जीडीपी 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। यह आंकड़ा बताता है कि घरेलू मांग, विनिर्माण और सेवाओं के दम पर भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी तेज गति से आगे बढ़ रही है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का सबसे पहला और सीधा असर महंगाई पर पड़ता है। पेट्रोल और डीजल केवल कार और मोटरसाइकिल चलाने के लिए जरूरी नहीं हैं। देश में माल ढुलाई से लेकर कृषि, निर्माण और उद्योग तक का बड़ा हिस्सा पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर है। महंगाई का सबसे ज्यादा दबाव उस मध्यवर्ग पर पड़ता है जिसके पास इससे बचने के सीमित रास्ते हैं। दूसरी बड़ी चिंता रुपये पर दबाव है। भारत कच्चे तेल के लिए डॉलर में भुगतान करता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का अर्थ है कि समान मात्रा में तेल खरीदने के लिए भारत को अधिक डॉलर खर्च करने होंगे। इससे डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव आ सकता है। रुपया कमजोर हुआ तो तेल के साथ-साथ कई दूसरे आयात भी महंगे हो सकते हैं। इसका असर उद्योगों की लागत और अंततः उपभोक्ता कीमतों पर दिखाई देगा। तीसरा असर देश के चालू खाते और व्यापार घाटे पर पड़ सकता है। महंगे तेल का मतलब बड़ा आयात बिल है। भारत को जितना ज्यादा पैसा तेल के आयात पर खर्च करना पड़ेगा, उतना ही दबाव उसके बाहरी क्षेत्र पर बढ़ेगा। हालांकि भारत का मजबूत सेवा निर्यात और विदेशी मुद्रा भंडार इस झटके को सहने की क्षमता देते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महंगे तेल का कोई असर नहीं होगा। सरकार के सामने सबसे कठिन सवाल घरेलू ईंधन कीमतों को लेकर होगा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने के बावजूद यदि पेट्रोल-डीजल की कीमतों को स्थिर रखा जाता है तो तेल विपणन कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। यदि कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो आम उपभोक्ता पर बोझ बढ़ेगा। सरकार को इन दोनों के बीच ऐसा संतुलन बनाना होगा जिससे न तो कंपनियों की वित्तीय स्थिति बिगड़े और न ही महंगाई को अनावश्यक ईंधन मिले। दुनिया में जब भी भू-राजनीतिक तनाव बढ़ेगा, तेल की कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था की परीक्षा लेंगी। इसका स्थायी समाधान केवल कीमतों को नियंत्रित करना नहीं, बल्कि आयातित तेल पर निर्भरता घटाना है। ऊर्जा के स्रोत जितने विविध होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था उतनी ही सुरक्षित होगी। फिलहाल तस्वीर के दोनों पहलू सामने हैं। एक तरफ 7.8 प्रतिशत की तेज आर्थिक वृद्धि भारत की मजबूती की कहानी कह रही है, दूसरी तरफ 100 डॉलर का कच्चा तेल दुनिया की अस्थिरता की याद दिला रहा है। चुनौती यह है कि तेल की आग विकास की रफ्तार तक न पहुंचे। भारत ने आर्थिक मजबूती हासिल करने में लंबा सफर तय किया है। अब परीक्षा इस बात की है कि वह वैश्विक ऊर्जा झटकों से अपनी इस रफ्तार को कितनी कुशलता से बचा पाता है।

मुद्दा
प्रणय कुमार

मानवता व विरोध का वैचारिक ईकोसिस्टम

> पश्चिमी समाजों में वाम-उदारवादी विचारधारा और कट्टरपंथी–जिहादी राजनीति के बीच बढ़ता वैचारिक सामंजस्य स्वतंत्रता, बहुलता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की व्याख्या को भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। जिस अमेरिका ने दशकों तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने लोकतंत्र की आत्मा और असहमति के अधिकार को अपनी सभ्यतागत पहचान बताने का दंभयुक्त दावा किया, उसी अमेरिका में अब किसी विचार, संगठन अथवा व्यक्ति की स्वीकार्यता कई बार इस बात से तय होती दिखाई देती है कि वह उसके प्रचलित वैचारिक आख्यान के अनुकूल है या उसके प्रतिकूल। न्यूयॉर्क में आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' इसी बदलते विमर्श का उल्लेखनीय उदाहरण है।

मानवाधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और परमाणु अप्रसार जैसे मुद्दों पर पश्चिमी जगत लंबे समय से स्वयं को वैश्विक नैतिकता का पहरेदार बताता आया है। जब इन्हीं आदर्शों को वास्तविक आचरण की कसौटी पर परखा जाता है, तो कथित नैतिक श्रेष्ठता के पीछे छिपे उसके दोहरे मापदंड बार-बार उजागर होते हैं। विडंबना यह है कि यह विरोधाभास अब केवल उसकी विदेश नीति अथवा वैश्विक राजनीति तक सीमित नहीं रहा। पश्चिमी समाजों में वाम-उदारवादी विचारधारा और कट्टरपंथी-जिहादी राजनीति के बीच बढ़ता वैचारिक सामंजस्य स्वतंत्रता, बहुलता, धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की व्याख्या को भी प्रभावित करता दिखाई दे रहा है। जिस अमेरिका ने दशकों तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपने लोकतंत्र की आत्मा और असहमति के अधिकार को अपनी सभ्यतागत पहचान बताने का दंभयुक्त दावा किया, उसी अमेरिका में अब किसी विचार, संगठन अथवा व्यक्ति की स्वीकार्यता कई बार इस बात से तय होती दिखाई देती है कि वह उसके प्रचलित वैचारिक आख्यान के अनुकूल है या उसके प्रतिकूल। न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पिछले दिनों आयोजित 'यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन' इसी बदलते विमर्श का उल्लेखनीय उदाहरण है।

विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच संवाद, सह-अस्तित्व और सार्वभौमिक एकता का संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत का संबोधन हुआ। आयोजन 'अमेरिकन हिंदूज़ फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग' द्वारा किया गया था और इसे विभिन्न हिंदू-अमेरिकी संगठनों का समर्थन प्राप्त था। अमेरिका के लगभग 39 राज्यों, 853 शहरों तथा 31 देशों से आए लगभग 6,000 प्रतिनिधियों और 250 से अधिक हिंदू-अमेरिकी संगठनों की सहभागिता ने इसकी व्यापकता को रेखांकित किया। इसके बावजूद न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने कार्यक्रम के प्रति सार्वजनिक असहमति जताई और 61 संगठनों ने कार्यक्रम रद्द करने की मांग की। कार्यक्रम अंततः संपन्न हुआ और अपने घोषित उद्देश्य में पूर्णतया सफल रहा, लेकिन इससे एक मूलभूत लोकतांत्रिक प्रश्न उठा, क्या किसी वक्ता को सुने बिना ही उसके विचारों और संगठन को 'बहिष्कारी' अथवा अस्वीकार्य घोषित कर देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बहुलतावाद की उस उदार परंपरा के अनुरूप है, जिन्हें पश्चिम लंबे समय से वैश्विक मानक के रूप में प्रस्तुत व प्रचारित करता रहा है? विरोध की इस शृंखला में 'हिंदूज़ फॉर ह्यूमन राइट्स' (एचएफएचआर) भी प्रमुख रूप से सक्रिय था। घोर आश्चर्य है कि जिस संगठन के नाम के साथ 'हिंदूज' जुड़ा है, वह भारत, हिंदुत्व और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े मुद्दों पर आलोचनात्मक अभियानों का संचालन करता रहा है। इस संगठन के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसके सलाहकार सदस्यों में तीस्ता सीतलवाड़, फादर आनंद मैथ्यू, सैयदा हमीद, स्वरा भास्कर, अपूर्वानंद, हर्ष मंदर आदि के नाम सम्मिलित हैं। इससे सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि संघ-प्रमुख मोहन भागवत के कार्यक्रम के विरुद्ध वह क्यों खड़ी थीं?

विरोध करने वाले 61 संगठनों की सूची में 'इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल' (आईएएमसी), 'जस्टिस फॉर ऑल', 'इंटरफेथ सेंटर ऑफ न्यूयॉर्क' सहित अनेक धार्मिक, नागरिक अधिकार और एक्टिविस्ट संगठन दिखाई देते हैं। आईएएमसी और इसके प्रमुख मुहम्मद जवाद भारत में हिंदुत्व, संघ और मोदी सरकार से जुड़े मुद्दों पर लंबे समय से विरोधी अभियान चलाते रहे हैं। गाजा और इजरायल के प्रश्न पर भी उनका रुख अत्यंत मुखर रहा है। 'जस्टिस फॉर ऑल' के अध्यक्ष अब्दुल मलिक मुजाहिद लंबे समय से अमेरिकी मुस्लिम एक्टिविज्म और अंतर्धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इसी संदर्भ में न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की भूमिका भी प्रश्नों के घेरे में आती है। वे भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा इजरायल से जुड़े प्रश्नों पर भी मुखर राजनीतिक रुख अपनाते रहे हैं।

इसलिए यह पूछना असंगत नहीं होगा कि उनकी निष्ठा लोकतांत्रिक परंपराओं व मान्यताओं में है या मज़हबी रिवाजों, तक़रीरों व यकीनों में? विरोध के इसी क्रम में 26 अगस्त को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (यूएससीआईआरएफ) के अध्यक्ष आसिफ महमूद द्वारा डॉ. मोहन भागवत की अमेरिका यात्रा के संदर्भ में भारत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगाए गए गंभीर आरोप तथा संघ से जुड़े लोगों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के समर्थन ने इस विमर्श के पीछे सक्रिय टूलकिट की सच्चाई सामने रखी। भारत पर आयोग के पूर्ववर्ती वक्तव्यों और सुनवाइयों में सीएए, एनआरसी, जम्मू-कश्मीर, उमर खालिद और शरजील इमाम जैसे विषयों को धार्मिक स्वतंत्रता के विमर्श से जोड़ा जाता रहा है। इस पूरी शृंखला को केवल अलग-अलग संगठनों की स्वतंत्र प्रतिक्रियाओं के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। न्यूयॉर्क की स्थानीय राजनीति, एक्टिविस्ट संगठनों, भारत-केंद्रित मुस्लिम एवं मानवाधिकार समूहों और धार्मिक-स्वतंत्रता संस्थाओं की भूमिकाओं को एक साथ रखने पर एक ऐसा वैचारिक ईकोसिस्टम दिखाई देता है, जिसमें अलग-अलग मंचों से उठने वाले आरोप और नैरेटिव कई बार एक-दूसरे को पुष्ट करते हैं। एक मंच पर लगाया गया आरोप दूसरे मंच पर संदर्भ बनता है, दूसरा मंच उसे वैधता देता है और अंततः वही आरोप सार्वजनिक विमर्श में स्थापित तथ्य की तरह प्रस्तुत होने लगता है। इन समस्त विरोधों के बीच सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि स्वयं डॉ. मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में क्या कहा? उन्होंने 'अस्तित्व की एकता' को अपनी विश्व-दृष्टि का आधार बताया और स्पष्ट किया कि एकता के लिए एकरूपता आवश्यक नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य की श्रेष्ठता दूसरों पर प्रभुत्व में नहीं, बल्कि सम्पूर्ण विश्व के प्रति अपने दायित्व को समझने में है। न्यूयॉर्क से उनका यह संदेश भारत की उस दीर्घ सभ्यतागत दृष्टि का वैश्विक प्रतिपादन था, जिसमें 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना निहित है।

विडंबना यह है कि जिस मंच से एकता, संवाद, सह-अस्तित्व और मानवता का संदेश दिया जाना था, उसी मंच के वक्ता के विचार सुने बिना उसके विरोध में अभियान चलाया गया। किसी व्यक्ति के विचारों से असहमति लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उसे सुने बिना ही अस्वीकार्य घोषित कर देना बहुलतावाद की मूल भावना पर प्रश्नचिह्न लगाता है। लोकतंत्र की वास्तविक परीक्षा सहमति में नहीं, असहमति को सहने की क्षमता में होती है। पश्चिमी लोकतंत्रों की परिपक्वता की एक कसौटी यह भी होनी चाहिए कि वे अपने समाजों में उभरते वामी-जिहादी गठजोड़ को पहचानें और उसकी विभाजनकारी एवं कट्टरपंथी प्रवृत्तियों पर प्रभावी अंकुश लगाएं, ताकि कलह, वैमनस्य और संघर्ष से पीड़ित विश्व को वास्तविक शांति और सह-अस्तित्व की दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग मिल सके।

(लेखक शिक्षाविद एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

मेजबानी
डॉ. मोनिका शर्मा

भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बढ़ता महत्व

भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आज दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में गिना जाता है। महिलाओं के पेशेवर क्रिकेट खेलने को पुरुषों के समान ही महत्व मिलने लगा है। अब न केवल मैदान में बल्ला घुमाती बेटियों के प्रति लोगों की सोच बदली है, बल्कि महिलाओं का खेल देखने में भी रुचि बढ़ी है। ऐसे में भारत को पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना क्रिकेट के खेल में महिलाओं के बढ़ते दखल और महिला क्रिकेट के बढ़ते महत्व से जुड़ा सुखद समाचार है। पहली बार होने जा रहे महिला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन 14 से 28 फरवरी तक होगा। गौरतलब है कि आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी-2027 से पहले महिला आईसीसी के महिला क्रिकेट से जुड़े दो ही आयोजन होते रहे हैं। ऐसे में वनडे विश्व कप और टी20 विश्व कप के साथ अब महिला चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना, महिला क्रिकेट से ही नहीं खेल-जगत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम भी है। दरअसल, कुछ साल पहले बीसीसीआई से अनुबंधित महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को पुरुषों के बराबर मैच फीस मिलने के निर्णय के बाद से इस मोर्चे पर बड़ा बदलाव देखा गया। साथ ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) द्वारा वर्ल्ड कप में पुरुषों और महिलाओं को समान पुरस्कार राशि दिए जाने का निर्णय भी अहम भी रहा। असल में पुरुष क्रिकेट भारत सहित दुनिया के बहुत से देशों में दशकों से एक लोकप्रिय खेल बना हुआ है। पुरुषों के मुकाबले इस खेल में महिलाओं की भागीदारी की ओर ध्यान जरा कम रहा है। गौरतलब है कि दुनिया का पहला महिला क्रिकेट विश्व कप 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। वहीं पुरुषों के पहले क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 में हुआ। महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन दो वर्ष पहले होने एक बावजूद इस खेल में पुरुषों के मुक़ाबले कम ही चर्चा मिली। लोगों का रुझान भी बहुत धीमी गति से बढ़ा। आगे चलकर इंटरनेशनल महिला क्रिकेट परिषद का विलय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में हुआ। इससे महिला क्रिकेट को पुरुषों के समान संसाधन, मीडिया कवरेज और वैश्विक मंच मिलना शुरू हुआ। भारत में 2006 में भारतीय महिला क्रिकेट संघ का विलय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में होने के बाद से महिला क्रिकेटरों को बेहतर सुविधाएं और अच्छे अनुबंध मिलने शुरू हुए। उस समय यह अनुमान लगाना भी मुश्किल था कि बीसीसीआई के भावी निर्णय और महिला खिलाड़ियों की लगन इस खेल को इतनी ऊंचाई पर ले जाएंगे। हालिया वर्षों में शुरू हुए टी20 और आईपीएल आयोजनों के बाद से महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की बहुत प्रभावी पहचान बन गई है। कुछ समय पहले आई आईसीसी की महिला वनडे रैंकिंग के अनुसार स्मृति मंधाना दुनिया की नंबर-1 बल्लेबाज हैं। इन दिनों दुबई में चल रहे महिला एशिया कप-2026 में भी हमारी टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है। ध्यातव्य है कि भारत में 2017 में आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम के पहुंचने के बाद से ही महिला क्रिकेट को गंभीरता से लिया जाने लगा। अपने बेहतरीन प्रदर्शन को कायम रखते हुए हमारी महिला टीम 2020 में टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी पहुंची थी। साथ ही 2022 में बर्मिंघम में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में भी टीम ने रजत पदक हासिल किया था। आईसीसी महिला एक दिवसीय विश्व कप-2025 का खिताब भी हमारी महिला क्रिकेट टीम ने जीता था। इतना ही नहीं, अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप में भी भारतीय टीम ने भी वैश्विक स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। आईपीएल के साथ ही महिला क्रिकेटर अपने खेल का दमखम घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मैदानों पर जमकर दिखा रही हैं। ऐसी उपलब्धियों के चलते ही कभी पुरुषों का खेल माने जाने वाले क्रिकेट में अब महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन की खूब चर्चा होने लगी है। देखने में भी आ रहा है कि अब भारत में अधिक संख्या में महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं। घर-परिवार में भी बेटियों के इस खेल से जुड़ने के मोर्चे पर सहजता आई है। हर पहलू पर हो रहे सकारात्मक बदलाव का ही परिणाम है कि दर्शक भी बड़े पैमाने पर महिला मुकाबलों में रुचि लेने लगे हैं। 2025 में घरेलू मैदान पर अपना पहला महिला विश्व कप जीतकर इतिहास रचने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम हर आयोजन में अपनी बेहतरीन क्षमता का परिचय दे रही है। स्पष्ट है कि महिला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की मेजबानी से महिला क्रिकेट को लेकर आमजन का रुझान और रोमांच और बढ़ेगा। भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका की टीमों की हिस्सेदारी वाले इस आयोजन से देश ही नहीं, दुनियाभर में महिला खिलाड़ियों के मान-मनोबल की चर्चा होगी। बेटियों को क्रिकेट के खेल से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी।

(लेखिका स्वतंत्र स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हृदय का करें अनुसरण

संकलित
दर्शन

कोई भी धर्मग्रंथ हमें धार्मिक नहीं बना सकता। चाहे हम दुनिया के सारे धर्मग्रंथ पढ़ डालें, परंतु फिर भी ईश्वर या धर्म का हमें तनिक भी ज्ञान नहीं होता। हम सारी उम्र धर्म या ईश्वर संबंधी बातें करते रहें, पर हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती। दुनिया के विद्वानों ने भले ही हमारी बुद्धि प्रखर कर दी हो, पर हम ईश्वर तक नहीं पहुंच सके। पाश्चात्य संस्कृति का दोष यह है कि हम बुद्धि का संस्कार करते समय हृदय के संस्कार की ओर ध्यान ही नहीं देते। इसका परिणाम यह होता है कि मनुष्य दस गुना स्वार्थी हो जाता है। यदि हृदय और बुद्धि में विरोध उत्पन्न हो, तो तुम हृदय का अनुसरण करो, क्योंकि बुद्धि केवल एक तर्क के क्षेत्र में ही काम कर सकती है, वह उसके परे जा ही नहीं सकती, पर वह केवल हृदय ही है, जो हमें उच्चतम भूमिका पर आरूढ़ करता है। वहां तक बुद्धि कभी नहीं पहुंच सकती। हृदय, बुद्धि का अतिक्रमण कर अंतःस्फूर्ति को पा लेती है। बुद्धि से कभी अंतःस्फूर्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अंतःस्फूर्ति का कारण केवल ज्ञानोदय बासित हृदय ही है। बुद्धिप्रधान, किंतु हृदय शून्य मनुष्य कभी स्फूर्तिमान नहीं बन सकता। प्रेममय पुरुष की समस्त क्रियाएं उसके हृदय से अनुप्राणित होती हैं। एक ऐसा उच्चतर साधन, जिसे बुद्धि कभी नहीं दे सकती, अगर किसी ने पाया है तो हृदय ने ही, और वह साधन है अंतःस्फूर्ति। जिस तरह बुद्धि ज्ञान का साधन है, उसी तरह हृदय अंतःस्फूर्ति का। शुरुआत में हृदय इतना शक्तिशाली नहीं होता, जितनी कि बुद्धि। एक अनपढ़ मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं होता, पर वह थोड़ा बहुत भावना प्रधान होता है।

अपनी गठरी टटोलें

संकलित
प्रेरणा

दो आदमी यात्रा पर निकले! दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का गंतव्य एक था तो दोनों यात्रा में साथ हो चले। सात दिन बाद दोनों के अलग होने का समय आया तो एक ने कहा- भाई साहब! एक सप्ताह तक हम दोनों साथ रहे क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरे ने कहा- नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। पहला यात्री बोला- महोदय मैं एक नामी ठग हूँ परन्तु आप तो महाठग हैं। आप मेरे भी गुरू निकले। दूसरा यात्री बोला- कैसे? पहला यात्री- कुछ पाने की आशा में मैंने निरंतर सात दिन तक आपकी तलाशी ली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। इतने दिन साथ रहने के बाद मुझे यह पता है आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी यात्रा पर निकले हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है? बिल्कुल खाली हाथ हैं! दूसरा यात्री- मेरे पास एक बहुमूल्य हीरा है और थोड़ी-सी रजत मुद्राएं भी है। पहला यात्री बोला- तो फिर इतने प्रयत्न के बावजूद वह मुझे मिले क्यों नहीं? दूसरा यात्री- मैं जब भी बाहर जाता, वह हीरा और मुद्राएं तुम्हारी पोटली में रख देता था और तुम सात दिन तक मेरी झोली टटोलते रहे। अपनी पोटली संभालने की जरूरत ही नहीं समझी। तो फिर तुम्हें कुछ मिलता कहां से! ईश्वर नित नई खुशियां हमारी झोली में डालते हैं परन्तु हमें अपनी गठरी पर निगाह डालने की फुर्सत ही नहीं है, यही सबकी मूलभूत समस्या है। जिस दिन से इंसान दूसरे की ताकझाख बंद कर देगा उस क्षण सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अपनी गठरी टटोलें! जीवन में सबसे बड़ा गूढ मंत्र है स्वयं को टटोले और जीवन-पथ पर आगे बढ़े सफलताएं आप की प्रतीक्षा में है।

अंतर्मन

आज की पाती

जहरीली शराब से मौतें, जिम्मेदार कौन?

बहुत ही निंदनीय है कि मध्य प्रदेश में लापरवाही कुछ लोगों की जान पर भारी पड़ गई। यह लापरवाही सरकार, प्रशासन और खुद नशा करने वाले लोगों की मानी जा सकती है। यहां जहरीली शराब बहुत से लोगों की जान की दुश्मन बन गई। हमारे देश में नशा बहुत से लोगों की जान पर भारी पड़ता आ रहा है, लेकिन सरकारें और प्रशासन इस पर कोई खास गंभीर नहीं दिखते, तभी तो देश में जहरीली शराब पीने से होने वाली मौतों का आंकड़ा भी चिंताजनक स्थिति में है। एक तरफ सरकारें नशे पर नकेल कसने के दावे करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जहरीली शराब का दानव समय-समय पर सिर उठाकर सैकड़ों लोगों को मौत की नींद जब सुलाता है तो इन सभी खोखले दावों की हकीकत को बयां कर देता है। - *राजेश वर्मा, कांकेर*

करंट अफेयर

ब्रिटेन ने साइबर हमले की आशंका से किया इनकार

ब्रिटेन की राष्ट्रीय हवाई यातायात सेवा (एनएटीएस) ने बुधवार को इस बात से इनकार किया कि देश के हवाईअड्डों पर बड़े पैमाने पर हुए व्यवधान का कारण साइबर हमला था। इस व्यवधान से भारत आने-जाने वाली कई उड़ानें भी प्रभावित हुईं। मंगलवार को हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली में आई तकनीकी समस्या के कारण हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और करीब 2,000 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं। इसके दुष्प्रभाव दूसरे दिन भी जारी रहे। इस व्यवधान के कारण हजारों यात्रियों को दिक्कत हुई। ब्रिटेन के सबसे व्यस्त हीथ्रो हवाई अड्डे के अलावा गैटविक, स्टैनस्टेड, ल्यूटन और मैनचेस्टर हवाई अड्डों पर भी बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द हुईं और देरी हुई।

एनएटीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मार्टिन रॉल्फ ने बीबीसी से कहा, 'हम बहुत गहन जांच करेंगे। फिलहाल, हमने साइबर हमले की आशंका को खारिज किया है।' उन्होंने कहा, ''मुझे नहीं लगता कि हमने इससे पहले कभी ऐसी घटना देखी है जो एक से अधिक बार हुई हो। यह ऐसी घटना होगी, जिसे हमने 50 से अधिक वर्षों के संचालन में नहीं देखा है। मैं कहूंगा कि सुरक्षा और आपदा से निपटने की क्षमता, दोनों के लिहाज से ब्रिटेन की दुनिया में सबसे अच्छी साख है।'

ऑफ बीट

स्वीडन में पूंजीपतियों को लेकर नजरिया बदल रहा

फर्नीचर कंपनी आईकिया के संस्थापक इंग्वार कम्पराड के मामले में स्वीडन के लोगों को यह बात खास तौर पर पसंद थी कि वह पुरानी कार चलाते थे (स्वाभाविक रूप से वोल्वो)। वह अपने स्टोर में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच जाकर उनसे बातचीत करते थे और हर साल खुद उन्हें क्रिसमस के तोहफे देते थे। उनका यह साधारण दिखने का अंदाज (जिसे कुछ लोग सोची-समझी रणनीति भी कह सकते हैं) लोगों का ध्यान इस बात से हटा देता था कि कम्पराड दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और स्वीडन के ऊंचे करों से बचने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। 'वॉल स्ट्रीट जर्नल' ने स्वीडन में आए हैरान करने वाले पूंजीवादी कायापलट पर लिखा है और 'फाइनेंशियल टाइम्स' ने इस धारणा पर खबर की है कि यह देश अब अरबपतियों से भरा गया है। बीबीसी ने 2024 में 'सुपर-रिच स्वेड्स' नाम से एक वृत्तचित्र पॉडकास्ट भी प्रसारित किया। और इस दिलचस्पी के पीछे ठोस वजहें हैं। लंबे समय तक स्वीडन दुनिया में सबसे अधिक कर लगाने वाले देशों में शामिल रहा, लेकिन पूंजी और संपत्ति पर कर लगाने के मामले में अब स्थिति अलग है। मसलन, देश में अब संपत्ति कर, विरासत कर या अचल संपत्ति कर नहीं है।

ट्रेंड

मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 3 मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स से भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इनकी अनुमानित लागत 10,783 करोड़ है।
- **नितिन गडकरी**, केंद्रीय राजमार्ग मंत्री

समान भागीदार

महिलाएं अब केवल शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अपनी आबादी के अनुपात में हर क्षेत्र में समान भागीदार बनेंगी। इसके लिए डबल-इंजन सरकार अपने सभी कार्यक्रमों को लगातार आगे बढ़ा रही है।
- **योगी आदित्यनाथ**, सीएम, यूपी

कानून-व्यवस्था नहीं

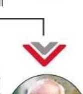

मणिपुर के जाने-माने संगीतकार चोंगथम विक्रम सिंह जी की भीड़ द्वारा बेरहमी से की गई हत्या, बीजेपी के शासन में पूरी तरह से कानून-व्यवस्था के न होने की एक और डरावनी याद दिलाती है। छात्र सुरक्षित नहीं है। महिलाओं को हर दिन अत्याचार का सामना करना पड़ता है।
- **मल्लिकार्जुन खरगे**, अध्यक्ष, कांग्रेस

बाहर जाने की मनाही

जो लोग कहते है कि मैं भारत आने से इनकार करने वाला भगोड़ा हूँ, उन्हें बता दूँ कि मैं 1992 से यूनाइटेड किंगडम का स्थायी निवासी हूँ और अभी कानूनी तौर पर मुझे इस देश से बाहर जाने की मनाही है।
- **विजय माल्या**, पूर्व राज्यसभा सदस्य

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

प्रेरणा

हमेशा जो हो, वो बने रहो। खुद को व्यक्त करो, खुद पर विश्वास रखो। - ब्रूस ली

संपादकीय

ब्रिक्स समिट में हमारा फोकस अपने हितों पर हो

ट्रम्प टैरिफ का डर, पारस्परिक भू-रणनीतिक समस्याएं, युद्धों में प्रमुख शक्तियों का सीधा जुड़ाव, बहुपक्षीय ट्रेड संभावनाओं को कमजोर करने वाली सदस्य देशों की भौगोलिक दूरियां- ये तमाम फैक्टर्स भारत की अध्यक्षता में आगामी 12-13 सितम्बर को आयोजित 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के परिणामों के प्रति विश्लेषकों को भले ही आशान्वित न करें, लेकिन कई बार 'ऑप्टिक्स' वास्तविक निष्कर्षों से ज्यादा अहम होता है और मोदी, शी और पुतिन का साथ होना वैसा ही दृश्य होगा। 11 पूर्णकालिक सदस्यों और 10 पार्टनर सदस्यों वाला ब्रिक्स दुनिया की 28% जीडीपी (नॉमिनल) और आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। चीन, भारत, ब्राजील, रूस इसके मुख्य किरदार हैं। जिस सम्मलेन में शी और पुतिन के आने की खबर हो, उसमें जो दिखाई देता है, वह भी कूटनीति की दुनिया के लिए अहम संदेश होता है। शी 400 उद्योग और अन्य आर्थिक-वाणिज्यिक गतिविधियों से जुड़े प्रमुखों के साथ आ रहे हैं। यह उनकी 2014 की गांधीनगर में झूला-वार्ता, 2019 की चेन्नई-मल्लापुरम लॉन में चर्चा के बाद नई दिल्ली की पहली यात्रा होगी। ऐसे में कूटनीति को फिर से एक मौका देना दोनों देशों के लिए जरूरी होगा। भारत को रूस से बेहतर हथियार और चीन से अन्य सामानों के अलावा रेयर-अर्थ सप्लाई का कोई पुख्ता आश्वासन चाहिए। ऐसे माहौल में ब्राजील और रूस की चाहत कि डॉलर के समानांतर कोई वैकल्पिक करेंसी विकसित की जाए, शायद ही इस बार भी परवान चढ़े।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता

humarehanuman@gmail.com

योग करेंगे तो सौंदर्य हो या नहीं, पर तेज अवश्य होगा

सुंदरता और कुरूपता के मामले में हम केवल देह पर टिकते हैं। कौन सुंदर है, कौन कुरूप है- मनुष्य के शरीर के मामले में यह हमारा दिया हुआ ही प्रमाण-पत्र है। और चूंकि हम देह पर टिकते हैं, इसीलिए एक जगह की सुंदरता दूसरे स्थान में कुरूपता बन जाती है। गोरी चमड़ी, काली चमड़ी तो सबसे बड़ा मापदंड हो गया सुंदरता का। और पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। कम ही लोग जान पाते हैं कि एक जन्मजात सौंदर्य भी होता है, और वह होता है आत्मा का। आज सभी लोग ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सबका झुकाव बाहरी जीवन पर है। मशीन इंसान को सुंदर भी बना रही है और कुरूप भी। लेकिन जिन्होंने आत्मा के सौंदर्य को जाना, उनके शरीर से एक अतिरिक्त बात प्रकट हुई और उसको तेज कहते हैं। जो सौंदर्य और कुरूपता दोनों से अलग है, बल्कि कहें कि ऊपर है। आत्मा पर जाने के लिए योग एक साधन है। और जो भी योग करेंगे, उनके पास सौंदर्य हो या कुरूपता, लेकिन तेज बरकरार रहेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अष्टावक्र हैं, जिन्हें कुरूपता का प्रतीक माना गया पर उनके तेज के आगे सब फीके थे। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

शब्दों का जादू

स्मृतियां

स्मृतियां जनमेजय थीं।
श्रृंगी ऋषि का शाप।
आड़ी-टेढ़ी काली रेखाएं
त्वचा के भीतर कहीं
मेरी सांसों से संचरित।

मुझे नाग-यज्ञ करना था,
वे कंकाल थीं-
न मरतीं, बच निकलतीं।
स्मृतियां जनमेजय थीं।

मैं सोचती- वे मर गईं।
समय बह गया,
दर्द सो गया।
छंट गई धुंध,
कट गई बरसों की पीली घास
जो सूख चुकी थी मन में।

पहली रात जोरों की बारिश गिरी,
उग आई पुनः स्मृतियां हरी-हरी
सच, स्मृतियां जनमेजय थीं।
-आंचल बावा, दिल्ली
(मूल कविता के सम्पादित अंश)

पूरी कविता को पढ़ने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

भास्कर कविता उत्सव की शीर्ष 100 कविताओं में चयनित

पाठकों के पत्र

एआई के इस्तेमाल में सुरक्षा भी जरूरी

एआई के अधिक उपयोग से साइबर अपराधियों के लिए नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। संदिग्ध एआई टूल्स और चैटबॉट्स के नाम पर लोगों को साइबर हमलों का शिकार बनाया जा रहा है। ऐसे में एआई का उपयोग करते समय सुरक्षा को भी प्राथमिकता देना जरूरी है। -हेमंत कुमार, रांची, झारखंड

बुजुर्गों संबंधी मामलों पर ध्यान दें

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठ नागरिकों संबंधी सैकड़ों केस 3 से 6 वर्ष से सुनवाई के लिए लम्बित हैं। हर बार तारीख पर तारीख दी जाती है, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती। लोगों के करोड़ों रुपए वकीलों के पास जमा हैं। क्या मुख्य न्यायाधीश इस मामले में ध्यान देंगे? -डीपी कपूर, चंडीगढ़

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

मन की प्रयोगशाला

दोस्तियां सेहत के लिए भी अच्छी हैं...

अमेरिकी जर्नल 'प्लॉस मेडिसिन' की एक ताजा रिसर्च हममें से कइयों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। रिसर्च के अनुसार अकेलापन केवल सामाजिक ही नहीं, जैविक समस्या भी है। यानी लंबे समय तक अकेलापन हम में तनाव हार्मोन बढ़ा सकता है और इम्युन सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। निष्कर्ष यह है कि दोस्तियां केवल खुशी ही नहीं देतीं, वे हमारा स्वास्थ्य भी सुधारती हैं।

सुर्खियों से आगे • कोई हमें अन्नदाता कहे या जनता जनार्दन, पर चुनावों के हम मालिक नहीं हैं

चुनावों की सरगर्मी और हम

देशकाल

नवनीत गुर्जर

navneet@dbcorp.in

उत्तर प्रदेश और पंजाब दो अहम राज्य हैं, जहां चुनाव होने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां इन चुनावों के लिए ही अपनी कमर कस रही हैं। नए-नए प्रभार गढ़े जा रहे हैं और नए-नए प्रभारी बनाए जा रहे हैं। हर तरह से, हर तरफ जोर-शोर से तैयारी की जा रही है।

अगर कोई बेफिक्र बैठा है, अगर कोई किसी तरह की तैयारी नहीं कर रहा है तो वो हैं हम।

आम लोग! आम वोटर्स!

क्योंकि हमें कोई कुछ भी कहे- अन्नदाता, जनता जनार्दन और भी बहुत कुछ- पर हकीकत यह है कि हर दो, ढाई या पांच साल में होने वाले चुनावों के हम मालिक नहीं हैं। हमने अपने मन को आजादी दी है तो सिर्फ इतनी, कि अपनी मर्जी से चुनाव कर लें अपने पिंजरे का। रहना हमें कैद में ही है।

हर तरह के कैदखाने हैं देश में...

और हर तरह की कैदें।

बच्चे अपनी वजन बढ़ाऊ किताबों की बस्ताई शिक्षा में कैद हैं। बेटियां अपनी सुरक्षा के खतरे के कारण खुद में ही कैद रहने को मजबूर हैं। और महिलाओं, बुजुर्गों की कैदों का तो पारावार नहीं है। तथाकथित सभ्य समाज इन कैदों को घर, ऑफिस, मुहल्ला, खेत, खलिहान, सड़क, बाजार और जाने क्या-क्या कहता है।

जब हर कोई कैद है, अलग-अलग कैदखानों में, फिर कैसी आजादी, कैसा लोकतंत्र, कैसा चुनाव?

अगर ये पार्टियां, ये नेता, सच में चुनाव जीतना चाहते हैं तो हमें इन कैदखानों से मुक्ति दिला दें। फिर करें राज। चतुर्दिक। एकतरफा।

फिर किसी भी नेता को वोट के लिए गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा। लोग खुद ही चुन लेंगे अपने मुक्तिदाता को।

लेकिन सच ये है कि अंग्रेजों के जाने के बाद ये जो मौजूदा कैदखाने हैं, इनमें से ज्यादातर का निर्माण राजनीति ने ही किया है। और चौंकने की कोई वजह हमारे पास नहीं है, क्योंकि हर कैदखाने के उद्घाटन के वक्त बड़े मजे से तालियां भी हमने ही बजाई हैं।

सभ्य समाज कहा जाने वाला बड़ा कैदखाना जरूर हमने खुद बनाया है। दकियानूसी सोच की गलत परंपराओं की कई शाखाएं भी खोली हैं, जिनमें हमारा बचपन, जवानी और वृद्धावस्था कैद है।

चुनाव के वक्त भी ये कैदें काम करती हैं। जातिवाद की कैद सबसे बड़ी और लंबी है। फिर गांव, शहर, पंचायत, सरपंच, पटेल, रिश्तेदारों का क्षेत्रवाद अलग कैदखाने गढ़ता है।

चुनाव के वक्त ये कैदें कानों में गूंजती हैं या कहिए कान फोड़ती हैं। जैसे ठण्ड के मौसम में हवा आवाज करती है- दांतों में कंघी रखकर। कुछ फटी-फटी... झीनी-झीनी... बालिग होते लड़कों की तरह।

वोट देते वक्त तो ये आवाजें और भी ऊंची होती हैं, जैसे दरिया के दो किनारों पर खड़े होकर देहात के दो दोस्त गांवभर के हाल पूछ रहे हों।

जब तक हम इन कैदों, इन बेड़ियों को तोड़कर वोट नहीं देंगे, सरकारें ऐसी ही आती रहेंगी। बेमुरौव्वत और आलसी। जनप्रतिनिधि ऐसे ही रहेंगे। लालची और गिरोहबाज।

हम ही इन बेड़ियों, इन कैदों के अब आदी हो चुके हैं...

दरअसल, हम इन बेड़ियों, इन कैदों के आदी हो चुके हैं। सरकार भ्रष्ट नहीं हो, तो हमें लगता है काम जल्दी नहीं होंगे। व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो हमें लगता है काम पक्का नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि लालची या गिरोहबाज नहीं हो, तो लगता है सीधा यानी कमजोर होगा।

दरअसल, हम इन बेड़ियों, इन कैदों के आदी हो चुके हैं। सरकार भ्रष्ट नहीं हो, तो हमें लगता है काम जल्दी नहीं होंगे। व्यवस्था दुरुस्त हो जाए तो हमें लगता है काम पक्का नहीं होगा। और जनप्रतिनिधि लालची या गिरोहबाज नहीं हो, तो लगता है सीधा यानी कमजोर होगा।

वोट बेचकर अच्छी सरकार का सपना देखने वाली मानसिकता से बाहर आना होगा, वरना हम ऐसे ही पिसते रहेंगे। व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी और सरकारें यूं ही आती-जाती रहेंगी- घपले-घोटाले करते हुए। सच को दबाते हुए। ईमानदारी को धकियाते हुए और जनता को किनारे करते हुए।

हमारी हालत ऐसी ही रहेगी, जैसी अभी है। बिजली के पुराने, जंग-आलूदा, पान खाए दांतों की तरह, जैसे फ्यूज प्लेटें लगी रहती हैं।

वो जो एक मियाद होती है, दवाओं की शीशियों पर लिखी हुई। दवा लेते वक्त ज्यादातर लोग उसे ही देखते हैं। मियाद बीत जाए तो बेअसर हो जाती है दवा। कभी-कभी जहरीली भी।

आप पार्टी जब नई-नई आई थी तो उसे देखकर कुछ हद तक लगा था कि पुरानी ज्यादातर पार्टियों की मियाद बीत चुकी है। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पुरानी पार्टियां जमती, बढ़ती गईं और उनकी तगड़ी जमावट ने आप पार्टी की बरात निकाल दी।

दरअसल, राजनीति एक ऐसी संस्कृति है, जिसमें रिश्तों का, भावनाओं का, काया का अपमान इन तमाम शब्दों से अनजान रहते हुए किया जाता है।

कुल-मिलाकर यह संस्कृति भावनाओं के शून्य की प्रतीक है।

...और जहां भावनाएं नहीं होतीं, वहां अपमान के सिवाय कुछ नहीं होता।

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए QR कोड को स्कैन करें।

नजरिया • छात्रों की समस्याएं समाधान चाहती हैं

'सत्य निकेतन' ने हमारे समाज का कौन-सा सच दिखाया है?

युवा मन

चेतन भगत

अंग्रेजी के उपन्यासकार

chetan.bhagat@gmail.com

पहले यह माना जाता था कि एजुकेशन की मदद से ही छात्र अपनी बदहाली से छलांग लगाकर बाहर आ सकते हैं। आज भी ऐसा ही है, लेकिन फर्क इतना है कि यह छलांग अब लगातार कठिन होती जा रही है। सत्य निकेतन हादसे ने हमें यही बताया है। यह दक्षिण दिल्ली की एक छोटी-सी बस्ती है, जो आलीशान कॉलोनियों से घिरी हुई है। यहां छोटे-छोटे भूखंडों पर बने तंग, एक-दूसरे में सिमटे मकान खरपतवार की तरह बढ़ते चले गए हैं। इनमें से कई इमारतों में छात्र छोटे-छोटे कमरे किराये पर लेकर रहते हैं। वे वहां कॉलेज की पढ़ाई या प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हुए रहते हैं। कॉलोनी में छात्र-अर्थव्यवस्था को सहारा देने वाले तरह-तरह के कारोबार भी हैं- खाना पहुंचाने वाली सेवाएं, जेरॉक्स की दुकानें, चाय की थड़ियां, पेइंग गेस्ट (पीजी) और कोचिंग सेंटर संचालक। इन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता ही सत्य निकेतन जैसी बस्तियों को फलने-फूलने का अवसर देती है। यह किसी झुग्गी-बस्ती जैसी दिख सकता है, फर्क यह है कि यह शिक्षा-केंद्रित स्लम होती है।

छात्र आते-जाते रहते हैं; कुछ प्रवेश परीक्षाओं में सफल होते हैं, ज्यादातर नाकाम रहते हैं। लेकिन इन छात्रों को सामान और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले कारोबारी लगातार बने रहते हैं। परीक्षाओं के नतीजे चाहे जो हों, वे हमेशा कमाई करते हैं। मुनाफे की तलाश में गुणवत्ता की अनदेखी की जाती है और नियमों को तोड़ा-मरोड़ा जाता है। बिना फायर-सेफ्टी वाला अवैध रूप से बना गेस्टहाउस भी किराये पर उठ जाता है, क्योंकि छात्रों के पास विकल्प ही क्या हैं? 80 गज के प्लॉट पर अनुमति से ज्यादा मंजिलें तान दी जाती हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं। अगर कमरा खाली है, तो कोई ना कोई छात्र उसे ले ही लेगा। इमारत के चारों ओर बिजली के खुले तार लटक रहे हैं? क्या फर्क पड़ता है, जब तक सोने के लिए एक बेड मिल रहा हो?

बस इतना समझ लीजिए कि सत्य निकेतन की जिंदगी वैसी नहीं है, जैसी बॉलीवुड की कॉलेज कैंपस वाली फिल्मों में दिखाई जाती है। देशभर से जाने कितने युवा छात्र ऐसी जगहों पर आते हैं और खस्ताहाल, अवैध ठिकानों पर डेरा जमाते हैं। फिर शुरू होती है दो से पांच साल तक चलने वाली लंबी और कठिन यात्रा। यह कोई कॉलेज होस्टल नहीं है। यहां न कोई ओरिएंटेशन होता है, न बैच के साथियों से मुलाकात। यहां छात्रों के लिए न कोई कॉमन रूम है, न खेल की सुविधाएं। न सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, न पाठ्येतर गतिविधियां। यहां केवल एक ही उद्देश्य है और एक ही गतिविधि- जीवन की चक्की में पिसते रहना।

और वे पिसते रहते हैं- दिन-रात, इस उम्मीद में कि परीक्षा निकाल लेंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए, या मेडिकल कॉलेज में। या सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए- शीर्ष स्तर की सिविल सेवाओं से लेकर निचले स्तर की किसी सरकारी भर्ती तक। कुछ भी आसान नहीं है। संभावनाएं बहुत कम हैं- पेपर-लीक हो या न हो। किसी को परवाह नहीं कि आपका दिन, महीना या साल खराब रहा। और जैसा कि हालिया हादसा दिखाता है, किसी को आपकी जिंदगी की भी परवाह नहीं है।

इससे हमें शर्म महसूस होनी चाहिए। हमें पूछना चाहिए कि एक देश और समाज के रूप में हम क्या कर रहे हैं? हम अगली पीढ़ी को कैसी संस्कृति सौंप रहे हैं? क्या संदेश दे रहे हैं? क्या यही कि भारत में जिंदगी ऐसी ही होती है? हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं से बहुत कम अवसरों के लिए बेहद तीखी प्रतिस्पर्धा करने को कहती है, जबकि हमारा समाज एक अच्छी जिंदगी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त वैकल्पिक रास्ते बनाने में विफल रहा है। और अवसरों की इस कमी के इर्द-गिर्द एक पूरा संदिग्ध बिजनेस-इकोसिस्टम खड़ा हो गया है। जब खुद हताशा एक उद्योग बन जाए, तो इसे क्या कहा जाना चाहिए?

हमारी शिक्षा व्यवस्था युवाओं से बहुत कम अवसरों के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा करने को कहती है। हमारा समाज अच्छी जिंदगी तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रास्ते बनाने में विफल रहा है। और अवसरों की इस कमी के इर्द-गिर्द एक पूरा संदिग्ध बिजनेस-इकोसिस्टम खड़ा हो गया है।

सत्य निकेतन का अर्थ होता है- 'सच्चाई का घर'। लेकिन इस हादसे ने छात्रों के जीवन की दुःखद सच्चाई को उजागर कर दिया है। हम चाहें तो इसे एक अलग-थलग घटना मानकर छोड़ सकते हैं, या इसका इस्तेमाल एक बड़ी सच्चाई का सामना करने के लिए कर सकते हैं- यह कि हमें इन हालात में आमूलचूल बदलाव करने होंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विश्लेषण • मजाक बनकर रह गया है पड़ोसी मुल्क

क्रिकेट में अपनी बदहाली के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार

स्पोर्ट्स

बोरिया मजुमदार

सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा के सहलेखक और खेल पत्रकार

इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के अधबीच में पाकिस्तान ने घबराकर ऐसा कदम उठा लिया कि पूछिए मत। उसने सात खिलाड़ियों को वापस भेज दिया और कोचों को हटा दिया और मानो उन्हें सबक सिखाने की नजीर पेश करना चाहता हो। अब बाबर आजम ऑन-रिकॉर्ड कह रहे हैं कि उन्हें इन फैसलों की कोई जानकारी ही नहीं थी। तो आखिर पीसीबी इन खिलाड़ियों को घर भेजकर किस बात का उदाहरण सामने रखना चाहता था? बेइज्जती और दुर्व्यवहार का? और जो कुछ उन्होंने किया, उससे पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ियों को क्या संदेश जा रहा है?

खिलाड़ियों और कोचों पर तो गाज गिर रही है, लेकिन अधिकारियों का क्या? उनके बारे में एक शब्द तक क्यों नहीं? वे जवाबदेह क्यों नहीं हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई उनसे एक सवाल तक न करे और वे ऐसे काम करते रहें, जैसे कुछ हुआ ही नहीं?

सच्चाई यह है कि खिलाड़ी आसान निशाना और मोहरे हैं। पीसीबी उनके साथ तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करके बच निकल सकता है। और चूंकि वह सत्ता की स्थिति में है, इसलिए कोई उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। पाकिस्तानी क्रिकेट और उसका खेल जगत वहां पर खेल प्रशासन की कमान संभाल रहे राजनीतिक वर्ग के अहंकार का शिकार हो गया है।

ये सच है कि खिलाड़ियों ने भी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अगर आप ड्रेसिंग रूम में यह सुन रहे हों कि आपका बोर्ड मैच और सीरीज का बहिष्कार करने की धमकी दे रहा है, तो आप किस मानसिक स्थिति में खेल जारी रखेंगे? आप अपने काम पर कैसे फोकस कर पाएंगे?

सलमान आगा का ही उदाहरण लीजिए। उन्हें पहले टेस्ट में आखिरी वक्त पर कप्तानी संभालने के लिए कहा गया और फिर दूसरे टेस्ट के लिए टीम से बाहर कर दिया गया। अब तीसरे टेस्ट से पहले उन्हें घर भेज दिया गया है। यह हास्यास्पद है। आप इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच के आधार पर किसी खिलाड़ी का आकलन कैसे कर सकते हैं? वह भी तब, जब आखिरी क्षण में उसे कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई हो?

पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से चीजों को यूं ही चलते रहने दिया गया है। बहुत लंबे समय से खिलाड़ी और कमेंटेटर चुप रहे हैं। आखिरकार अब हम प्रभावशाली लोगों को आवाज उठाते देख रहे हैं। पूर्व खिलाड़ियों को बोलना ही होगा, क्योंकि अंत में नुकसान सिर्फ खेल का ही होता है।

जिन खिलाड़ियों को वापस भेज दिया गया है, वे अपमानित होकर घर लौट रहे हैं और उनका भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। और जो खिलाड़ी इंग्लैंड में खेल रहे हैं, उनके पास परिस्थितियों के अनुकूल ढलने का समय नहीं है। ऐसे में तो टीम को मानसिक रूप से पूरी तरह टूट ही जाना है।

और व्यापक तस्वीर यह है कि इन तमाम घटनाओं को पाकिस्तान के एक 'फेल्ड-स्टेट' होने से जोड़ा जा सकता है। खेल महज उसका एक और प्रतिबिम्ब है। हर जगह तस्वीर भयावह है। कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, जो उम्मीद की किरण बन सके। वहां हर चीज पर राजनीति हावी है। हर स्तर पर दखल और नियंत्रण ने पाकिस्तान के खेल का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्रिकेट टीम महज इस बात का उदाहरण हैं कि इस तरह का हस्तक्षेप क्या कर सकता है। दोष खिलाड़ियों पर मढ़ा जा रहा है।

पाकिस्तान में हर जगह तस्वीर भयावह है। तमाम चीजों पर सियासत हावी है। हर स्तर पर दखल और नियंत्रण ने पाकिस्तान के खेल का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्रिकेट टीम महज इस बात का उदाहरण है कि खेल में इस तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप क्या कर सकता है।

लेकिन क्या गलती उन्हीं की है? क्या पाकिस्तान के पतन की सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर डालकर बाकी चीजों पर परदा डाला जा सकता है?

बड़ा सवाल यह भी कि आज पाकिस्तान में कितने लोग उन राजनेताओं पर उंगली उठाएंगे, जो खेल में लगातार दखल देते रहे हैं और जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को इस हालत में पहुंचा दिया है? यह एक समूची व्यवस्था की विफलता है। ढांचे का पूरी तरह चरमरा जाना है। यह एक ऐसी निष्प्राण राज्य-व्यवस्था, जिसमें खेल का कोई महत्व ही नहीं रह गया है। लॉर्ड्स में पाकिस्तानी टीम के समर्पण और हॉकी में उसकी दुर्दशा का कारण भी यही है।

फिलहाल एक मुल्क के रूप में तो पाकिस्तान की यही कहानी है और ऐसा संकेत देने वाली बहुत कम चीजें हैं कि इसमें जल्द कोई बदलाव आने वाला है। तब तक प्रशंसक और खिलाड़ी बड़े राजनीतिक अहंकारों की बलिवेदी पर लगातार कुर्बान किए जाते रहेंगे। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा • हमें दिखावे से अधिक टिकाऊपन और जल्दबाजी से अधिक प्रभावशीलता को महत्व देना चाहिए...

जल्दी में बनाया गया वो इंफ्रास्ट्रक्चर किस काम का, जो टिका ही नहीं?

बुनियादी ढांचा

राघव चंद्रा

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पूर्व चेयरमैन

ये सच है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ है। लेकिन परियोजनाओं के पूरा होने के चंद दिनों में ही उनमें लगातार सामने आ रही खामियां चिंता का विषय हैं। भारी-भरकम बजट से तैयार और हाल ही में शुरू हुए लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे और गंगा एक्सप्रेस-वे में सर्फेस स्लिपेज, दरारें पड़ने, जमीन धंसने और गड्ढे होने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले दिल्ली-देहरादून और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे में भी ऐसा ही हुआ था। इन घटनाओं में हुआ आर्थिक नुकसान करोड़ों में है, लेकिन इससे जनता और सरकार के बीच आई भरोसे की कमी कहीं ज्यादा बड़ी क्षति है।

3 मई 2026 की रात भागलपुर के पास विक्रमशिला सेतु का 33 मीटर लंबा स्लैब टूटकर गिर गया। 4.7 किलोमीटर लंबे पुल के दो हिस्सों में बंटने से दक्षिण और उत्तर बिहार का सड़क-लिंक टूट गया। जब तक सेना और बीआरओ ने मिलकर बैली ब्रिज नहीं बनाया, यात्रियों को 161 किलोमीटर लंबे वैकल्पिक मार्ग से जाना पड़ा और फिर नावों का सहारा लेना पड़ा। 2022 से 2024 के बीच अगुवानी से सुल्तानगंज के बीच बन रहा पुल भी तीन बार ढहा। मई 2025 में केरल में एनएच-66 के रामानाट्टुकरा-वलंचेरी स्ट्रेच पर प्रोजेक्ट पूरा होने वाला ही था कि एक रीइन्फोर्स्ड अर्थ वॉल ढह गई। अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बीच चक्की ब्रिज कॉरिडोर पर कुछ महीने पहले ही बनी 100 मीटर लंबी प्रोटेक्शन वॉल टूट गई। हाल ही में मध्य रेलवे (सीआर) के भोरघाट सेक्शन में ठाकुरवाड़ी और मंकी हिल के बीच हुए भूस्खलन ने भारी क्षति पहुंचाई। 50-60 मीटर रेलवे लाइन बह गई। 30 ट्रेनें रद्द हुईं।

ये अलग-अलग जगहों पर दुर्भाग्यवश हुए मामले नहीं हैं। भू-तकनीकी जांच की कमी, ग्राउंड-इम्प्रूवमेंट उपायों की अनदेखी, ड्रेनेज के पर्याप्त इंतजाम नहीं करना, ऐसे इलाकों में रीइन्फोर्स्ड-सॉइल वॉल तकनीक का इस्तेमाल, जहां वह उपयुक्त ही नहीं थी- ये ऐसी खामियां हैं, जिन्हें इन घटनाओं का कारण माना जा सकता है। एक अन्य बड़ा कारण डिजाइनरों, कंपनियों, स्वतंत्र इंजीनियरों और एनएचएआई के फील्ड कर्मचारियों के बीच सुपरवाइजरी ढांचे का इतना बिखरा हुआ होना है कि कुछ गलत होता है तो किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती।

जिस दीवार, सड़क या पुल के हिस्से को ढहना ही नहीं चाहिए था, उसे दोबारा बनाने में खर्च हुआ हर रुपया वो है, जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने या मौजूदा ढांचों की मरम्मत में काम आ सकता था। इसमें बहुत-सी अप्रत्यक्ष लागत भी जुड़ जाती है। मसलन, डायवर्जन के फेर में माल ढुलाई में देरी होती है, घंटों के अतिरिक्त चक्कर में उत्पादकता घटती है और जिन कामों के लिए पुल बने थे, वे अब फिशिंग बोट से करने पड़ते हैं।

चूंकि सरकारी टेंडर सबसे कम बोली लगाने वाले ठेकेदार को दिए जाते हैं, इसलिए गुणवत्ता प्रभावित होती है। जो ठेकेदार बहुत कम बोली लगाकर प्रोजेक्ट हासिल करते हैं, उनके पास मुनाफा निकालने का एक ही रास्ता बचता है- मटैरियल, जमीन की जांच और निर्माण कार्य में कटौती। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और ग्राउंड असेसमेंट हर प्रोजेक्ट की रीढ़ होते हैं। लेकिन अकसर इन्हें पिछली परियोजनाओं की रिपोर्ट से ही बना लिया जाता है। बस नई जगह की भौगोलिक स्थिति, वाटर टेबल या बाढ़ की हिस्ट्री के हिसाब से छोटे-मोटे बदलाव किए जाते हैं। स्वतंत्र इंजीनियरों का काम कंक्रीट डालने से पहले इन कमियों को पकड़ने का होता है। लेकिन अकसर उनके पास ऐसे अनुभव या अधिकार का अभाव होता है, जिसमें वे परियोजना को रोक सकें। रीइन्फोर्स्ड वॉल और पुलों की डिजाइन की जांच होनी चाहिए। यह महज सामान्य डीपीआर के अनुमानों पर नहीं, बल्कि पुष्ट मृदा परीक्षण और कम से कम एक दशक के मानसून और बाढ़ के आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए। अन्य तकनीकी सुधारों के अलावा सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की गति पर गर्व करना और उसका महिमामंडन बंद करना चाहिए। हमें क्वांटिटी से अधिक क्वालिटी, दिखावे से अधिक टिकाऊपन और जल्दबाजी से अधिक प्रभावशीलता को महत्व देना चाहिए। (ये लेखक के अपने विचार हैं)

बड़ी चुनौती • मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की सालाना बिक्री में त्योहारी सीजन का 30% से ज्यादा योगदान

चिप संकट से गैजेट्स महंगे; त्योहारी बिक्री बचाने के लिए कैशबैक, लंबी ईएमआई, एक्सचेंज पर जोर

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

मेमोरी चिप की बढ़ती कीमतों ने त्योहारी सीजन से पहले स्मार्टफोन और लैपटॉप कंपनियों की लागत बढ़ा दी है। इसका असर उपकरणों की कीमत, उपलब्धता और ग्राहकों की खरीद क्षमता पर दिख रहा है। आईडीसी के मुताबिक, सितंबर तिमाही में भारत का कुल पर्सनल कंप्यूटर बाजार 5% घट सकता है, जबकि उपभोक्ता लैपटॉप बिक्री में दोहरे अंक की गिरावट की आशंका है। स्मार्टफोन शिपमेंट भी जुलाई-सितंबर तिमाही में 25-30% और अक्टूबर-दिसंबर में करीब 20% घटने का अनुमान है। इन अनुमानों के बीच कंपनियां त्योहारी मांग को सहारा देने के लिए बैंक छूट, एक्सचेंज बोनस और आसान मासिक किस्तों पर जोर देने की तैयारी कर रही हैं। सितंबर से दिसंबर का त्योहारी सीजन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों की सालाना बिक्री में एक-तिहाई से ज्यादा योगदान देता है। इसलिए बिक्री की वास्तविक तस्वीर दशहरा-दिवाली के दौरान ही स्पष्ट होगी।

फेस्टिव सीजनः कंपनियां इस साल प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस कर सकती हैं

कैटेगरी	बाजार के संकेत	कंपनियों की रणनीति
स्मार्टफोन	सितंबर तिमाही में शिपमेंट 30% तक घटने का अनुमान	बैंक छूट, एक्सचेंज बोनस, ईएमआई
उपभोक्ता लैपटॉप	बिक्री में दोहरे अंक की गिरावट संभव	पुरानी लागत वाले स्टॉक पर चुनिंदा ऑफर
प्रीमियम फोन	बजट श्रेणी के मुकाबले मांग मजबूत	अपग्रेड योजना और लंबी अवधि की फाइनेंसिंग

चिप 1 साल में 4 गुना तक महंगी, ये संकट कैसे भारी पड़ रहा है?

मेमोरी चिप की कीमतें एक साल में करीब 4-4.5 गुना बढ़ चुकी है। स्मार्टफोन और लैपटॉप में रैम मल्टीटास्किंग, जबकि स्टोरेज चिप डेटा सुरक्षित रखने का काम करती है। एआई डेटा सेंटरों और सर्वरों से उच्च क्षमता वाली मेमोरी की मांग बढ़ी है। निर्माता ज्यादा लाभ वाली एडवांस चिप को प्राथमिकता दे रहे हैं। इससे सामान्य इस्तेमाल होने वाली मेमोरी की उपलब्धता घटी और लागत बढ़ी।

एंट्री लेवल पर सुस्ती, लेकिन प्रीमियम की मांग मजबूत

आईडीसी के मार्च तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक, 9500 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन का शिपमेंट 59% घटा। इसके उलट 38 हजार से 57 हजार रुपए की श्रेणी 29% और 57 हजार से 76 हजार रुपए के मोबाइल की बिक्री 32% बढ़ी। काउंटरपॉइंट रिसर्च के मुताबिक, 20,000 से ज्यादा कीमत वाले फोन की मांग तुलनात्मक रूप से स्थिर रह सकती है।

सीधी छूट कम, बैंक-एक्सचेंज ऑफर से दाम घटाने की कोशिश

कंपनियां लागत का पूरा बोझ एक साथ ग्राहकों पर डालने के बजाय मूल्यवृद्धि सीमित रखने की कोशिश कर रही हैं। आईडीसी की उपासना जोशी के मुताबिक, इस साल भारी छूट की संभावना कम है।

उद्योग अधिकारियों और मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां त्योहारी मांग बचाने के लिए नवंबर अंत तक आगे की बढ़ोतरी टाल सकती हैं।

जिन विक्रेताओं ने पुरानी कीमत पर माल खरीदा है, वे चुनिंदा ऑफर दे सकते हैं। बैंक कार्ड ऑफर, कैशबैक, नो-कॉस्ट ईएमआई और पुराने उपकरण पर अतिरिक्त एक्सचेंज बोनस प्रमुख रणनीति होगी।

बोझ बढ़ा

मोबाइल की कीमत 10.4% बढ़ी, लैपटॉप भी तेजी से महंगे

आईडीसी के मुताबिक, जनवरी-मार्च 2026 में भारत में स्मार्टफोन का औसत बिक्री मूल्य सालाना 10.4% बढ़कर रिकॉर्ड 302 डॉलर, यानी करीब 27,000 पहुंच गया। यूनिट शिपमेंट 4.1% घटने के बावजूद बाजार का कुल मूल्य 5.8% बढ़ा। इससे पता चलता है कि महंगे मॉडलों ने बाजार को सहारा दिया।

सैमसंग-शाओमी समेत कई कंपनियां पहले ही कई दौर की कीमत बढ़ोतरी कर चुकी हैं। सस्ते फोन पर सबसे ज्यादा मार पड़ने की आशंका है।

लैपटॉप के लिए बाजार-व्यापी औसत उपलब्ध नहीं। एसर इंडिया का कहना है कि 2026 में कीमतें करीब 40% तक बढ़ी हैं। वहीं, मार्च में आईडीसी ने बताया था कि तब तक लैपटॉप 10-12% महंगे हो चुके और पूरे साल में बढ़ोतरी 35% तक पहुंच सकती है।

विस्तार • वैश्विक निवेशकों ने 5.5% हिस्सेदारी ली

अदाणी ग्रुप का एयरपोर्ट सिटी पर दांव, ₹9,512 करोड़ जुटाए

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

अदाणी समूह एयरपोर्ट के आसपास नए बिजनेस हब विकसित करने के लिए करीब एक अरब डॉलर (करीब 9,512 करोड़ रुपए) जुटाएगा। ब्लैकरॉक, टेमासेक, अल्फा वेव ग्लोबल और प्रेमजी इन्वेस्ट यह रकम अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स (एएएचएल) में लगाएंगे। इसके बदले इन्हें कंपनी में 5.54% हिस्सेदारी मिलेगी।

सौदे में एएएचएल का निवेश से पहले का इक्विटी मूल्यांकन 18 अरब डॉलर (करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए) आंका गया। यह निवेश मौजूदा शेयरों की बिक्री के बजाय नए शेयर जारी कर जुटाया जाएगा। इसका इस्तेमाल एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने, टर्मिनल आधुनिक बनाने तथा एयरपोर्ट सिटी और विमानन से इतर कारोबार के विस्तार में होगा। फिलहाल अदाणी एयरपोर्ट्स होल्डिंग्स के पास मुंबई सहित 8 एयरपोर्ट हैं। कंपनी के मुताबिक, इनसे देश के 23% हवाई यात्री और 29% एयर कार्गो की आवाजाही होती है।

वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी ने 13,081 करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। नई पूंजी की मदद से कंपनी अपने एयरपोर्ट की संयुक्त क्षमता बढ़ाकर सालाना करीब 20 करोड़ यात्री करना चाहती है। इस खबर से बुधवार को अदाणी समूह के शेयरों में तेजी आई। शुरुआती कारोबार में अदाणी एंटरप्राइजेज 5% से अधिक चढ़कर 3,104 के 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब पहुंच गया। अदाणी पोर्ट्स में करीब 3.22% और अदाणी पावर में लगभग 2.74% तेजी दर्ज की गई।

नई पूंजी से 2.2 करोड़ वर्गफुट विकास की तैयारी, 20 करोड़ यात्रियों की तैयारी

निवेश/कारोबार	आंकड़ा
नई पूंजी	9,825 करोड़
हिस्सेदारी	5.54%
कंपनी मूल्यांकन	₹1.7 लाख करोड़
एयरपोर्ट	8
राजस्व	₹13,081 करोड़
यात्री शेयर	23%
कार्गो शेयर	29%
प्रस्तावित विकास	2.2 करोड़ वर्गफुट
प्रस्तावित क्षमता	20 करोड़ यात्री

भास्कर नॉलेज

एयरपोर्ट सिटी पर दांव क्यों लगा रहा समूह...

2.2 करोड़ वर्गफुट में होटल-दफ्तर, एयरपोर्ट बनेंगे कमाई के नए केंद्र

- अदाणी समूह की योजना मुंबई, नवी मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी एयरपोर्ट के आसपास 655 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट सिटी विकसित करने की है। पहले चरण में 2.2 करोड़ वर्गफुट निर्माण पर 20,000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। इसमें होटल, दफ्तर, दुकानें, रेस्तरां, मनोरंजन और सम्मेलन केंद्र बनाए जाएंगे। 70% प्रस्तावित निवेश मुंबई, नवी मुंबई में होगा।
- यह मॉडल सिंगापुर के चांगी, दुबई, एम्स्टर्डम के शिफोल और सोल के इंचियोन एयरपोर्ट क्षेत्रों से प्रेरित है। इन केंद्रों को एयरपोर्ट, मेट्रो और शहर के दूसरे परिवहन साधनों से जोड़ा जाएगा।
- एयरपोर्ट की विमानन आय यात्री शुल्क, लैंडिंग और पार्किंग जैसी सेवाओं से आती है। एयरपोर्ट सिटी से कंपनी होटल, किराया, रिटेल, खानपान, विज्ञापन, पार्किंग और सम्मेलन जैसी गतिविधियों से कमाई कर सकती है। इससे आय उड़ानों और यात्री शुल्क पर निर्भर नहीं रहती।

बिजनेस ब्रीफ

सेबी ने जेपी मॉर्गन की इकाई से प्रतिबंध हटाया

मुंबई | सेबी ने कॉप्थॉल मॉरीशस और मानसी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकिंग पर लगा व्यापक बाजार प्रतिबंध हटा दिया है। दोनों ने कथित गलत कमाई की राशि जमा कर दी है। जेपी मॉर्गन की इकाई कॉप्थॉल ने 2.96 करोड़ और मानसी ने 71.65 लाख जमा किए। हालांकि, दोनों क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) में भाग नहीं ले सकेंगी।

भारत में एक साथ आएंगे स्कोडा और जेएसडब्ल्यू

मुंबई | स्कोडा ऑटो और जेएसडब्ल्यू ग्रीन मोबिलिटी ने भारत में संयुक्त उद्यम की संभावना तलाशने के लिए गैर-बाध्यकारी समझौता किया है। प्रस्तावित कंपनी पेट्रोल-डीजल, इलेक्ट्रिक, प्लग-इन हाइब्रिड और हाइब्रिड यात्री वाहन विकसित कर भारत और विदेशी बाजारों में बेचेगी। दोनों कंपनियों का संयुक्त नियंत्रण होगा।

ICICI प्रू. चार बैंकों में बढ़ा सकेगी हिस्सेदारी

नई दिल्ली| रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को चार बैंकों में 9.95% तक हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इन बैंकों में कोटक महिंद्रा, सीएसबी, डीसीबी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। यह होल्डिंग 1 साल में करनी होगी। तय अवधि में प्रक्रिया पूरी न होने पर मिली मंजूरी अपने आप रद्द हो जाएगी

ई20 के आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल की तैयारी

नई दिल्ली| सरकार फ्लेक्सी-फ्यूल वाहनों के जरिए ई20 से आगे एथेनॉल ब्लेंडिंग की इजाजत देने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर के अनुसार ई20 प्रोग्राम सफल रहा है। ऑटो कंपनियां फ्लेक्सी-फ्यूल वाहन उतारने जा रही हैं। महंगे क्रूड के बीच देश में एथेनॉल उत्पादन क्षमता जरूरत से अधिक हो चुकी है।

भास्कर एनालिसिस निफ्टी तीन महीने के निचले स्तर, अब 23,300 का स्तर अहम

सेंसेक्स 813 अंक टूटा, आईटी इंडेक्स 3% गिरा

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

4,588 शेयरों में ट्रेडिंग हुई... 39% में बढ़त, 56% में गिरावट

1,792	2600	196	40
में बढ़त	में गिरावट	शेयर स्थिर	लोअर सर्किट

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, 100 डॉलर के पार पहुंचे कच्चे तेल और आईटी शेयरों में भारी बिकवाली से बुधवार को शेयर बाजार तीन महीने के निचले स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 813 अंक यानी 1.08% गिरकर 74,764 पर बंद हुआ। निफ्टी 204 अंक टूटकर 23,432 पर आ गया। बाजार ने दोपहर में संभलने का प्रयास किया, लेकिन तेजी टिक नहीं सकी और दोनों बेंचमार्क इंडेक्स दिन के निचले स्तर पर बंद हुए।

ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने से भारत के आयात बिल, रुपए और महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार दूसरे दिन कमजोर होकर 28 पैसे नीचे 95.10 पर बंद हुआ। महंगा तेल कंपनियों की लागत बढ़ाने के साथ ब्याज दर में कटौती की गुंजाइश सीमित कर सकता है। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च प्रमुख विनोद नायर के मुताबिक, बाजार अब पश्चिम एशिया में लंबे संघर्ष की आशंका को कीमतों में शामिल कर रहा है। महंगी ऊर्जा आर्थिक वृद्धि और महंगाई, दोनों के लिए जोखिम है। बॉन्ड यील्ड और मुद्राओं में उतार-चढ़ाव से निवेशक सतर्क रह सकते हैं। एसबीआई सिक्युरिटीज के सुदीप शाह के मुताबिक, निफ्टी के लिए 23,330-23,300 का रेंज अहम सहारा है। इसके नीचे टिकने पर बिकवाली का जोखिम और बढ़ सकता है। इसके नीचे गिरावट 23,170-23,150 तक बढ़ सकती है। ऊपर 23,620-23,640 पर तत्काल रुकावट है। इसे पार करने पर इंडेक्स 23,800 की ओर लौट सकता है।

लॉर्ज कैप की तुलना में मिड और स्मॉलकैप इंडेक्स में कम गिरावट

- बड़ी कंपनियों के मुकाबले मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट कुछ कम रही। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में लगभग 0.5% गिरावट।
- निफ्टी आईटी इंडेक्स 3.24%, रियल्टी इंडेक्स 2% गिरा। इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो में सबसे ज्यादा दबाव रहा।
- मीडिया, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक इंडेक्स करीब 1% टूटे। मेटल 1.8% और एनर्जी इंडेक्स 0.6% बढ़े।
- अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स, टाटा स्टील और कोल इंडिया में तेजी रही। 180 से ज्यादा शेयर 52 सप्ताह के उच्च स्तर पर पहुंचे।

दबाव

आईटी इंडेक्स 6 दिन में 10% टूटा, कॉफोर्ज में इस्तीफे से बढ़ी चिंता

निफ्टी आईटी लगातार छठे सत्र गिरा है और इस दौरान 10% से ज्यादा टूट चुका है। बुधवार को पूरे सेक्टर पर अमेरिकी वीसा शुल्क, ऊंची ब्याज दरों और कमजोर वैश्विक टेक खर्च की चिंता हावी रही। इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा में 3 से 5% तक गिरावट आई।

- कॉफोर्ज का शेयर 5% गिरा। चेयरमैन ओपी भट्ट ने आंतरिक ऑडिट में बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया पर सवाल उठने के बाद इस्तीफा दे दिया। बोर्ड की मूल्यांकन रिपोर्ट व भट्ट के प्रदर्शन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पूरी तरह साझा नहीं की गई।
- इस्तीफा देते हुए भट्ट ने कहा कि उन्होंने कंपनी के हित में काम किया। कंपनी ने विवेक शर्मा को 31 जनवरी 2027 तक अंतरिम चेयरमैन नियुक्त किया है।

मेगा इश्यू • आईपीओ का प्राइस बैंड 1,700 से 1,785 रुपए संभव

NSE IPO: अनलिस्टेड शेयरों की मांग में उछाल, लेकिन 23% तक घाटे का अंदेशा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

एनएसई का आईपीओ अनलिस्टेड मार्केट के भाव से नीचे तय हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसका संभावित प्राइस बैंड 1,700 से 1,785 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। यह बीते एक साल में अनलिस्टेड बाजार के 1,950 से 2,200 रुपए के ट्रेडिंग स्तर से 8.5% से 22.7% तक कम है। इससे ऊंचे भाव पर शेयर खरीदने वाले निवेशकों को लगभग 23% घाटा झेलना पड़ सकता है।

जोखिमः इश्यू से पहले मांग 40% तक बढ़ी

- अनलिस्टेड शेयर डीलरों के अनुसार, आईपीओ की खबर आने के बाद से खरीदारी की मांग में 30% से 40% तक का उछाल देखा गया है। यह इश्यू 18 सितंबर को खुलकर 25 सितंबर को लिस्ट हो सकता है।
- अनलिस्टेड मार्केट में 1,975 रुपए के भाव पर एक्सचेंज का वैल्युएशन 4.9 लाख करोड़ रुपए बैठता है। यह 2026 का सबसे बड़ा आईपीओ होगा।
- देश के इस सबसे बड़े एक्सचेंज का डेरिवेटिव्स मार्केट में दबदबा है। मर्चेंट बैंकर नए निवेशकों के लिए लिस्टिंग पर मार्जिन छोड़ते हैं। इस वजह से अनलिस्टेड मार्केट के निवेशकों को नुकसान का खतरा है।

धोखेबाज-भगोड़ा कहने पर भी उठाया सवाल

ब्रिटेन छोड़ने पर कोर्ट की रोक है तो भारत कैसे लौटूं: माल्या

बिजनेस संवाददाता | लंदन

किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या ने भगोड़ा कहे जाने पर पलटवार किया है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे 1992 से यूके के स्थायी निवासी हैं। फिलहाल ब्रिटिश अदालतों के आदेश के कारण उनके देश छोड़ने पर कानूनी रोक लगी हुई है।

माल्या 2016 में भारत से बाहर चले गए थे, जब एजेंसियां बैंक लोन मामलों की जांच कर रही थीं। बाद में 2018 के कानून के तहत उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया। हालांकि माल्या ने खुद को धोखेबाज और भगोड़ा कहे जाने पर सवाल उठाए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट में ईडी के हलफनामे का हवाला देते हुए उन्होंने 2021 में 14,131.60 करोड़ रुपए वसूले जाने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि संपत्तियां जब्त होने से वे भुगतान नहीं कर सके। लेकिन बाद में ईडी ने माल्या के जब्त फंड में से कर्मचारियों को 350 करोड़ रुपए जारी किए। माल्या के मुताबिक यूके की अदालत द्वारा देश छोड़ने और ट्रेवल डॉक्यूमेंट रखने पर रोक लगाए जाने के कारण वे भारत लौटने की तारीख तय नहीं कर सकते।

130 हॉर्सपावर की एस्टन मार्टिन की पहली बाइक, सिर्फ 300 ही बनेंगी, कीमत का खुलासा नहीं किया

ठोस टाइटेनियम से बने फ्रेम का वजन महज 5 किलो... बाइक में 1,083 सीसी का वाटर-कूल्ड वी-ट्विन इंजन है, जो 130 बीएचपी ताकत और 110 न्यूटन मीटर टॉर्क पैदा करता है। कुल वजन 190 किलो है। इसमें ठोस टाइटेनियम ब्लॉक से बना फ्रेम 5 किलो का है।

पेरिस | लग्जरी कार निर्माता एस्टन मार्टिन ने ब्रफ सुपीरियर के साथ मिलकर अपनी पहली बाइक एएमबी 002 रोडस्टर से पर्दा उठा दिया है। यह केवल रेसिंग बाइक एएमबी 001 का बदला हुआ रूप नहीं है, बल्कि सामान्य सड़कों पर चलाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस सुपर बाइक की सिर्फ 300 यूनिट बनेंगी और डिलीवरी 2027 की तीसरी तिमाही में शुरू होगी।

अगस्त में सोना 13% चढ़ा, ये तीसरी बड़ी मासिक तेजी

भास्कर न्यूज़ | मुंबई

अगस्त 2026 में सोना 13% चढ़कर 4,563 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (डब्ल्यूजीसी) के मुताबिक, यह बीते 25 साल का तीसरा सबसे बड़ा मासिक रिटर्न है। तेजी की प्रमुख वजह गोल्ड ईटीएफ में व्यापक निवेश और डॉलर की कमजोरी रही। यूरोपीय ईटीएफ में 7.9 अरब डॉलर, उत्तरी अमेरिका में 7.8 अरब डॉलर और एशिया में 2 अरब डॉलर का निवेश आया।

कॉमेक्स में नेट मैनेज्ड मनी पोजिशन भी 13 अरब डॉलर बढ़ी। अब निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सितंबर के ब्याज दर फैसले पर है। बुधवार को एमसीएक्स पर अक्टूबर का सोना 0.7% बढ़कर 1,53,644 प्रति 10 ग्राम रहा। निकट अवधि में भाव 1,51,000 रुपए से 1,55,500 रुपए के बीच रह सकता है।

भारत में अवैध रूप से कारोबार कर रहे थे

मनी लॉन्ड्रिंग पर सख्ती, 15 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बंद होंगे

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) सर्विस प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी किया है। वीडीए सर्विस प्रोवाइडर क्रिप्टो और एनएफटी जैसी वर्चुअल एसेट्स के लेनदेन की सुविधा देने वाले प्लेटफॉर्म हैं। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का पालन न करने पर हुई है। जांच में वीक्स इंटरनेशनल एक्सचेंज, बीएलएफ ग्लोबल और बिटयूनिक्स एलएलसी जैसी संस्थाएं भारत में अवैध रूप से कारोबार करती पाई गईं। इसलिए आईटी एक्ट के तहत इनके एप और यूआरएल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में मार्च 2023 से ही सभी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के दायरे में हैं। इसके तहत देशी-विदेशी कंपनियों के लिए एफआईयू में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इन्हें हर लेनदेन का रिकॉर्ड रखना और रिपोर्ट देना होता है। भारत में दफ्तर न होने पर भी व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर यह कानून लागू होगा। सरकार ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टो और एनएफटी सरकारी नियमों के दायरे में नहीं आते, इसलिए नुकसान पर निवेशकों को कानूनी राहत नहीं मिलेगी।

बिजनेस एंकर 1,200 सीनियर एक्जीक्यूटिव के सर्वे में खुलासा, 94% लीडर बदलाव के लिए तैयार

63% ढूंढ रहे नई नौकरी, 41% बोले- 1 साल टिकना भी मुश्किल

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

देश में कॉरपोरेट जगत के 94% सीनियर एग्जीक्यूटिव्स नई नौकरी तलाशने और करिअर में बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल, भारत में सीनियर लीडरशिप का परिदृश्य बहुत तेजी से बदल रहा है। एग्जीक्यूटिव्स अब अपने करिअर में तेज प्रगति, बड़ी जिम्मेदारियां और अपनी छाप छोड़ने के अवसर चाहते हैं। दूसरी ओर, कंपनियों पर भी इन शीर्ष अधिकारियों को अपने साथ जोड़े रखने का भारी दबाव बना हुआ है। यह अहम खुलासा एग्जीक्यूटिव सर्च कंपनी पेज एग्जीक्यूटिव इंडिया की 'एग्जीक्यूटिव कम्पनसेशन एंड टैलेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट' में हुआ है। देश के 1,200 से अधिक सी-लेवल अधिकारियों और शीर्ष लीडर्स पर किए गए इस अध्ययन के मुताबिक, 63% अफसर तो पूरे जोर-शोर से नई भूमिका ढूंढ रहे हैं। वहीं 41% अफसरों का स्पष्ट मानना है कि वे एक साल से ज्यादा अपने मौजूदा पद पर नहीं टिकेंगे।

पेज एग्जीक्यूटिव इंडिया के मैनेजिंग पार्टनर जॉन गोल्डस्टीन बताते हैं कि भारतीय बाजार में योग्य टैलेंट की कोई कमी नहीं है। असली चुनौती यह है कि कंपनियां किस रफ्तार से इस टैलेंट को विकसित करती और संभालती हैं। आज के लीडर्स तेज प्रगति, बड़ा प्रभाव और अपने प्रदर्शन तथा पुरस्कार के बीच स्पष्ट तालमेल देखना चाहते हैं। दूसरी तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) भी अब बड़े पदों के कामकाज का जरूरी हिस्सा बन चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, 72% अफसरों का मानना है कि एआई के इस्तेमाल से उनके काम का स्तर काफी सुधरा है। माइकल पेज इंडिया और सिंगापुर के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर निलय खंडेलवाल के अनुसार, एआई पर चर्चा अब इसे अपनाने से आगे बढ़कर जवाबदेही पर आ चुकी है। जैसे-जैसे जिम्मेदारियां विकसित हो रही हैं, सबसे बड़ी प्राथमिकता ऐसे टैलेंट को खोजने, विकसित करने और रोके रखने की होगी जो एआई के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सके।

हालांकि, अच्छी सैलरी देकर सीनियर लीडरशिप को रोकना अब कंपनियों के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अफसर पदोन्नति और आगे बढ़ने के अवसरों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसके साथ ही, देश में अब स्किल्स के आधार पर होने वाली भर्तियों का चलन तेजी से बढ़ रहा है।

सैलरी: 87% अधिकारियों के लिए वेतन ही संतुष्टि का प्रमुख आधार

- सैलरी के मामले में 65% एग्जीक्यूटिव्स अपने मौजूदा पैकेज से संतुष्ट हैं। वहीं 87% अधिकारियों का मानना है कि जॉब सैटिस्फेक्शन के लिए पैसा ही सबसे बड़ा पैमाना है। हालांकि केवल बेहतर सैलरी देकर अफसरों को लंबे समय तक रोकना अब किसी कंपनी के लिए मुमकिन नहीं रह गया है।
- 75% एग्जीक्यूटिव्स अपने रोजमर्रा के कामकाज में एआई का नियमित इस्तेमाल कर रहे हैं। इतने ही अधिकारियों ने इससे अपनी काम करने की क्षमता में भारी बढ़ोतरी दर्ज की है। उन्होंने कहा कि एआई के इस्तेमाल से उनके काम का स्तर काफी सुधरा है।

भास्कर एक्सप्लेनर सिंगापुर सरकार ने खारिज की आशंका

एअर इंडिया को 14,262 करोड़ की नई पूंजी चाहिए, सिंगापुर में सियासी विवाद क्यों छिड़ा?

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

रिकॉर्ड घाटे से जूझ रही एअर इंडिया ने अपने प्रवर्तकों टाटा संस और सिंगापुर एयरलाइंस से करीब 1.5 अरब डॉलर (करीब 14,262 करोड़) की अतिरिक्त पूंजी मांगी है। इसमें से टाटा संस को 10,682 करोड़ और सिंगापुर एयरलाइंस को 3,580 करोड़ देने हैं। सिंगापुर एयरलाइंस की हिस्सेदारी में सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक मेजॉरिटी शेयरधारक है। इसी कारण यह कारोबारी जरूरत सिंगापुर में सार्वजनिक धन और जवाबदेही से जुड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई है। इसे समझते हैं...

1. एअर इंडिया को फंड क्यों चाहिए?
एयरलाइन को वित्त वर्ष में 2.33 अरब डॉलर (करीब 22,154 करोड़) का घाटा हुआ है। बेड़े के विस्तार और सेवाओं के सुधार के लिए यह पैसा चाहिए। टाटा ग्रुप ने 112.35 करोड़ डॉलर (करीब 10,682 करोड़) मंजूर कर दिए हैं।

3. सिंगापुर में विवाद क्यों हुआ?
सिंगापुर एयरलाइंस में सरकारी कंपनी टेमासेक मुख्य शेयरधारक है। वहां के विपक्ष को आशंका है कि राष्ट्रीय खजाने का पैसा घाटे में चल रही भारतीय एयरलाइन को सहारा देने में इस्तेमाल हो सकता है।

4. सिंगापुर सरकार की क्या सफाई है?
सरकार ने विपक्ष की आशंका खारिज करते हुए कहा है कि निवेश का निर्णय सिंगापुर एयरलाइंस का बोर्ड करेगा और इसके लिए नागरिकों या शेयरधारकों से नई पूंजी नहीं मांगी गई है। टेमासेक या सरकार सीधे फंड नहीं दे रही है। एयरलाइन अपने आंतरिक स्रोतों से ही इस निवेश का पैसा जुटाएगी।

सिंगापुर एयरलाइन का क्या प्लान है?
सिंगापुर एयरलाइंस ने निवेश को अपनी दीर्घकालिक 'मल्टी-हब' रणनीति का हिस्सा बताया है। कंपनी भारत को अपने प्रमुख हब के रूप में देख रही है। घाटे से उबरने में 10 साल लग सकते हैं, फिर भी वह लंबे समय तक भारतीय बाजार का हिस्सा बने रहना चाहती है। लेकिन अब फंड देने से पहले मैनेजमेंट में ज्यादा कंट्रोल की शर्त रख रही है।